सिंचित राजस्थान

राजस्थान सरकार की मरू क्षेत्र के लिए जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना

इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जीर्णोद्धार, 10 जिलों को होगा लाभ

—जयपुर—

इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण के नहरी तंत्र के जीर्णोद्धार के लिए न्यू डवलपमेंट बैंक द्वारा जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना को वित्त पोषित किया गया है। इसका लाभ श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर, झुंझुनूं, सीकर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों को मिलेगा। परियोजना 13 फरवरी, 2018 को प्रारम्भ हुई थी, जिसमें अब तक 281 कार्य पूर्ण हुए हैं। वर्तमान में 120 कार्य प्रगतिरत है। इन्दिरा गांधी फीडर, इन्दिरा गांधी मुख्य नहर एवं इसके नहरी तंत्र की कुल 2678.22 किमी. लंबाई में री-लाइनिंग का कार्य प्रस्तावित है। अब तक 1549.50 किमी. री-लाइनिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है। परियोजना की कुल अनुमानित लागत राशि 3291.63 करोड़ रुपए है। जून, 2023 तक 1806.77 करोड़ रुपए व्यय हो चुका है। परियोजना 55 प्रतिशत पूर्ण हो चुकी है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में परियोजना के लिए 784.89 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है। जून, 2023 तक 156.88 करोड़ का व्यय किया गया है। परियोजना पूर्ण होने की तिथि 12 फरवरी, 2025 है।

पंजाब को राशि हस्तांतरित कर चुका है राजस्थान

इंदिरा गांधी फीडर (पंजाब भाग) में 97 किमी लंबाई में री-लाइनिंग कार्य करवाए जाने हैं, जिसके विरुद्ध अब तक 81.70 किमी लंबाई में री-लाइनिंग का काम पूरा हो चुका है। इन कार्यों पर जून, 2023 तक राशि 1052.25 करोड़ रुपए व्यय हो चुके हैं। राजस्थान द्वारा इन कार्यों पर अपनी हिस्सा राशि के तहत अब तक 659.15 करोड़ रुपएपंजाब को हस्तांतरित किए जा चुके हैं।

सर हिन्द फीडर पर भी चल रहा है काम

सरहिन्द फीडर में कुल 100 किमी लंबाई में री-लाइनिंग कार्य किए जाने हैं। अब तक 84 किमी लंबाई में री-लाइनिंग कार्य करवाए जा चुके हैं। इन कार्यों पर जून, 2023 तक 506.15 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं। राजस्थान द्वारा इन कार्यों पर अपनी हिस्सा राशि के विरुद्ध अब तक 125.83 करोड़ रुपए पंजाब को हस्तांतरित किए जा चुके हैं। पंजाब द्वारा यह काम जून, 2024 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

27 जिलों में 137 सिंचाई परियोजनाओं का पुनर्वास

राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना के तहत 27 जिलों में 137 सिंचाई परियोजनाओं के पुनर्वास एवं जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है। इससे 4.70 लाख हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र के काश्तकार लाभान्वित होंगे। परियोजना पर वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 300 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है। जून, 2023 तक 11.48 करोड़ व्यय हो चुके हैं।

14 हजार करोड़ से होगा सिंचाई तंत्र का विकास

राजस्थान इरिगेशन रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम से किसान होंगे आर्थिक उन्नत

—जयपुर—

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा 2022-23 में राज्य में सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित कर कृषकों के आर्थिक उत्थान के लिए राजस्थान इरिगेशन रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। इसके अन्तर्गत आगामी वर्षों में लगभग 14 हजार 860 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। एनिकट में संग्रहित जल को सौर ऊर्जा आधारित सूक्ष्म सिंचाई पद्धति स्थापित कर स्थानीय काश्तकारों को सिंचाई एवं पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी।

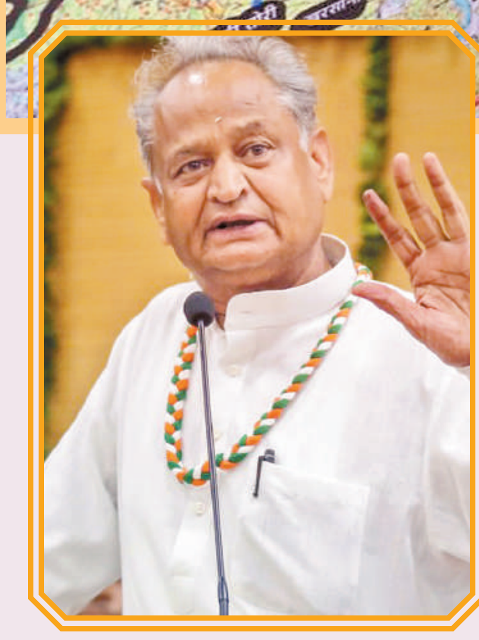

2.5 हजार करोड़ की अपर हाई लेवल केनाल परियोजना

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2022-23 के बजट में 2500 करोड़ रुपए की अपर हाई लेवल केनाल परियोजना की घोषणा की थी। इस परियोजना से बांसवाड़ा जिले के तीन विधानसभा क्षेत्रों बांसवाड़ा, बागीदौरा एवं कुशलगढ़ तथा 6 तहसीलों यथा बांसवाड़ा बागीदौरा, गांगडतलाई, आनंदपुरी, कुशलगढ़ और सज्जनगढ़ के कुल 338 गांवों के 42 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही, 105 किलोमीटर लम्बी मुख्य नहर के एलाइनमेंट में आ रहे तालाबों में पेयजल आपूर्ति संभव होगी। परियोजना के कार्यादेश 12 मई 2023 को जारी कर दिए गए।

पीपलखूंट हाई लेवल केनाल परियोजना

माही बांध से पीपलखूंट हाई लेवल केनाल निकालकर पीपलखूंट तहसील के 5000 हैक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही माही बांध से 3.72 टीएमसी जल जाखम बांध में परिवर्तित किया जाना प्रस्तावित है। इस हाई लेवल केनाल द्वारा माही बांध से जल अपवर्तन कर जाखम परियोजना का 28 हजार 320 हैक्टेयर क्षेत्र भी माही जल पर परिवर्तित कर जाखम जल से प्रतापगढ, उदयपुर, राजसमंद एवं चित्तौड़गढ़ जिले में पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई जा सकेगी।

परियोजना में मुख्य नहर भी लोहे के पाइप में निर्मित कर डिग्गियों में जल डाल कर पम्प व पाइपों द्वारा कमाण्ड क्षेत्र के प्रत्येक सवा से डेढ़ हैक्टेयर क्षेत्र में नक्का बनाकर फव्वारा पद्धति से सिंचाई की जाएगी। इस प्रणाली से सिंचाई जल का कुशलतम उपयोग होगा एवं पानी की छीजत न्यूनतम होगी। 2 हजार करोड़ रुपए की इस परियोजना की प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं।

सेई एवं साबरमती बांध

पाली एवं सिरोही जिले में पेयजल की भारी कमी को देखते हुए मुख्यमंत्री द्वारा बजट 2022-23 में पाली जिला एवं सिरोही जिला (शिवगंज) में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने हेतु उदयपुर की कोटडा तहसील में सेई एवं साबरमती नदी पर बनाए जाने वाले जलाशयों का 1,800 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण करवाने की घोषणा की गई। इन जलाशयों से जवाई बांध तक पानी लाने पर 1,200 करोड़ रुपए व्यय किये जाएंगे। परियोजना के पूर्ण होने पर पाली जिले के 9 कस्बे एवं 560 गांव तथा सिरोही जिले की शिवगंज तहसील के अन्तर्गत शिवगंज कस्बा एवं 178 गांवों की पेयजल सुविधा सुदृढ़ हो सकेगी। राज्य सरकार द्वारा इसके लिए 2,554 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। परियोजना में दो बांध एवं दो सुरंग के कार्यों के लिए 1255.90 करोड़ रुपए के कार्यादेश जारी किए गए हैं।

सालगांव बांध

माउण्ट आबू शहरी पेयजल योजना के अंतर्गत सालगांव-सिरोही में बांध निर्माण सहित अन्य कार्य करवाए जाने की मुख्यमंत्री द्वारा बजट 2022-23 में घोषणा की गई। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के डिपोजिट वर्क के रूप में इसकी 250.50 करोड़ रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। इसमें 155.56 मिलियन घन फीट भराव क्षमता का सालगांव बांध स्थानीय सालगांव एवं गंभीरी नाला के संगम पर निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। 111 करोड़ रुपए की परियोजना से माउंट आबू पवर्तीय स्थल की लगभग 45 हजार आबादी लाभान्वित होगी।

189 बांधों पर चल रहा है तेजी से काम

बड़े बांधों के जीर्णोद्धार से रुकेगा जल रिसाव

—जयपुर—

बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना (ड्रिप) के कार्य (डीआरआईपी) के माध्यम से राज्य के बड़े बांधों का जीर्णोद्धार किया जाएगा तथा जल रिसाव रोका जाएगा, जिससे बांधों की जलभराव क्षमता बढ़ेगी और किसानों को सिंचाई तथा आम जन को पीने के लिए अधिक जल उपलब्ध होगा। आधुनिक उपकरणों के माध्यम से बांधों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। जिससे वर्षाकालीन / बाढ़ बचाव संबंधी आंकड़े तत्काल उपलब्ध होंगे। डीआरआईपी द्वितीय और तृतीय के तहत 189 बांधों को लिया गया है। बजट घोषणा वर्ष 2020-21 में 18 एवं वर्ष 2021-22 में 18 बांधों के जीर्णोद्धार करने की घोषणा की गई है। केन्द्रीय जल आयोग / वर्ल्ड बैंक को कुल 35 बांधों की पीएसटी भेजी जा चुकी है, जिसकी अनुमानित लागत 660.92 करोड़ रुपए है तथा केन्द्रीय जल आयोग / वर्ल्ड बैंक द्वारा 12 बांधों के जीर्णोद्धार के लिए 404.14 करोड़ की स्वीकृति जारी हो चुकी है। केन्द्रीय जल आयोग / वर्ल्ड बैंक के स्तर पर 22 बांधों के जीर्णोद्धार के लिए 251.93 करोड़ तथा अन्य स्तर पर 2 बांधों के जीर्णोद्धार लिए 37.71 करोड़ रुपए की स्वीकृति लंबित है। परियोजना पर वर्ष 2023-24 के लिए 209.24 करोड़ रुपए का प्रावधान स्वीकृत है, जिसके विरुद्ध जुलाई, 2023 तक 10.31 करोड़ व्यय हो चुके हैं।

कुओं में आया फिर से पानी

—जयपुर—

यह सच है कि संपूर्ण भारत में कुओं का जलस्तर तेजी से नीचे गिर रहा है। ऐसे में राजस्थान सरकार नए कुएं खुदवाने के साथ ही पुराने कुओं की उपयोगिता बनाए रखना चाहती है। राज्य में सरकारी खर्चे पर एक लाख 25 हजार 428 कुओं का उर्जीकरण कराया गया। इन कुओं में फिर से पानी आ गया है और अब इनकी सहायता से खेती की जा रही है। उर्जीकृत किए गए कुओं में 3149 कृषि कुएं जनजातीय इलाके के थे। चूंकि राजस्थान में अब भी जनजातीय इलाके में उतना विकास नहीं हो पाया है, जितने की जरूरत है। यही वजह है कि इन इलाकों को विशेष तवज्जो दी गई और कुओं को उर्जीकृत कराने के साथ ही 1832 जनजातीय कृषकों के कुओं को ब्लास्टिंग से गहरा कराया गया। इससे किसान फिर से खेती में जुट पाए।

8 वृहद परियोजनाएं, 5 मध्यम परियोजनाएं तथा 41 लघु सिंचाई परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर

किसानों के लिए मील का पत्थर साबित होंगी सिंचाई की परियोजनाएं

—जयपुर—

राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप जल संसाधन विभाग सिंचाई और पेयजल आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर लगातार परियोजनाओं पर तेजी से काम कर रहा है। ताकि आने वाले समय में सिंचाई के लिए पानी की कोई कमी नहीं रहे। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में किए गए महत्त्वपूर्ण कार्यों की वजह से सिंचाई और पेयजल आपूर्ति में सुधार आया है। सरकार जिन परियोजनाओं पर काम कर रही है, उनके पूरा होने के बाद पानी की कोई कमी नहीं रहेगी।

- **नर्मदा** नहर परियोजना परियोजना में 1793 किमी लंबाई में वितरिकाओं एवं उप-वितरिकाओं का काम हो चुका है। 2.46 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अभी तक 3242.04 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं।
- **परवन** वृहद् बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना कोटा, बारां और झालावाड़ को फायदा मिलेगा। परियाजना के पहले चरण में 1 लाख 31 हजार 400 हैक्टेयर और द्वितीय चरण में 70 हजार हैक्टेयर भूमि पर सिंचाई क्षमता का सृजन प्रस्तावित है।
- **धौलपुर** लिफ्ट सिंचाई एवं पेयजल परियोजना पर 834 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस पैसे से चम्बल नदी से 6.54 क्यूमेक्स पानी प्रतिवर्ष माह अक्टूबर से मार्च तक लिफ्ट कर धौलपुर जिले के 256 गांवों के 39 हजार 980 हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
- **ईसरदा** पेयजल आपूर्ति परियोजना बीसलपुर की डाउन स्ट्रीम में ग्राम बनैठा तहसील उनियारा, टोंक के पास बनास नदी पर बनाई जा रही है। 615 करोड़ रुपए की योजना से दौसा जिले के 1079 गांव एवं 5 शहर तथा सवाई माधोपुर जिले के 177 गांव एवं एक शहर को पेयजल आपूर्ति प्रस्तावित है।
- **जल** संसाधन विभाग द्वारा कुल 5 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर कार्य किया गया। इस पर करीब 674.82 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं।

पानी की बर्बादी नहीं होगी

वित्तीय वर्ष 2023-24 में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के अतिरिक्त) पर 5399.23 करोड़ का वित्तीय प्रावधान व 69798 हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। जून, 2023 तक 705.45 करोड़ रुपए व्यय हो चुके हैं। दस हजार 97 हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित की गई है। वर्ष 2023-24 में 8 वृहद परियोजना, 5 मध्यम परियोजनाएं तथा 41 लघु सिंचाई परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है।

जल संसाधन विभाग द्वारा प्रसारित

सड़क- सुविधा राजस्थान

राजस्थान में मजबूत हुआ सड़क तंत्र 65 हजार किमी सड़कों का हुआ विकास

73 हजार किमी सड़कों के लिए 45 हजार करोड़ की स्वीकृतियां की जारी

—जयपुर—

राजस्थान सरकार लगातार प्रदेश में उत्कृष्ट आधारभूत ढांचा तैयार करने का काम कर रही है। पिछले चार साल छह महीने में 32 हजार 384 करोड़ रुपए की लागत से 65 हजार किलोमीटर सड़कों का विकास हुआ है।

साथ ही 73 हजार किलोमीटर सड़कों के निर्माण के लिए 45 हजार करोड़ रुपए की स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं। हाल ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3377.55 करोड़ रुपए की लागत से 53 सड़कों, आरओबी और पुलों का शिलान्यास और लोकार्पण किया।

राजस्थान देश में मजबूत सड़क तंत्र के अग्रणी राज्यों में हुआ शामिल

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मानना है कि किसी भी प्रदेश और गांवों के विकास में सड़कों की भूमिका अहम होती है। सड़कों के विकास के चलते आज राजस्थान मजबूत सड़क तंत्र के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। हाल ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को विभिन्न जिलों में सड़क विकास कार्यों की सौगात दी। अजमेर जिले में 13.93 करोड़ रुपए की लागत से 2 सड़क विकास कार्य का, अलवर जिले में 7.25 करोड़ की लागत से 1 सड़क विकास कार्य का लोकार्पण किया गया है। इसके अलावा बांसवाड़ा जिले में 25.25 करोड़ रुपए की लागत से 3 सड़क एवं पुल निर्माण कार्य का, बारां जिले में 9 करोड़ रुपए की लागत से 1 सड़क विकास कार्य का, भीलवाड़ा जिले में भी 12.40 करोड़ रुपए की लागत से 1 सड़क विकास कार्य का लोकार्पण किया गया है। इसी तरह से बीकानेर जिले में 60 करोड़ रुपए की लागत से 1 सड़क विकास कार्य का, बूंदी जिले में 20 करोड़ रुपए की लागत से 1 सड़क विकास कार्य का, चित्तौड़गढ़ जिले में 9.90 करोड़ रुपए की लागत से 1 सड़क विकास कार्य का, हनुमानगढ़ जिले में 48 करोड़ रुपए की लागत से 2 सड़क विकास कार्य का लोकार्पण मुख्यमंत्री कर चुके हैं। झुंझुनूं जिले में 143.50 करोड़ रुपए की लागत से 7 सड़क विकास कार्य का, प्रतापगढ़ जिले में 34.25 करोड़ रुपए की लागत से 1 सड़क विकास कार्य का, राजसमंद जिले में 8.34 करोड़ की लागत से 1 सड़क विकास कार्य का, सवाई माधोपुर जिले में 32.20 करोड़ रुपए की लागत से 2 सड़क विकास कार्य का लोकार्पण किया गया है। इसी तरह से सीकर जिले में 25.40 करोड़ रुपए की लागत से 2 सड़क विकास कार्य का, श्रीगंगानगर जिले में 32.05 करोड़ रुपए की लागत से 2 सड़क विकास कार्य का और उदयपुर जिले में 58.25 करोड़ रुपए की लागत से 5 सड़क और पुल निर्माण कार्य का लोकार्पण किया जा चुका है। शिलान्यास के कार्यक्रम में अजमेर जिले में 458.34 करोड़ रुपए की लागत से 2 सड़क विकास कार्यों का, बांसवाड़ा जिले में 253.37 करोड़ रुपए की लागत से 1 सड़क विकास कार्य का, बारां जिले में 65.60 करोड़ रुपए की लागत से 2 सड़क एवं पुल निर्माण कार्य का शिलान्यास हो चुका है। भरतपुर जिले में 6 करोड़ रुपए की लागत से 1 सड़क विकास कार्य का, बीकानेर जिले में 586.39 करोड़ रुपए की लागत से 2 सड़क विकास कार्य का शिलान्यास भी हो चुका है। बूंदी जिले में 301.52 करोड़ रुपए की लागत से 4 सड़क एवं पुल निर्माण कार्य का, चूरू जिले में 554.12 करोड़ रुपए की लागत से 2 सड़क विकास कार्य का, झालावाड़ जिले में 27.81 करोड़ रुपए की लागत से 2 सड़क एवं पुल निर्माण कार्य का, सवाईमाधोपुर जिले में 163 करोड़ रुपए की लागत से 2 सड़क विकास कार्य का, सीकर जिले में 421.67 करोड़ रुपए की लागत से 2 सड़क विकास कार्य का शिलान्यास मुख्यमंत्री ने किया है।

नई दिल्ली के लुटियंस जोन में निर्माणाधीन भवन

राजस्थानी कला का बेजोड़ नमूना होगा राजस्थान हाउस

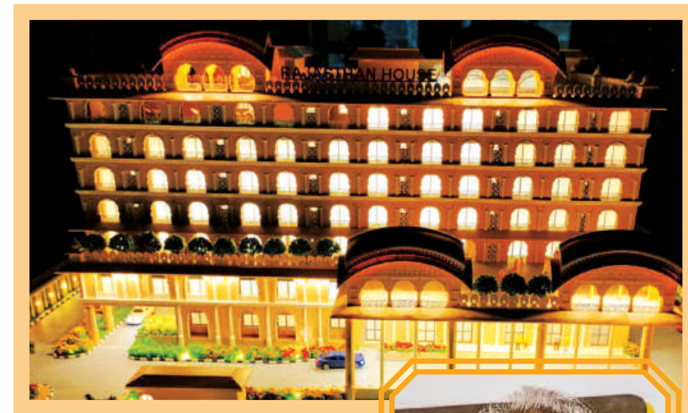

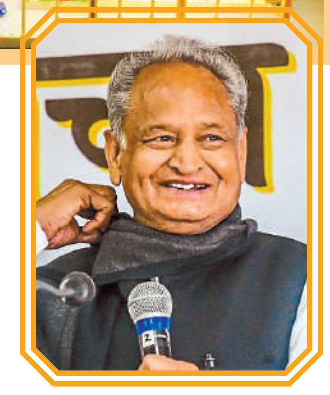

—जयपुर—

नई दिल्ली के 'लुटियंस जोन' में 7050 वर्ग मीटर में राजस्थान हाउस को राज्य सरकार नया रूप दे रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मई, 2023 में इसकी नींव रखी। इस कार्य पर करीब 158.54 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। भवन का काम जून, 2024 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए दिल्ली के संबंधित विभागों से सरकार ने एनओसी भी ले ली है। ग्रीन हाउस बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पर बन रहे इस भवन की उंचाई 26 मीटर होगी। इसमें राजस्थान की कलात्मक वास्तुशिल्प का प्रयोग किया जाएगा। इसमें दो बेसमेंट, भूतल और 6 फ्लोर का प्रावधान रखा गया है। भवन के बेसमेंट में 52 कारों की पार्किंग का भी प्रावधान किया गया है। मुख्य भवन में लॉबी, कैफेटेरिया, वेटिंग एरिया, डाइनिंग एरिया, फव्वारा, हैंगिंग झूमर, एट्रियम आदि का निर्माण किया जाएगा।

धौलपुर सैण्ड स्टोन का होगा प्रयोग

भवन की बाहरी दीवार पर धौलपुर सैण्ड स्टोन क्लेडिंग का कार्य किया जाएगा। प्रथम तल पर कांफ्रेंस हॉल, पुस्तकालय और जिम का भी निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। छत पर टैरेस गार्डन, पार्टी हॉल, योग कक्ष आदि का भी निर्माण होना है। प्रस्तावित गेस्ट हाउस भवन में दो द्वार का प्रावधान किया गया है। भवन का निर्माण आरसीसी संरचना से किया जाएगा।

दूदू-नरैना-सांभर पर आरओबी शुरू

10 लाख से ज्यादा लोगों को हुआ फायदा

----जयपुर----

नरैना के नजदीक 46 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से लेवल क्रॉसिंग नंबर 5 पर दो लेन आरओबी का निर्माण किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 18 दिसंबर, 2020 को आरओबी का वर्चुअली लोकार्पण किया था। इसकी लंबाई 1.5 किमी है। इस आरओबी के निर्माण से दूदू, नरैना, सावरदा, फुलेरा, सांभर, परबतसर तथा रूपनगढ़ सहित आसपास के गांवों तक परिवहन और यातायात में सुगमता आई है। इस आरओबी के बनने से इन क्षेत्रों की 10.60 लाख से ज्यादा आबादी को लाभ हुआ है। परियोजना पूर्ण होने के बाद आरओबी से यातायात शुरू हो गया है। इससे लोगों को बार-बार रेल फाटक बंद होने से लगने वाले जाम से निजात मिली है।

सतर्कता टीमें कर रही निरीक्षण

सड़क गुणवत्ता पर सरकार का फोकस

—जयपुर—

प्रदेश सरकार का निर्माण की गुणवत्ता पर फोकस है। प्रदेश में 33 गुण नियंत्रण प्रयोगशाला संचालित हो रही हैं। सतर्कता दल शिकायतों पर निरीक्षण करते हैं और शिकायत सही होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी करते हैं। 2022-23 में 23 हजार 795 टेस्ट में 667 में कमियां मिलने पर एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) जारी की गई। इसी तरह 2023-24 में 9478 टेस्ट में 66 टेस्ट में कमी मिलने पर सुधार के लिए एटीआर जारी की गई।

उपकरण खरीद शुरू

विभाग की एक केंद्रीय एवं पांच संभागीय प्रयोगशालाओं के एनएबीएल प्रमाणीकरण के लिए उपकरण खरीद हो रही है। बीकानेर संभाग की प्रयोगशाला काम पूरा कर लिया गया है। प्रमाणीकरण के आवेदन के लिए स्वीकृति जारी हो गई है। 27 जिला स्तरीय प्रयोगशालाओं में से 9 प्रयोगशालाओं के बाह्य स्रोत के माध्यम से संचालन एवं एनएबीएल क प्रमाणीकरण की कार्रवाई प्रगतिरत है। शेष 18 जिलास्तरीय प्रयोगशालाओं के लिए कार्रवाई की जा रही है।

7.65 करोड़ रुपए आई लागत

अंडरब्रिज निर्माण से सुगम हुई राह

----जयपुर----

सार्वजनिक निर्माण विभाग के हनुमानगढ़ खण्ड की ओर से भटिण्डा-सूरतगढ़ सेक्शन गांधीनगर, हनुमानगढ़ में रेलवे अंडरब्रिज (आरयूबी) का निर्माण किया गया है। करीब 7.65 करोड़ रुपए की लागत से बने इस आरयूबी का उद्घाटन 13 फरवरी, 2021 को हुआ। आरयूबी के निर्माण से हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लगभग 40 हजार से ज्यादा लोगों को आवागमन में सुविधा मिल रही है। इस क्षेत्र के लोगों को हनुमानगढ़ टाउन और जंक्शन बाजार क्षेत्र के लोगों को जिला न्यायालय, सरकारी कार्यालय व जिला कलेक्ट्रेट जाने के लिए सुगम व सुरक्षित रास्ता उपलब्ध हुआ है।

अभियंताओं का प्रशिक्षण जारी

पीडब्ल्यूडी में 1822 को मिला नौकरी का तोहफा

—जयपुर—

राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग में लगभग 10 वर्षों बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से सहायक अभियन्ता (सिविल) के 319 पदों, कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल / विद्युत) के 879 पदों, कनिष्ठ सहायक के 281 पदों पर बम्पर भर्तियां निकाली गईं। इस भर्ती प्रकिया को शीघ्रता से पूर्ण कर विभाग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्तियां प्रदान की जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा मृतक कर्मचारी के 333 आश्रितों को विभाग में कनिष्ठ सहायक, प्रयोगशाला प्रवर्तक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर अनुकम्पा नियुक्तियां प्रदान की गई हैं। सरकार द्वारा राजस्थान के उत्कृष्ट खिलाड़ियों के कोटे से 10 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को विभाग में कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्तियां प्रदान की गई हैं। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में विभाग में विभिन्न पदों पर कुल 1822 अभ्यर्थियों को नियुक्तियां प्रदान की गई हैं। नवनियुक्त सहायक अभियन्ताओं को आधारभूत पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण एचसीएम रीपा और जेईएन का प्रशिक्षण ईएसटीआई संस्थानों में जारी है।

खाटूश्यामजी के लिए बनेगा कॉरिडोर

----जयपुर----

खाटूश्याम मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। इन्हें सुगम दर्शन कराने के लिए बजट में 32 करोड़ रुपए के कॉरिडोर निर्माण की घोषणा सरकार ने की थी। इसके लिए भूमि अधिग्रहण का काम जल्द होगा। 3.50 किलोमीटर की लंबाई के इस कॉरिडोर निर्माण के साथ ही यहां जन सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी और यहां आने का रास्ता भी सुरक्षित होगा।

1423 ब्लैक स्पॉट किए दुरुस्त

सड़क दुर्घटनाओं को रोकने का प्रयास

—जयपुर—

सड़क निर्माण के साथ-साथ सड़क दुर्घटनाएं रोकने पर भी राजस्थान सरकार विशेष ध्यान दे रही है। प्रदेश के 1 हजार 548 ब्लैक स्पॉट को चिह्नित कर उनमें से 1 हजार 423 को दुरूस्त कर दिया गया है। विशेषज्ञों की ओर से निरीक्षण के साथ ही अब सड़क बनाने वाली कम्पनी की जिम्मेदारी भी 5 साल कर दी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में शाहजहांपुर से अजमेर, बर से बिलाड़ा और सीकर से बीकानेर सड़क मार्गों को सड़क दुर्घटना मुक्त कराने के लिए विशेषज्ञों से ऑडिट कराया है। इन्हें दुर्घटना मुक्त बनाने की पहल की गई है।

2642 किमी नगरीय सड़कों के निर्माण का शिलान्यास

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही 1528 करोड़ रुपए की लागत से राज्य में 2642 किमी लंबी नगरीय सड़कों का निर्माण कार्य करने का शिलान्यास किया है। इसमें 232 नगरीय इकायों में 4 हजार 101 कार्य किए जा रहे हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से बीते चार वर्ष में 64 हजार 946 किमी सड़कों के निर्माण और विकास कार्य करवाए गए हैं। दरअसल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मानना है कि किसी भी प्रदेश की प्रगति में मजबूत सड़क तंत्र का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है।

सेंटर फॉर एक्सीलेंस भी बनेगा

जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के निर्माण के लिए 55 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

बनेंगे भूकम्परोधी भवन

32 बहुमंजिला आवासों के निर्माण कार्य का शिलान्यास

----जयपुर----

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा के अनुरूप अब सार्वजनिक निर्माण विभाग राज्य में वास्तु, ग्रीन बिल्डिंग, भूकंपरोधी आदि भवनों का निर्माण कर रहा है। हाल ही जयपुर स्थित गांधीनगर में प्रथम श्रेणी के 32 बहुमंजिला आवासों के निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया गया। इस 8 मंजिला आवास परिसर का क्षेत्रफल 8 हजार वर्गमीटर होगा, जिसके बेसमेंट में पार्किंग की सुविधा होगी और भूतल पर विभिन्न सुविधाएं प्रस्तावित हैं। प्रथम तल से आठवें तल तक हर तल पर 3500 स्क्वायर फुट के 4 फ्लैट प्रस्तावित हैं। ये फ्लैट शयनकक्ष, ड्रॉइंग रूम, कार्यालय कक्ष और गेस्ट रूम जैसी सुविधाओं से युक्त होंगे। साथ ही कॉमन एरिया में बैंक्वेट हॉल, लाइब्रेरी, जिम, इनडोर खेल क्षेत्र, किड्स प्ले जोन, शिशुगृह, टेनिस कोर्ट आदि सुविधाएं होंगी। सुगम आवाजाही के लिए 4 लिफ्ट भी प्रस्तावित हैं। भवन का निर्माण आरसीसी संरचना से किया जाएगा, जिसमें भूकंपरोधी प्रावधानों को शामिल किया गया है। परिसर में पेड़ भी लगाए जाएंगे।

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रसारित

जल-अनमोल राजस्थान

सर्वाधिक स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए

स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग में राजस्थान को मिला अवॉर्ड

—जयपुर—

उपभोक्ताओं को सही मात्रा और तय गुणवत्ता मानकों के साथ पेयजल आपूर्ति की मॉनिटरिंग के लिए आईओटी आधारित स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करने के लिए राजस्थान को पुरस्कृत किया गया। नई दिल्ली में 25 अगस्त, 2022 को आयोजित डिजिटेक कॉन्क्लेव-2022 में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री महेश जोशी एवं एसीएस पीएचईडी सुबोध अग्रवाल ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। राजस्थान ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत सर्वाधिक गांवों में आईओटी आधारित स्मार्ट वॉटर सप्लाई मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए हैं। जयपुर जिले के 15 गांवों में नलों के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की रियल टाइम मॉनिटरिंग के पायलट प्रोजेक्ट के तहत आईओटी सिस्टम लगाया गया।

ऐसे काम करता है आईओटी सिस्टम

इस सिस्टम में उच्च जलाशय से किए जाने वाली पेयजल आपूर्ति की लाइन की शुरुआत, पाइपलाइन के ब्रांच नोड एवं टेल नोड पर सेंसर्स लगाए गए हैं। यह सिस्टम लगने के बाद गांवों में नल के माध्यम से होने वाली पेयजल आपूर्ति के प्रबंधन में भी बदलाव दिखाई दिए हैं। इन सेंसर्स को इंटरनेट से जोड़ा गया है। जिसके माध्यम से सेंसर्स द्वारा एकत्र डेटा का आदान-प्रदान एवं मॉनिटरिंग की जाती है। इन सेंसर्स के माध्यम से यह चैक किया जाता है कि टंकी का पानी शुद्ध है एवं उसमें किसी तरह की अशुद्धि नहीं है।

सरकार ने किए 239 करोड़ रुपए स्वीकृत

जयपुर शहर के परकोटा क्षेत्र में बदली जाएंगी पुरानी पाइपलाइन

—जयपुर—

जयपुर शहर के परकोटा एवं आसपास के क्षेत्रों में पुरानी लाइनें बदलकर नई लाइनें डालने और शहरी जल योजनाओं का संवर्धन कर सप्लाई सुचारू की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार ने 239 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा जयपुर शहर में परकोटा क्षेत्र सभी चौकड़ियों सहित आसपास के क्षेत्रों में पुरानी पाइपलाइन बदलने के साथ जरूरत के हिसाब से नई पाइपलाइन डाली जाएंगी। आमेर की ढाणियों सहित जयपुर के कई हिस्सों को बीसलपुर से जोड़ा जाएगा। इससे करीब 10 हजार की आबादी लाभांवित होगी। इसके अलावा ब्रह्मपुरी, ट्रांसपोर्ट नगर, झोटवाड़ा में पुरानी पाइप लाइनें और जल कनेक्शन बदलने जैसे कार्य होंगे।

जयपुर में बेहतर होगी पेयजल व्यवस्था

- **पृथ्वीराज** नगर के लिए 1311 करोड़ रुपए की बीसलपुर-पृथ्वीराज नगर योजना स्वीकृत।
- **बीसलपुर** से जगतपुरा, प्रतापनगर और महल रोड क्षेत्र में जलापूर्ति की फेज-टू की 215 करोड़ रुपए की पेयजल परियोजना स्वीकृत।
- **दिल्ली** रोड, लक्ष्मण डूंगरी में पेयजल के लिए 20 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत।
- चारदीवारी व आसपास पानी का प्रेशर बढ़ाने के लिए 5 टंकी बनेंगी। मुख्य वितरण व जर्जर पाइपलाइन बदलने पर 165 करोड़ होंगे खर्च।
- नौ लाख की आबादी को इसी योजना से लाभ मिलेगा।

राजस्थान के 45 लाख से ज्यादा घरों को मिल रहा नल से शुद्ध जल

ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से जल कनेक्शन दे रही है राजस्थान सरकार

—जयपुर—

राजस्थान में वर्तमान सरकार के गठन के साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पानी की समस्या को दूर करने की दिशा में काम शुरू किया। वर्ष 2019 में राजस्थान में महज 11 प्रतिशत जल कनेक्शन ही उपलब्ध थे जो अन्य राज्यों के मुकाबले काफी कम थे। दिसम्बर, 2019 में प्रदेश में हर घर जल कनेक्शन वाले परिवारों की संख्या 11 लाख 74 हजार 131 थी, लेकिन सरकार ने इस दिशा में काम शुरू किया और अब कनेक्शन की संख्या 45 लाख हो गई है। इस प्रकार 2019 से लेकर अभी तक प्रदेश में 33 लाख 15 हजार नए जल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। सीएम अशोक गहलोत की मॉनिटरिंग एवं समीक्षा से कनेक्शन देने का ग्राफ तेजी से ऊपर चढ़ा है। राज्य सरकार वर्ष 2024 तक प्रदेश के सभी ग्रामीण परिवारों को हर घर जल कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

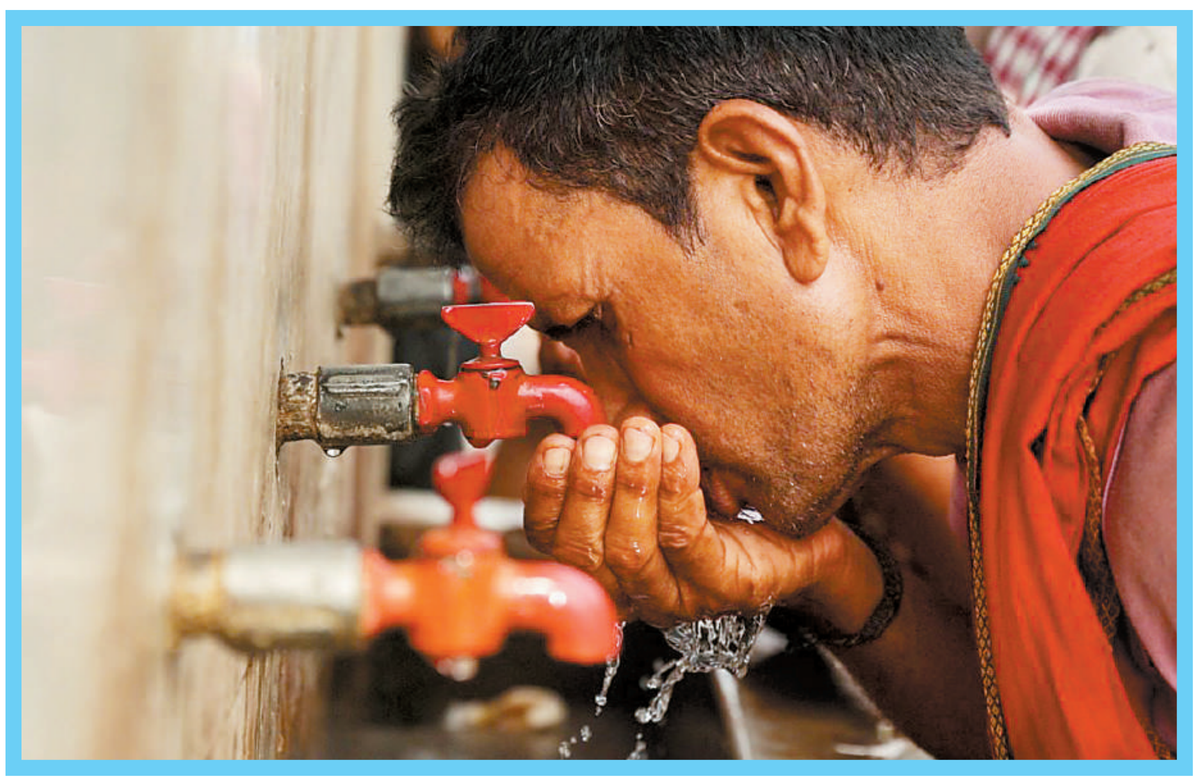

पहली तिमाही में 7.35 लाख नए कनेक्शन

जनवरी से मार्च, 2023 की तिमाही में 7 लाख 35 हजार जल कनेक्शन दिए गए। जनवरी से मार्च की तिमाही के प्रतिदिन जल कनेक्शन को देखें तो राजस्थान देश में तीसरे स्थान पर रहा है। अकेले मार्च 2023 में 3 लाख 74 हजार से अधिक ग्रामीण परिवारों को जल कनेक्शन दिए गए। राजस्थान ने अब तक के सर्वाधिक जल कनेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 31 मार्च 2023 को एक दिन में 27 हजार 470 कनेक्शन किए हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 14 लाख 13 हजार 679 जल कनेक्शन किए जा चुके हैं।

स्वच्छता समितियों के खोले खाते

वित्तीय वर्ष 2023-24 में अभी तक जारी 5.81 लाख जल संबंधों एवं प्रतिदिन जल कनेक्शन की संख्या के आधार पर राजस्थान ने अच्छी परफोरमेंस दी है। अभी तक 17 हजार 854 करोड़ रुपए व्यय कर खर्च के मामले में राजस्थान दूसरे स्थान पर है। प्रदेश के 43 हजार 251 गांवों में ग्राम जल स्वच्छता समितियों के गठन के साथ ही करीब 13 हजार ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों का बैंक खाता खोला जा चुका है। समितियों के गठन और विलेज एक्शन प्लान तैयार करने में भी देश में सबसे आगे है। अभी तक 43 हजार 208 ग्राम कार्य योजनाएं बनाई जा चुकी हैं।

15 हजार लीटर पानी के उपभोग पर जल शुल्क नहीं

—जयपुर—

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जल उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए कई अहम निर्णय किए हैं। इसके तहत शहरी क्षेत्रों में चालू मीटर वाले घरेलू जल उपभोक्ताओं से 15 हजार लीटर मासिक उपभोग तक जल शुल्क नहीं लिया जा रहा है। इसी तरह गैर मरूस्थलीय इलाके के ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू जल उपभोक्ताओं को 40 एलपीसीडी तथा मरूस्थलीय क्षेत्र में 70 एलपीसीडी पानी के उपभोग तक जल शुल्क माफ रहेगा। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 26 लाख 31 हजार उपभोक्ताओं को प्रतिवर्ष 177 करोड़ रुपए से अधिक जल शुल्क माफ किया गया। राज्य सरकार की एमनेस्टी योजना के तहत प्रदेश की सभी नगरीय एवं ग्रामीण पेयजल योजनाओं के सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को 31 दिसम्बर, 2021 तक के बकाया जल प्रभार शुल्क 30 सितम्बर तक एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज एवं जुर्माने में शत-प्रतिशत छूट दी गई थी। गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 1207 आरओ प्लांट लगाए । अगस्त 2016 में चिह्नित शेष 6849 फ्लोराइड प्रभावित गांव-ढाणियों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था के साथ दिसम्बर 2018 के बाद 3 हजार 866 गांव-ढाणियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने एवं 10 हजार 700 नए ट्यूबवैल स्थापित किए जाने का कार्य किया जा रहा हैं।

राजस्थान में पेयजल प्रोजेक्ट्स पर सरकार का फोकस

वृहद परियोजनाओं से दूर होगी पानी की कमी

—जयपुर—

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सर्वाधिक फोकस पानी पर है। राजस्थान की विषम परिस्थितियों में किस तरह पानी उपलब्ध कराया जाए, इसे लेकर कई वृहद परियोजनाएं राजस्थान में चल रही हैं। इसमें चम्बल-धौलपुर-भरतपुर वृहद परियोजना भी शामिल है। इसके लिए 3 हजार 106 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। धौलपुर जिले के 132, भरतपुर जिले के 953 गांव सहित भरतपुर के 8 शहरों की 2054 तक लक्षित 37 लाख 88 हजार आबादी को इसका लाभ मिलेगा।

इसी तरह 1799 करोड़ रुपए की राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना तृतीय चरण की राज्य मद से स्वीकृति दी गई है। इससे जोधपुर शहर के साथ ही जोधपुर जिले के 1830 गांव, बाड़मेर के 211, पाली के 126 गांवों को पानी मिलेगा। जाखम बांध से प्रतापगढ़ जिले के प्रतापगढ़, अरनोद एवं पीपलखूंट क्षेत्र के 524 गांवों को हर घर जल उपलब्ध कराने के लिए 1062.77 करोड़ रुपए की परियोजना अनुमोदित की गई है। परियोजना से 82 हजार 525 घरों में जल कनेक्शन दिए जाएंगे। 2053 की आबादी के हिसाब से 76 लाख से अधिक आबादी को इसका लाभ मिलेगा।

399 गांवों को मिलेगा शुद्ध पेयजल

बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ एवं सज्जनगढ़ पंचायत समिति के 399 गांवों को माही बांध से शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए 211.60 करोड़ रुपए की पेयजल परियोजना मंजूर की गई है। वर्ष 2051 तक की अनुमानित 9 लाख 64 हजार से अधिक की आबादी को इसका लाभ मिलेगा। 81 हजार से अधिक घरों को कनेक्शन दिए जाएंगे। 93.99 करोड़ रुपए की राजीव गांधी लिफ्ट परियोजना आधारित बारू, धोलिया, टेपू, टेकरा, राणेरी, सिंहड़ा पेयजल परियोजना का अनुमोदन किया गया है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा के बाद पीएचईडी ने जारी की नई नीति की अधिसूचना

अब शहरी क्षेत्रों की बहुमंजिला इमारतों को मिलेंगे जल कनेक्शन

—जयपुर—

राज्य के नगरीय क्षेत्रों के बहुमंजिला भवनों में पेयजल कनेक्शन के लिए पीएचईडी ने नई नीति की अधिसूचना जारी कर दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2023-24 के बजट में बहुमंजिला भवनों को पेयजल कनेक्शन देने की घोषणा की थी। इन इमारतों में जल कनेक्शन का शुल्क 25 रुपए प्रति वर्गफुट तय किया है। शुल्क की गणना फ्लैट के कारपेट एरिया के हिसाब से होगी। नीति में जल कनेक्शन शुल्क में रियायत भी दी गई है। इसके लिए इमारतों में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण एवं पुनः उपयोग प्रणाली व सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने पर बिल्डर को कनेक्शन पर 5 से 20 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।

नई नीति में ये प्रावधान

-नीति सभी नगरपालिका, सरकार के अधिसूचित क्षेत्रों की बहुमंजिला इमारतों पर लागू।

-इमारत में एक ही कनेक्शन जारी किया जाएगा।

-कनेक्शन रेरा, नगर निकाय, विकास प्राधिकरण या अन्य सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के बाद ही जारी होगा।

-अधीक्षण अभियंता द्वारा कनेक्शन फिजिबल होने पर एकमुश्त राशि जमा कराने पर 60 दिन में जारी होगा।

-घरेलू पेयजल मांग की गणना 1500 वर्गफीट कारपेट एरिया तक के फ्लैट में 5 व्यक्ति और इससे अधिक में 7 व्यक्ति प्रति फ्लैट के अनुसार होगी।

-कनेक्शन के लिए एकमुश्त शुल्क की 25 प्रतिशत राशि कनेक्शन जारी होने के समय देनी होगी।

-75 प्रतिशत एक मुश्त शुल्क राशि जल उपभोग बिल के साथ 60 समान किश्तों में 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष साधारण ब्याज के साथ देनी होगी।

जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग द्वारा प्रसारित

जगमग **राजस्थान**

राजस्थान में 100 यूनिट निशुल्क बिजली

1 करोड़ से ज्यादा घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली बिल होगा शून्य

—जयपुर—

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घरेलू बिजली बिल को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। सीएम गहलोत ने राज्य के बजट में 100 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा की थी। इसके बाद सीएम ने 200 यूनिट तक फ्यूल सरचार्ज सहित अन्य शुल्क माफ कर दिए। प्रदेश के लोगों को इसी साल के जून से इस घोषणा का लाभ मिलने लगा है। प्रदेश के 1.04 करोड़ परिवारों को लाभ देय है। राजस्थान सरकार घरेलू व कृषि मिलाकर करीब 80 प्रतिशत परिवारों को फ्री बिजली या इसमें बड़ी छूट दे रही है। सरकार की ओर से लगाए गए महंगाई राहत कैम्पों में यह लाभ प्राप्त करने के लिए अब तक करीब 94.63 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है।

ऐसे मिल रहा है फायदा

राजस्थान में अब घरेलू कंज्यूमर्स को 100 यूनिट तक बिजली फ्री मिल रही है। किसी भी कंज्यूमर को पहले 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर बिल शून्य आएगा। इसके अलावा 200 यूनिट तक बिजली पर किसी तरह का सरचार्ज, परमानेंट चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी फीस नहीं देनी पड़ रही है। सरकार की इस योजना से आमजन में खुशी है।

बिजली बिल की गणना

50 यूनिट तक 4.75 रुपए प्रति यूनिट, 51 से 100 यूनिट तक 6.50 रुपए प्रति यूनिट, 151 से 300 यूनिट तक 7.35 रुपए प्रति यूनिट, 301 से 500 यूनिट तक 7.65 रुपए प्रति यूनिट, 501 या उससे ज्यादा यूनिट पर 7.95 रुपए प्रति यूनिट, 300 यूनिट तक बिजली की खपत होने पर फिक्स चार्ज 275 रुपए लगता है। 301 से 500 यूनिट तक की खपत होने पर फिक्स चार्ज 345 रुपए वसूला जाता है। शहरी उपभोक्ताओं पर 15 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से अरबन सेस लगाया जाता है। सभी उपभोक्ताओं पर 40 पैसे प्रति यूनिट की दर से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगाई जाती है।

किसान हितैषी सरकार

ब्याज में छूट से किसानों को फायदा

—जयपुर—

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर कृषि श्रेणी के नियमित अथवा कटे हुए तथा गैर कृषि श्रेणी के अन्तर्गत कटे हुए विद्युत कनेक्शनों के लिए 31 दिसम्बर, 2022 तक देय विलम्ब राशि व ब्याज में चरणबद्ध छूट की अवधि को 30 सितम्बर, 2023 तक बढ़ाया गया। इससे 22 लाख से अधिक उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने विद्युत कनेक्शन की पेंडेंसी को खत्म करने की दिशा में भी काम किया है। 31 दिसम्बर, 2012 से चली आ रही 9 वर्ष से अधिक की पेंडेंसी के लगभग 4.88 लाख विद्युत कनेक्शन आवेदन खत्म करने को लेकर सरकार काम कर रही है। इसके लिए 22 फरवरी, 2022 तक के समस्त बकाया विद्युत कनेक्शन दो वर्षों में जारी किए जाएंगे। योजना के तहत वर्ष 2022-23 में 99 हजार 137 और वर्ष 2023-24 में जुलाई माह तक 48 हजार से अधिक कृषि कनेक्शन जारी किए गए हैं। सरकार ने कृषि कनेक्शन के लिए अलग से फीडर स्थापित करना शुरू किया है। प्रथम चरण में 1534 फीडर का काम पूरा हो गया है। दिसम्बर, 2018 से मई, 2023 तक किसानों को बिजली के बिलों में 71 हजार 53 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया।

प्रतिमाह दो हजार यूनिट निशुल्क बिजली से

करीब 11 लाख किसानों का बिजली बिल हुआ शून्य

—जयपुर—

राजस्थान सरकार किसानों को मुख्यमंत्री निशुल्क कृषि बिजली योजना के तहत प्रति माह 2 हजार यूनिट बिजली मुफ्त दे रही है। इससे प्रदेश के करीब 11 लाख किसानों का बिजली बिल शून्य हो गया है। महंगे बिजली बिल के चलते किसान अपने खेतों की सिंचाई सही तरीके से नहीं कर पाते। ऐसे में सरकार का यह फैसला किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ है। 2000 यूनिट बिजली बिल मुफ्त मिलने पर किसान अपनी फसल की सिंचाई के साथ-साथ अच्छी देखभाल कर सकता है। इसके चलते फसल की उपज भी ज्यादा होगी।

16 लाख से ज्यादा कृषि कनेक्शन

राज्य सरकार कृषि कनेक्शन वाले किसानों को हर महीने 2 हजार यूनिट बिजली मुफ्त दे रही है। राजस्थान में करीब 16 लाख से ज्यादा किसानों के पास कृषि कनेक्शन हैं। इनमें से 11 लाख से ज्यादा किसानों को सरकार की इस योजना का लाभ मिलेगा। प्रदेश के करीब 70 प्रतिशत किसानों का बिजली का बिल शून्य आ रहा है। जुलाई, 2023 तक 48 हजार से अधिक कृषि कनेक्शन दिए जा चुके हैं।

691 नए जीएसएस से मजबूत हुआ बिजली तंत्र

तीन नई सुपर क्रिटिकल इकाइयों से उत्पादन प्रारंभ

—जयपुर—

बिजली तंत्र को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कटिबद्ध हैं। दिसम्बर, 2018 से मई, 2023 तक 400 केवी का एक ग्रिड सब-स्टेशन, 220 केवी के 5, 132 केवी के 32 ग्रिड सब-स्टेशन एवं 33 केवी के 653 सब-स्टेशन स्थापित किए गए हैं। दिसम्बर, 2018 से अब तक 3,574 मेगावाट वृद्धि सहित कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 23,639 मेगावाट हो गई है। इसके अलावा 400 केवी के 2, 220 केवी के 11, 132 केवी के 34 जीएसएस और 33/11 केवी के 150 सब स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की गई है। 765 केवी का ग्रिड सब स्टेशन जोधपुर में स्थापित करने के लिए 3,089 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की गई है। छबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन की 660 मेगावाट की छठी इकाई एवं सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल परियोजना की 660 मेगावाट की इकाई-7 तथा 660 मेगावाट की इकाई-8 से वाणिज्यिक विद्युत उत्पादन शुरू हो गया है। कुसुम कंपोनेंट-ए के तहत 93 मेगावाट के 71 संयंत्र स्थापित किए गए हैं।

मुख्यमंत्री के प्रयासों से पूरे देश के लिए मॉडल स्टेट बना राजस्थान

राजस्थान सौर ऊर्जा पंपों की स्थापना में नंबर वन

—जयपुर—

राजस्थान सरकार ने किसानों को सिंचाई के लिए बिजली की उपलब्धता पर निर्भर नहीं रहना पड़े, इसके लिए खेतों में सोलर पम्प लगाने पर 60% तक का अनुदान दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इस पहल के जरिए प्रदेश के किसान सिंचाई के लिए कृषि विद्युत कनेक्शन, डीजल चलित संयंत्रों और अन्य वैकल्पिक साधनों पर निर्भर होने की बजाय सौर पम्प लगाने के लिए प्रेरित हुए। इससे किसानों की बिजली पर निर्भरता कम हुई है, वहीं प्रदेश में हरित ऊर्जा के रूप में सौर ऊर्जा के प्रयोग को भी बढ़ावा मिला है। सिंचाई सुविधा होने से खेतों में उपज बढ़ी है। राजस्थान सौर ऊर्जा पंपों की स्थापना में देश में पहले पायदान पर है।

इकाई की लागत का 60 प्रतिशत तक अनुदान

कृषकों को सौर ऊर्जा पंप संयंत्र स्थापना करने पर इकाई की लागत का 60 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है। प्रदेश के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को 45 हजार रुपए का अतिरिक्त अनुदान दिया जा रहा है।

57 हजार से अधिक किसानों को अनुदान

परियोजना के तहत पिछले चार सालों में 57 हजार 657 किसानों को संयंत्र लगाने के लिए 982.95 करोड़ रुपए अनुदान दिया गया। वर्ष 2018-19 में 3, 462 किसानों को 70.30 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया। वर्ष 2019-20 में 10 हजार 4 किसानों को 57.81 करोड़ रुपए, वर्ष 2020-21 में 13 हजार 880 किसानों को 133.39 करोड़ रुपए, वर्ष 2021-22 में 10 हजार किसानों को 320.41 करोड़ रुपए और वर्ष 2022-23 में अब तक 20 हजार 311 किसानों को 401 करोड़ 4 लाख रुपए का अनुदान देकर लाभान्वित किया गया है।

राजस्थान में लगेगा तैरता सोलर प्लांट

सस्ती बिजली के लिए बांध, तालाब, झीलों पर लगेंगे फ्लोटिंग सोलर प्लांट

बीसलपुर और माही बांध चिह्नित, 500 से 2 हजार मेगावाट तक के प्लांट

—जयपुर—

राजस्थान में सस्ती बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए अब पानी में भी सोलर प्लांट लगेंगे। ये प्लांट बांध, तालाब और झीलों में लगाए जाएंगे। पायलट प्रोजेक्ट के लिए जयपुर में मानसागर एवं अजमेर के आनासागर, फायसागर को चिह्नित किया गया है। वहीं, बड़े प्रोजेक्ट के लिए बीसलपुर और माही बांध को चिह्नित किया गया है। स्टडी के लिए हाल ही राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम और एनटीपीसी (नेशनल थर्मल पॉवर कार्पोरेशन) की टीम ने बांध, झीलों का जायजा भी लिया है। खास यह है कि इसके जरिए बांध, तालाब और झीलों से पानी का वाष्पीकरण 65 से 70 प्रतिशत तक कम होगा और जमीन की तुलना में 10 से 15 प्रतिशत तक ज्यादा बिजली बनेगी। प्रस्ताव पर जल्द ही निर्णय होगा।

यह होगा

बांध जल संसाधन विभाग के पास हैं, इसलिए उससे अनुमति लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। संभवतया एनटीपीसी बतौर वेंडर काम करेगा, जबकि अक्षय ऊर्जा निगम इसका खर्चा वहन करेगा।

8 लाख करोड़ रुपए के मिले प्रस्ताव

देश-विदेश के निवेशकों ने प्रदेश में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए इंवेस्ट राजस्थान समिट-2022 में 8 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव भेजे हैं। ऊर्जा परियोजनाओं को जल्द लागू करने के लिए सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।

फायदे का लेखा-जोखा

- जमीन पर 1 मेगावाट क्षमता के प्लांट के लिए डेढ़ से 2 हैक्टेयर भूमि की जरूरत है। जबकि, पानी में एक हैक्टेयर एरिया में ही काम होगा।
- जमीन या छत पर लगने वाले प्लांट के मुकाबले 10 से 15 प्रतिशत ज्यादा बिजली उत्पादन।
- पानी के वाष्पीकरण की दर में 62 से 70 प्रतिशत की कमी।
- बांध, तालाब में काई जमने की स्थिति कम होगी। इससे पानी के ट्रीटमेंट प्लांट संचालन में खर्चा कम होगा।
- सोलर पैनल की सफाई- धोने में काम आने वाला पानी बचेगा।

पायलट प्रोजेक्ट प्रस्तावित : 1 से 2 मेगावाट तक के प्लांट

- मानसागर, जयपुर- 1 मेगावाट
- आनासागर, अजमेर- 2 मेगावाट
- फायसागर, अजमेर- 2 मेगावाट

दो बांधों में बड़े प्रोजेक्ट

- बीसलपुर बांध- 500 से 1000 हजार मेगावाट
- माही बांध- 2000 मेगावाट (अभी स्टडी की गई है)

अक्षय ऊर्जा में राजस्थान अव्वल

अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान देश का अव्वल राज्य है। इस उपलब्धि को कायम रखने के लिए प्रदेश में रूफ-टॉप सोलर परियोजनाएं, कृषक हितकारी, कुसुम कंपोनेंट-ए परियोजनाएं और अन्य लघु, मध्यम एवं वृहद् अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के साथ ही इनके क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं का निराकरण भी सरकार कर रही हैं।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की थी घोषणा

सभी सरकारी विभागों में लगाए जाएंगे स्मार्ट प्री-पेड मीटर

—जयपुर—

राज्य सरकार प्रदेश के समस्त राजकीय कार्यालयों में एक सितम्बर, 2023 तक स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगवाएगी। इस संबंध में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में घोषणा की थी, जिसे मूर्त रूप देने की कवायद शुरू कर दी गई है। बजट घोषणा की अनुपालना में पुनरोत्थान वितरण योजना के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त राजकीय कार्यालयों सहित सभी विद्युत उपभोक्ताओं (कृषि के अतिरिक्त) के स्मार्ट प्री- पेड मीटर ऊर्जा विभाग की ओर से लगाया जाना अनिवार्य है। इस नवाचार का शुभारंभ प्रदेश के राजकीय कार्यालयों से किया जाएगा। इससे योजना का क्रियान्वयन व्यवस्थित रूप से हो सकेगा तथा आमजन को भी इसे अपनाने में सुविधा होगी। स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगवाने से कार्यालयों द्वारा किए जा रहे विद्युत व्यय के त्वरित भुगतान एवं निस्तारण में भी मदद मिलेगी। स्मार्ट प्री-पेड मीटर की स्थापना के लाभ तथा बिल राशि का अग्रिम भुगतान आदि के बारे में विद्युत निगमों द्वारा जिला स्तर पर राजकीय कार्यालयों में संबंधित अधिकारियों अथवा कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कुशल नेतृत्व तथा ऊर्जा राज्य मंत्री की ऊर्जा संरक्षण के प्रति विशिष्ट संवेदना के कारण राज्य को गत वर्ष के साथ-साथ इस वर्ष भी राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 से नवाजा गया है। राजस्थान सरकार लगातार ऊर्जा संरक्षण की दिशा में काम कर रही है।

ऊर्जा विभाग द्वारा प्रसारित

राजस्थान सरकार ने शुरू कराया काम, 37247 करोड़ का प्रोजेक्ट बदलेगा पूर्वी राजस्थान की तस्वीर

ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट: 13 जिलों और 40 फीसदी आबादी की लाइफलाइन बनेगी

नवनेरा बैराज और ईसरदा बांध का निर्माण तेज गति से चल रहा

3,510 मिलियन घन मीटर पानी मिलेगा, पेयजल और सिंचाई को नहीं रहेगी पानी की कमी

जयपुर। राजस्थान में 13 जिलों और प्रदेश की करीब 40 फीसदी आबादी की लाइफलाइन ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट (ईआरसीपी) पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार में काम शुरू हुआ है। जनता को मीठा पानी पिलाने और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने की इस योजना के लिए राज्य सरकार ने अपने स्तर पर मूर्तरूप देना शुरू कर दिया है।

राज्य स्तर पर बजट का प्रावधान करने के साथ ही इसका काम द्रुत गति से शुरू करवाया है। परियोजना से राज्य के 13 जिलों की आबादी को 3510 मिलियन घन मीटर पानी मिलेगा। जिसमें से करीब 49 फीसदी यानी 1723.5 मिलियन घन मीटर पानी पीने के लिए सप्लाई होगा। वहीं इस योजना का काम पूरा हो जाने पर तेरह जिलों में 2051 तक पीने का भरपूर पानी मिलेगा। यही नहीं फीडर केनाल के माध्यम से पूर्व में निर्मित क्षेत्र की 26 वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को पानी दिया जाना प्रस्तावित है ताकि इन बांधों में जल उपलब्धता सुनिश्चित कर पूर्व में सृजित 0.8 लाख हैक्टेयर में सिंचित क्षेत्र पुनर्स्थापित किया जा सके। साथ ही यह परियोजना करीब 2 लाख हैक्टेयर नए क्षेत्र में माइक्रो इरिगेशन सिस्टम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराएगी। इससे यहां खेतों में किसानों की फसलें लहलहाएंगी और उनके जीवन और आर्थिक व्यवस्था को कई गुना मजबूत करेगी। ईआरसीपी से उद्योगों एवं दिल्ली मुम्बई इण्डस्ट्रीयल कॉरिडोर यानी डीएमआईसी के उपयोग के लिए भी 286.4 मिलियन घन मीटर पानी उपलब्ध हो जाएगा। इससे क्षेत्र में इंडस्ट्री के विकास और इससे मिलने वाले रोजगार को भी पंख लग जाएंगे। मानसून के दौरान चम्बल बेसिन की सहायक नदी पार्वती, कालीसिंध, कुन्नू, कूल एवं मेज में उपलब्ध अधिशेष जल को न्यून जल वाले नदी बेसिनों में अपवर्तित करने के लिए यह परियोजना बनाई गई है।

इस परियोजना की अनुमानित लागत 37247.12 करोड़ रुपए है। परियोजना के तहत सबसे अधिक भराव क्षमता 226.65 मिलियन घन मीटर के नवनेरा बैराज का काम तो काफी हद तक हो भी गया है।

परियोजना की ग्रेविटी फीडर की लम्बाई 965 किलोमीटर, टनल की लंबाई 4.5 किलोमीटर, पंपिंग मैन की लंबाई 141 किलोमीटर एवं नेचुरल स्ट्रीम की लंबाई 157.5 किलोमीटर है। इसके तहत 15 स्थानों पर पंपिंग स्टेशन प्रस्तावित हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा में परियोजना को शीघ्र धरातल पर लाने के उद्देश्य से ईआरसीपी कॉर्पोरेशन गठित करने की घोषणा की थी। 17 जून 2022 को आदेश जारी कर इसका गठन किया। ईआरसीपी के दो महत्वपूर्ण हिस्से नवनेरा बैराज एवं ईसरदा बांध का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

प्रोजेक्ट्स में 6 बैराज और 1 बांध बनेगा

परियोजना के तहत 6 बैराज एवं 1 बांध बनाया जाएगा। इसमें बैराज का निर्माण जल अपवर्तन एवं बांध का निर्माण जल संग्रहण के लिए किया जाएगा।

- **कुन्नू बैराज**
बारां जिले की शाहबाद तहसील में कुन्नू नदी पर बनेगा, जिसकी भराव क्षमता 56.97 मिलियन घन मीटर होगी।
- **रामगढ़ बैराज**
बारां जिले की किशनगंज तहसील में कुल नदी पर बनेगा, जिसकी भराव क्षमता 50.49 मिलियन घन मीटर होगी।
- **महलपुर बैराज**
बारां जिले के मांगरौल में बनेगा, जिसकी भराव क्षमता 162.20 मिलियन घन मीटर होगी।
- **नवनेरा बैराज**
कोटा जिले की दिगोद तहसील में कालीसिंध नदी पर बनेगा, जिसकी भराव क्षमता 226.65 मिलियन घन मीटर होगी। यह बैराज सर्वाधिक भराव क्षमता वाला होगा।
- **मेज बैराज**
बूंदी जिले की इन्द्रगढ़ तहसील में मेज नदी पर बनेगा, जिसकी भराव क्षमता 50.80 मिलियन घन मीटर होगी।
- **राठौड़ बैराज**
सवाई माधोपुर जिले की चौथ का बरवाड़ा तहसील में बनास नदी पर बनेगा, जिसकी भराव क्षमता 143.09 मिलियन घन मीटर होगी।
- **डूंगरी बांध**
बैराज के साथ ही सवाई माधोपुर जिले की खण्डार तहसील में 2099 मिलियन घन मीटर क्षमता का डूंगरी बांध बनाया जाना प्रस्तावित है। यह ईआरसीपी के तहत जल संग्रहण का मुख्य बांध होगा। इससे 2 लाख हैक्टेयर नया सिंचित क्षेत्र विकसित होगा।

13 जिलों को मिलेगा पानी

प्रदेश के 13 जिलों अजमेर, अलवर, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, झालावाड़, भरतपुर, दौसा, जयपुर एवं टोंक के लिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना जीवनदायिनी साबित होगी, इसीलिए राज्य के वित्तीय संसाधनों से कार्य निरन्तर जारी है। अभी तक 1507 करोड़ रुपए व्यय कर नवनेरा बैराज एवं ईसरदा बांध के कार्य प्रगतिरत हैं। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम द्वारा रामगढ़ बैराज, महलपुर बैराज एवं नवनैरा-गलवा-बीसलपुर-ईसरदा लिंक परियोजना के कार्य पर 15113.00 करोड़ की स्वीकृति 12 अप्रैल 2023 को जारी की जाकर निविदाएं आमंत्रित कर ली गई हैं।

इन 13 जिलों के लिए वरदान होगी योजना

13 जिलों में झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर एवं धौलपुर के लिए योजना किसी वरदान से कम नहीं होगी। यह परियोजना इन जिलों के लिए जीवनदायिनी साबित होगी। क्योंकि इससे ना केवल पीने का बल्कि क्षेत्र में किसानों को सिंचाई और इंडस्ट्री को भरपूर पानी मिलेगा। इससे क्षेत्र के विकास की गति कई गुना रफ्तार से बढ़ेगी।

पानी की चुनौती दूर हो रही, प्रोजेक्ट जमीन पर मूर्तरूप ले रहे

बड़ी परियोजनाओं से अब पेयजल और सिंचाई के लिए मिल रहा है पानी

12 बांधों के जीर्णोद्धार के लिए 404.14 करोड़ मंजूर

जयपुर। अशोक गहलोत सरकार ने आम जनता की पेयजल और किसानों को सिंचाई के पानी की समस्या को दूर करने के लिए संवेदनशीलता दिखाई। बड़ी परियोजनाओं पर प्लानिंग करवाकर परियोजनाओं के तंत्र को मजबूत बनाकर पीने के लिए पानी सप्लाई के तंत्र और सिंचाई के लिए किसानों को पूरा पानी दिलवाने पर तेज गति से काम करवाया।

बांधों, बैराजों और परियोजनाओं में पानी संरक्षित रखने और सप्लाई से पानी की समस्या की चुनौती अब दूर हो रही है। बड़े प्रोजेक्ट्स के तंत्र जमीन पर मूर्तरूप ले रहे हैं।

36 बांधों का जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण

बांध पुनरुद्धार एवं सुधार परियोजना में (ड्रिप) बड़े बांधों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। जल रिसाव रोका जाएगा। इससे जलभराव क्षमता बढ़ेगी, किसानों को सिंचाई, आम जन को पेयजल को अधिक जल मिलेगा। बांधों का आधुनिकीकरण किया जाएगा जिससे वर्षा कालीन/बाढ़-बचाव संबंधी आंकड़े तत्काल उपलब्ध होंगे। इसमें कुल 189 बांधों को लिया गया है। वर्ष 2020-21 में 18 एवं वर्ष 2021-22 में 18 बांधों के जीर्णोद्धार की घोषणा हुई थी। वर्ल्ड बैंक सहित अन्य एजेंसियों से कुल 35 बांधों को 660.92 करोड़ के कामों की पीएसटीएस भेजी जा चुकी है। 12 बांधों के जीर्णोद्धार के लिए 404.14 करोड़ मंजूर हो चुके हैं। 21 बांधों के जीर्णोद्धार के लिए 24647 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। अन्य स्तर पर 3 बांधों के जीर्णोद्धार लिए 39.53 करोड़ की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु 209.24 करोड़ का प्रावधान है, जून 2023 तक 6.77 करोड़ खर्च हो चुके हैं।

धौलपुर लिफ्ट बहुद्देशीय परियोजना

धौलपुर राजाखेड़ा, सैंपऊ के 256 गांवों में 39980 हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। 2023-24 हेतु 50 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान स्वीकृत है। जिसके विरूद्ध माह जून 2023 तक 31.58 करोड़ रुपए व्यय किए।

नर्मदा नहर परियोजना

1793 किमी में वितरिकाओं-उपवितरिकाओं का कार्य पूर्ण। 2.46 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई। 2231 डिग्गियों का निर्माण कर 1215 डिग्गियों पर पंपिंग यूनिट स्थापित की गई हैं। 3242.04 करोड़ रूपए खर्च किए जा चुके हैं।

5 मध्यम, 41 लघु सिंचाई परियोजनाएं

वित्तीय वर्ष 2022-23 में 5 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं बूंदी के मांगली, डूंगरी नदी, गणेश नाला पर निमार्णाधीन गरडदा सिंचाई परियोजना, झालावाड़ में आहू नदी पर निमार्णाधीन गागरीन सिंचाई परियोजना, तकली मध्यम सिंचाई परियोजना, कोटा, बारां के ल्हासी नदी पर ल्हासी सिंचाई परियोजना तथा बारां जिले के करवरी खुर्द गांव में हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना शामिल हैं। दिसंबर 2022 तक 41 लघु सिंचाई परियोजनाएं प्रगतिरत थीं।

अनास नदी पर गराडिया एनिकट निर्माण

147 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न कार्य 26 मई 2023 से शुरू हैं। मई 2026 तक पूर्ण किया जाएगा। एनिकट में संग्रहित जल को सौर ऊर्जा आधारित सूक्ष्म सिंचाई पद्धति स्थापित कर स्थानीय काश्तकारों को सिंचाई एवं पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

परवन वृहद बहुद्देशीय सिंचाई परियोजना

1821 गांवों में पेयजल के साथ झालावाड, बारां एवं कोटा जिले के 637 गांवों की 2,01,400 हैक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। तापीय विद्युत परियोजना के लिए 79 मिलियन घन मीटर जल उपलब्ध कराके कुल 2970 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा सकेगा। वर्ष 2023-24 के लिए 750 करोड़ का बजट प्रावधान स्वीकृत है।

बड़े प्रोजेक्ट जिन पर काम हुए और जनता को बड़ी राहत मिली

पीपलखूंट हाई लेवल केनाल परियोजना

माही बांध से ईएल 259 मीटर के स्तर से निकाली जाकर दो भागों में विभक्त होगी। पीपलखूंट तहसील के 5000 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा होगा। जाखम परियोजना का 28320 हैक्टेयर क्षेत्र भी माही से जल अपवर्तन कर प्रतापगढ़, उदयपुर, राजसमंद एवं चित्तौडगढ़ जिले में पेयजल सुविधा उपलब्ध होगी। डिग्गियों में जल डाल कर पम्प व पाइपों द्वारा कमाण्ड क्षेत्र के प्रत्येक 1.25-1.5 हैक्टेयर क्षेत्र में फव्वारा पद्धति से सिंचाई जल मिलेगा। तीन साल का 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट है।

कालीतीर लिफ्ट परियोजना

धौलपुर के बसेड़ी विधानसभा के तहसील सरमथुरा के ग्राम कालीतीर में है। बाड़ी के 170 , बसेड़ी के 193 धौलपुर के 59 गांव लाभान्वित होगे। चम्बल नदी से वर्षाकाल में कुल 3553 एमसीएफटी पानी को लगभग 180 मीटर ऊंचाई में लिफ्ट कर धौलपुर के पार्बती बांध, रामसागर बांध को प्रतिवर्ष पूर्ण क्षमता तक भरा जाना प्रस्तावित है। 642.89 करोड़ की लागत से 25 मई 2023 को कार्य शुरू, सर्वे कार्य प्रगति पर।

देवास तृतीय एवं चतुर्थ परियोजना निर्माण कार्य

2023-24 में उदयपुर शहर को अतिरिक्त पेयजल को परियोजना में बांधों का 1691 करोड़ से निर्माण होगा। 1690.55 करोड मंजूर कर निविदा प्रक्रियाधीन है। 1,000 एमसीएफटी वार्षिक जल पेयजल हेतु अपवर्तन उदयपुर की झीलो में होगा। इससे झीले वर्ष पर्यन्त भरी रहेगी एवं पर्यटन- पर्यावरण को बढ़ावा मिलेगा।

अपर हाई लेवल केनाल परियोजना

2500 करोड़ लागत की अपर हाई लेवल केनाल परियोजना से कमाण्ड क्षेत्र से बाहर तथा ऊंचाई पर स्थित बांसवाड़ा जिले के बांसवाड़ा, बागीदौरा एवं कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र तथा 6 तहसीलों बांसवाड़ा, बागीदौरा, गांगड़तलाई, आनंदपूरी, कुशलगढ़ एवं सज्जनगढ़ के कुल 338 गांवों के 42000 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी। 105 किमी लम्बी मुख्य नहर के अलाइनमेंट के तालाबों में पेयजल आपूर्ति संभव होगी। करीब 1.5 हेक्टेयर क्षेत्र में फव्वारा पद्धति द्वारा सिंचाई सुविधा मिलेगी। परियोजना के लिए 2248.94 करोड़ जारी। नवम्बर 2026 तक निर्माण प्रस्तावित, सर्वे कार्य प्रक्रियाधीन।

82778 हैक्टेयर क्षेत्र में जल्द होगी सिंचाई

जयपुर। धौलपुर लिफ्ट परियोजना और अन्य परियोजनाओं से जल्द ही 82778 हैक्टेयर और क्षेत्र में जल्द सिंचाई होने लगेगी। धौलपुर लिफ्ट परियोजना से धौलपुर, राजाखेड़ा, सैपउ एवं मनिया तहसीलों के 256 गांवों में 39,980 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है। परियोजना पर दिसम्बर 2018 से मई 2023 तक 542.77 करोड़ रूपए व्यय किये जा चुके हैं। इसके साथ ही ल्हासी, गागरिन, राजगढ़, तकली, गरड़दा एवं हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से 42,798 हैक्टेयर भूमि सिंचित होगी। इन परियोजनाओं पर दिसम्बर 2018 से अप्रैल 2023 तक 674.82 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं।

इंदिरा गांधी नहर का हो रहा जीर्णोद्धार

नहर के पास जलाशय बन रहे, पेयजल को मिलेगा अतिरिक्त पानी

जयपुर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना द्वितीय चरण की नहरें जो लम्बे समय से लगातार जल प्रवाह के कारण एवं समुचित रख-रखाव के अभाव में जीर्ण-शीर्ण हो गई थी, उनमें से जैसलमेर संभाग में शहीद बीरबल शाखा अन्तर्गत रुपए 48.16 करोड़ का कार्य प्रगति पर है, जिस पर रुपए 44.50 करोड़ रुपए व्यय किये जा चुके हैं। बीकानेर संभाग में दातौर, नाचना, अवाई सांकरिया प्रणाली एवं मुख्य नहर की सीधी नहरों में 102.77 करोड़ की लागत से आवंटित 6 कार्यों में से 2 कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा शेष 4 कार्य प्रगति पर हैं।

इन सभी कार्यों पर 83.68 करोड़ रुपए व्यय किये जा चुके हैं। बरसलपुर शाखा, धोधा वितरिका और भुट्टोवाली वितरण प्रणाली के नवीनीकरण आधुनिकीकरण हेतु रुपए 94.93 करोड़ रुपए के कार्य आवंटित किए गए हैं, कार्य प्रगति पर हैं, जिस पर अब तक 57.79 करोड़ रुपए व्यय किए भी जा चुके हैं। चारणवाला शाखा की नहरों का चरणबद्ध रूप से जीर्णोद्धार हेतु कुल 3 कार्यों के 94.02 करोड़ के कायार्देश जारी कर कार्य आरंभ किए जा चुके हैं। जिन पर अब तक 12.050 करोड़ व्यय हो चुके हैं।

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग ने पेयजल योजनाओं के लिए आवश्यक अतिरिक्त जल उपलब्ध कराने के लिए इन्दिरा गांधी मुख्य नहर की बुर्जी 507, 750, 1121 एवं 1356 के निकट स्थित प्राकृतिक रूप से गहरे स्थानों को वृहद् जलाशयों में विकसित किया जा रहा है। इनमें वर्षा काल या अधिक पानी की उपलब्धता के समय अतिरिक्त पानी एकत्रित किया जाएगा।

पेयजल योजनाओं के लिए इसे उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए 1274 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के विरुद्ध 1087.55 करोड़ के कार्यादेश हो चुके हैं। 249.84 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं।

इंदिरा गांधी फीडर (पंजाब) में 97 किलोमीटर, सरहिन्द फीडर में 100 किलोमीटर री-लाइनिंग का काम होगा

इंदिरा गांधी फीडर (पंजाब) में कुल 97 किमी लंबाई में री-लाइनिंग कार्य करवाये जाने हैं जिसके विरुद्ध अब तक 81.70 किमी लंबाई में री-लाइनिंग कार्य करवाये जा चुके हैं। इन कार्यों पर जून 2023 तक 1052.25 करोड़ व्यय किए जा चुके हैं। राजस्थान द्वारा इन कार्यों पर अपनी हिस्सा राशि में से 659.15 करोड़ पंजाब को हस्तांतरित किए जा चुके हैं। सरहिन्द फीडर में कुल 100 किमी लंबाई में री-लाइनिंग कार्य प्रक्रियाधीन हैं।

जल संसाधन विभाग द्वारा प्रसारित

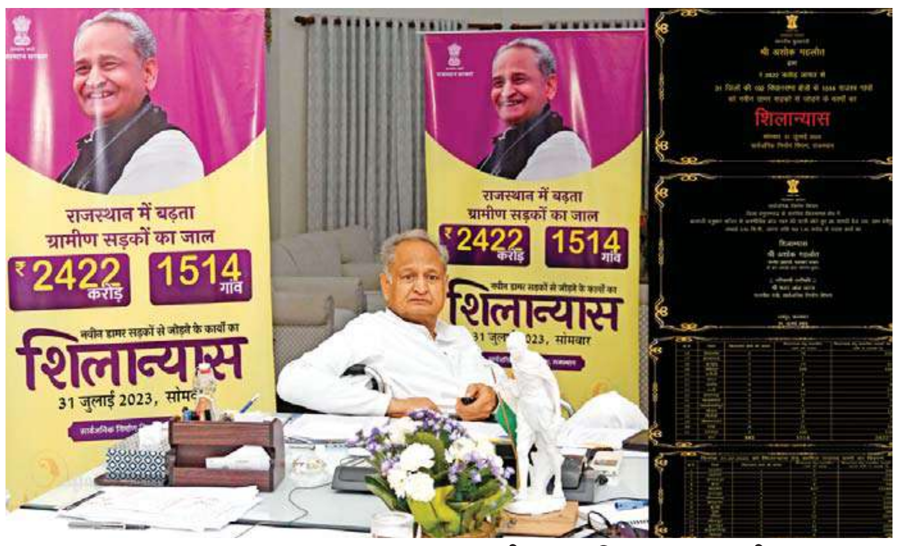

32,384 करोड़ की लागत से 64,946 किलोमीटर सड़कों का हुआ विकास

राजस्थान में सड़कों का बिछा जाल गांवों तक यातायात सुगम हुआ

1164 नए गांवों-ढाणी-मजरों को सड़कों से जोड़ा

जयपुर। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सुगम परिवहन-आवागमन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई ताकि विकास को तेज गति दी जा सके। राज्य सरकार ने सड़कों का जाल शहरों से लेकर दुर्गम गांवों तक बिछवाया। प्रदेश में दिसम्बर 2018 से लेकर जून 2023 तक 12 हजार 230 किलोमीटर सड़क बनाई जा चुकी हैं। सड़क निर्माण पर सरकार 6083.68 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। वहीं राजमार्गों के विकास और निर्माण के कामों पर 5030.52 करोड़ रुपए खर्च कर 1359 किलोमीटर की बढ़ोतरी की। इस तरह से 9427 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्गों व मुख्य जिला सड़कों का निर्माण करवाया है। जिस पर 10,387.26 करोड़ खर्च किए गए। सभी सड़कों के निर्माण, नवीनीकरण और विकास में राजस्थान सरकार ने 4 साल 7 माह में कुल 32,384.26 करोड़ रुपए अब तक खर्च कर जनता को सुगम और त्वरित गंतव्य तक पहुंचने की वृहद सुविधा उपलब्ध करवाई है। यहीं नहीं गांवों में भी अब वाहनों से जल्द पहुंच आसान हो गई है, क्योंकि सरकार ने प्रदेश में 41,930 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के विकास पर 10,882.80 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इस तरह से कुल 64,946 किलोमीटर 32,384.26 करोड़ की लागत से प्रदेश में सड़कों के निर्माण एवं विकास कार्य किए गए है।

सरकार ने न केवल शहर, कस्बों को बल्कि गांवों, ढाणियों और मजरों तक में सड़कों से आवागमन सुगम किया। अब वाहनों से इन इलाकों के ग्रामीणों के परिवहन ने जीवन को आसान बना दिया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 122 किलोमीटर लम्बाई में सड़कों का निर्माण कर 12 गांवों व 31 ढ़ाणी-मजरों को जोड़ा गया है। आरआरएसएमपी (विश्व बैंक योजना) के तहत 66 किलोमीटर लम्बाई में सड़कों का निर्माण कर 19 गांवों को सड़कों से जोड़ा गया है। 498 गावों को मिसिंग लिंक सड़क योजना, ग्रामीण सड़क योजना व अन्य योजनाओं के तहत सड़कों से जोड़ा गया। बजट घोषणा 2019-20 के अनुसार प्रथम चरण में 2011 की जन गणनानुसार 500 व अधिक आबादी के 330 गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए 393 करोड़ रुपए की लागत से किया कार्य सड़क विकास निधि के तहत प्रारम्भ किए गए। 1064 किलोमीटर लम्बाई में सड़कों का निर्माण कर 324 गांवों को सड़कों से जोड़ दिया गया है। अप्रेल 2022 में 367 गांवों को सड़कों से जोड़ने का स्वीकृत किया गया, जिसका काम तेजी से चल रहा है। इनमें से 303 गांवों को सड़कों से जोड़ दिया गया है। इस तरह से कुल 1164 गांव व 31 ढाणी-मंजरे सड़कों से जुड़ चुके हैं।

ये बड़े काम भी हुए

1. राजमार्ग और चौड़े हुए

सरकार ने उच्च मार्गो को चौड़ा व सुदृढ़ करने का भी रिकॉर्ड काम किया। 1077 किलोमीटर लम्बाई में चौड़ाईकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। वहीं 282 किलोमीटर लम्बाई में नवीनीकरण का कार्य पूरा किया गया है।

2. नाबार्ड योजना में भी काम

नाबार्ड योजना के तहत प्रदेश में 872 किलोमीटर लम्बाई में सड़कों के सुदृढ़ीकरण व नवीनीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। वहीं पीपीपी-वीजीएफ, एन्यूटी-ईपीसी के तहत 1372 किलोमीटर लम्बाई में काम हो चुके हैं।

सड़क रखरखाव-विकास और धन के सदुपयोग हेतु 'रेम्स'

जयपुर। सड़कों के रखरखाव, एवं विकास कार्यों के निर्णयों को उचित एवं राजकीय धन के प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता में सुधार के लिए रोड एसेट मैनेजमेंट सिस्टम (आरएएमएस-रेम्स) बनाया गया है। इसे स्टेट डाटा सेन्टर पर अपलोड करने की प्रक्रिया चल रही है। यह वेब पर आधारित सिस्टम है। मोबाइल एप्लीकेशन भी है। इससे सामुदायिक भागीदारी भी सुनिश्चित होती है। 2000 किमी के लिए पायलट डेटा का संग्रहण कर परिणामों की जांच कर ली गई है। स्टेट डेटा सेंटर (एसडीसी) पर अपलोड कार्यवाही हो रही है। एप्लीकेशन का 5 वर्ष तक अनुरक्षण-रखरखाव कार्य अनुबंध के एसपीसी द्वारा होगा। पायलट प्रोजेक्ट के बाद सभी राज्य राजमार्ग व मुख्य जिला सड़कों (लगभग 30 हजार) के नेटवर्क का डेटा संग्रह हो रहा है। अब तक लगभग 12000 किमी सड़कों का डेटा संग्रहण कर एप्लीकेशन में अपलोड किया जा चुका है।

आईटी से हाईटेक पीडब्ल्यूडी विभाग

पीडब्ल्यूडी ने आईटी के इस्तेमाल से खुद को हाईटेक किया है। रेम्स का उपयोग से वार्षिक, बहुवर्षीय मेंटेनेंस योजना बनाने में होगा। सम्पत्ति सूची, वर्तमान व भविष्य की सड़क अवस्था, यातायात, पूर्ण, प्रस्तावित कार्यों की जानकारी प्राप्त करने में भी उपयोग होगा। सरकारी निधि का संतुलित, बेहतर उपयोग होगा।

इससे यह होंगे फायदे

- रोड एसेट की बेहतर एवं प्रभावी जानकारी।
- मानकीकृत तरीकों के उपयोग से डेटा गुणवत्ता में स्थिरता, विश्वसनीयता।
- इंजीनियरिंग, यातायात, आर्थिक एवं सामाजिक मापदंडों से सड़क विकास, रखरखाव मूल्यांकन, प्राथमिकता तय करना।
- मापदंडों के आधार पर सड़क नेटवर्क की क्षमता (परफॉर्मेंस) की बेहतर मोनिटरिंग।
- निधि की उपलब्धता के आधार पर सड़क एसेट्स की स्थिति का अनुमान/आंकलन।
- अधिकतम लाभ/रिटर्न के लिए निधि आवंटन का एक तर्कसंगत आधार।

पीडब्ल्यूडी में हुई 1822 भर्तियां

जयपुर। राजस्थान में सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से विकास कामों में मानव संसाधन की कमी ना रहे। इसके चलते लंबे समय से खाली पड़े पदों को भी भरा गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से सहायक अभियंता के 319, कनिष्ट अभियता(सिविल/विद्युत) के 879 पदों, कनिष्ट सहायक के 281 पदों पर रिक्तियां/भर्तियां निकाली गई। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्तियां प्रदान की जा चुकी है।

इसके अलावा मृतक कर्मचारियों के 333 आश्रितों को विभाग में कनिष्ट सहायक, प्रयोगशाला प्रवर्तक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर अनुकंपा नियक्तियां प्रदान की गई हैं। राजस्थान के उत्कृष्ट खिलाड़ियों के कोटे से 10 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को विभाग में कनिष्ट सहायक के पद पर नियुक्तियां दी गईं हैं। विभाग के विभिन्न पदों पर कुल 1822 अभ्यर्थियों को नियुक्तियां प्रदान की गई हैं।

आरएसआरडीसी, राज्य योजना-निधि एनसीआर में 5440 किलोमीटर रोड बनी

राज्य राजमार्गों को चमकाया विकास को लगे पंख

जयपुर। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में सार्वजनिक निर्माण विभाग के जरिये 16 राज्य राज मार्गों के विकास कार्यो को पूरा करके क्षतिग्रस्त सड़कों को चमचमाता हुआ बना दिया है। यहां से अब कनेक्टिंग गांव, ढाणियां, कस्बे और शहरों तक परिवहन आसान होने से विकास को गति मिलने लगी है। इनमें बाड़मेर-सिन्दरी-जालोर राज्य राज मार्ग-16 ,आहोर-बाली-मुन्दरा राज्य राज मार्ग-16, पीलीबंगा-लखुवाली राज्य राज मार्ग-118, सरदारशहर-लुणकरणसर राज्य राज मार्ग-6 अ, चुरू-भालेरी राज्य राज मार्ग-69, संजू-तरनेऊ राजय राज मार्ग-60, रूपनगढ़-नारायणा राज्य राज मार्ग-100, अजीतगढ़-चला राज्य राज मार्ग-13, सीकर-गनेड़ी-जसवन्तगढ़ राज्य राज मार्ग-20 व 20 अ, बीदासर-नोखा राज्य राज मार्ग-20, सिंघाना-बुहाना राज्य सीमा राज्य राज मार्ग-13 ब, नागौर-तरनेऊ-डीडवाना-मुकन्दगढ़ राज्य राज मार्ग संख्या 8,19,60 व 82ए, बनाड़-भोपालगढ़-कुचेरा राज्य राज मार्ग-63, जोधपुर-मारवाड़ जंक्शन-जोजावर राज्य राज मार्ग-61, जोधपुर-सोजत राज्य राज मार्ग-58, भीनमाल-पंथेरी-जीवाना राज्य राज मार्ग-31अ मुख्य हैं।

वहीं आरएसआरडीसी के माध्यम से 424 किलोमीटर, राज्य योजना में 867 किलोमीटर लम्बाई में चौड़ाईकरण, सुदृढ़ीकरण व नवीनीकरण, राज्य सड़क निधि में 4018 किलोमीटर लम्बाई में चौड़ाईकरण, सुदृढ़ीकरण व नवीनीकरण, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 131 किलोमीटर लम्बाई में सड़कों का विकास कार्य कर नई इबारत लिखी गई।

मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण हुआ

ग्रामीण क्षेत्रों में 3057 कि.मी. लम्बाई में मिसिंग लिंक सड़क बनाई गई। 2420 किमी लम्बाई में 650 करोड़ रुपए की लागत के 1072 मिंसिंग लिंक सड़क कार्य नाबार्ड में मंजूर हुए। 2021-22 से कार्य प्रगति पर हैं। 2026 किलोमीटर लम्बाई में कार्य पूर्ण कर आमजन को उपलब्ध करा दिए गए हैं। वहीं 4382 किमी लम्बाई में 1276 करोड़ रूपए की लागत के 2025 मिंसिंग लिंक सड़क कार्य एसआरएफ में स्वीकृत हो चुके हैं। 2022-23 से काम चल रहा है और 883 किलोमीटर लम्बाई का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

गांवों में ये हुए काम

प्रदेश के ग्रामीण सड़कों का उन्नयन, सुदृढ़ीकरण व नवीनीकृत करने के काम में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार का फोकस रहा। पीएमजीएसवाय के तहत 15576 किलोमीटर लम्बाई में सड़कों को उन्नयन, सुदृढ़ीकरण व नवीनीकरण किया गया। योजना के तृतीय- प्रथम चरण उन्नयन कार्य 237, लम्बाई 2198.38 किलोमीटर लागत 1139.06 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं। वहीं द्वितीय चरण उन्नयन कार्य के तहत 3622.98 किलोमीटर व 6 पुल निर्माण में 1982.59 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। यह कार्य 2019 से चल रहे हैं। वहीं 2256.85 करोड़ रूपए का व्यय कर 5666 किलोमीटर लम्बाई में उन्नयन कार्य कर 590 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। नाबार्ड ग्रामीण सड़क योजना में 12879 कि.मी. लम्बाई में सड़कों को सुदृढ़ व नवीनीकृत करने का कार्य पूर्ण करा दिया गया है। एनसीआर के ग्रामीण क्षेत्र में 184 किमी सड़क बनी है। 148 किमी लम्बाई में नवीनीकरण का काम किया है। राज्य सड़क निधि में 11954 किमी सड़क बनी है।

राज्य के राजमार्ग हो रहे दो-लेन

बजट घोषणा 2022-23 के अनुसार 1001 किलोमीटर लंबाई के 53 राज्य राजमार्गों एवं 2023-24 के अनुसार 714 किलोमीटर लंबाई के 40 राज्य राजमार्गों को दो लेन किए जाने के कार्य प्रगतिरत हैं।

प्रदूषण फैलाते अपशिष्ट प्लास्टिक से 15 हजार किमी सड़कों का रिकॉर्ड बना

तकनीक से बदली तस्वीर, वेस्ट प्लास्टिक से भी हजारों किमी सस्ती-मजबूत सड़कें बनीं

सैल फील्ड कंक्रीट, हरित सड़क भी अब राजस्थान में

जयपुर। राजस्थान में सार्वजनिक निर्माण विभाग सहित प्रदेश की सड़क निर्माण की अन्य एजेंसियों के जरिये तकनीक का उपयोग कर सड़कों की तस्वीर नई विधा से बनाने का काम हुआ। प्रदूषण फैलाने वाली प्लास्टिक से भी प्रदेश में ऐसी सड़कें बना दी गई। जिन पर बड़े भारी वाहन भी पानी की तरह स्मूथ चल रहे हैं। साथ ही वेस्ट प्लास्टिक का निस्तारण भी हो गया है। सड़क निर्माण की इस नई तकनीक से प्रदेश में करीब 15 हजार किलोमीटर सड़क बन चुकी है। यह ना केवल मजबूत हैं बल्कि डामर सड़कों से सस्ती भी बन रही हैं।

इस तरह इनसे दोहरा फायदा हुआ है। एक तरफ प्रदूषण फैलाने वाली प्लास्टिक का सही उपयोग हो गया है, वहीं सरकार के सड़क बनाने के राजस्व में भी कमी आई है। यहीं नहीं सरकार की प्लानिंग और संसाधन उपलब्ध कराने से हमारे इंजीनियर्स ने सैल फील्ड कंक्रीट सड़क का भी निर्माण कर दिया है। अब तक करीब 330 किलोमीटर लम्बाई में सैल फील्ड कंक्रीट से सड़क बना दी गई है। हरित सड़क के नाम से ग्रिट, इमल्शन जिसमें बिना गर्म किए प्लांट में मिलाकर मजबूत सड़कें प्रदेश में बनाई जा रही है। नई तकनीक फुल डैप्थ रिक्लेमेशन से भी पुरानी सड़क की सामग्री का उपयोग कर नयी सामग्री (ग्रिट) के साथ सड़क का निर्माण किया जाने लगा है। इसमें नई सामग्री या ग्रिट की कम आवश्यकता पड़ती है।

पीडब्ल्यूडी का सेवा एप

डीएलपी अवधि में सड़कों व भवनों के रख-रखाव के लिए पीडब्ल्यूडी सेवा ऐप भी विकसित कर संचालित करने की तैयारी है, जिसका अभी परीक्षण चल रहा है। सड़कों व भवनों की टूट-फूट, निर्माण, व्याप्त खामियों की शिकायत अब इसी से ऑनलाइन दर्ज कराई जा सकेगी। शिकायत की सूचना भी ऑनलाइन हो जाएगी। एप के जरिये भवन या सड़क संबंधित कोई समस्या होने पर उसे सीधे आला अधिकारियों तक पहुंचाया जा सकेगा। संबंधित अधिकारियों के मोबाइल या कम्प्यूटर पर डाउनलोड होने के बाद एप खोलते ही अधिकारी को इसकी विस्तृत जानकारी हो जाएगी और वे त्वरित काम के निर्देश जारी कर सकेंगे।

क्वालिटी कंट्रोल की बेहतर मॉनिटरिंग

- एक केन्द्रीय, 5 संभाग स्तरीय एवं 27 जिला स्तरीय, कुल 33 गुण नियंत्रण प्रयोगशाला संचालित हैं।
- एक केन्द्रीय व पांच संभागीय प्रयोगशालाओं के एनएबीएल प्रमाणीकरण को परामर्शदाता का चयन, आवश्यक उपकरणों, आवर्धन/परिवर्तन का आकलन कर स्वीकृति कर क्रय शुरू।
- 27 जिला स्तरीय गुण नियंत्रण प्रयोगशालाओं में से 9 के बाहरी स्रोत के माध्यम से संचालन, एनएबीएल प्रमाणीकरण की कार्यवाही प्रगति पर, शेष 18 प्रयोगशालाओं की प्रक्रिया जारी।
- कार्य गुणवत्ता सुनिश्चित के लिए विभागीय फील्ड, गुण नियंत्रण अभियंताओं द्वारा निरीक्षण-परीक्षण हो रहे, मुख्यालय से इसकी निरंतर समीक्षा।
- सामान्य निरीक्षण के साथ गुणवत्ता सर्तकता टीमों का गठन, गंभीर शिकायतों पर आकस्मिक निरीक्षण। सही नहीं होने पर सख्त कार्यवाही।
- निरीक्षण में कमी मिली तो एटीआर जारी, वर्ष 2022-23 में कुल 23,795 टेस्ट हुए, इनमें 667 टेस्टों में कमियां मिलीं, सुधार हेतु एटीआर जारी।
- वर्ष 2023-24 में कुल 9478 टेस्ट किए, इनमें 66 टेस्टों में कमियां मिलीं, सुधार के लिए एटीआर जारी की।
- नियमित निरीक्षणों में कमियों को दूर कर अतिरिक्त मुख्य अभियंता द्वारा एटीआर का अंतिम निस्तारण होता है।

सुरक्षित, सुगम, सुंदर नगरीय सड़कों संग आगे बढ़ रहा राजस्थान

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने माह जुलाई 2023 में 232 नगरीय निकायों में 2 हजार 642 कि.मी. सड़कों के नवीनीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ाईकरण के कार्यों का शिलान्यास किया है। इस कार्यक्रम में 1528 करोड़ की लागत के 4 हजार 101 कार्य हो रहे हैं। बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा अनेक घोषणाएं की गई थीं और अब इनकी शुरूआत हो गई है। इनमें से पीडब्ल्यूडी से संबंधित कार्यों को विभाग द्वारा प्रमुखता से समय पर पूरा किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि नगर निगम जयपुर हेरिटेज में 20 करोड़ के 25, नगर निगम जयपुर ग्रेटर के 19 करोड़ के 174, नगर परिषद चौमूं में 10 करोड़ के 11, जयपुर जिले की विभिन्न नगर पालिकाओं में लगभग 6-6 करोड़ की लागत के कार्यों का शिलान्यास हुआ है। इनमे सांभर में 11 कार्य, जोबनेर में 30 कार्य, विराटनगर में 41 कार्य, पावटा प्रागपुरा में 26, किशनगढ़ रेनवाल में 47, बगरू में 21, शाहपुरा में 35, चाकसू में 11, बस्सी में 14 और मनोहरपुर एवं नरायणा में 41 कार्य हैं। नगरपालिका क्षेत्र में 20 किमी, नगरपरिषद क्षेत्र में 35 किमी और नगर निगम क्षेत्र में 50 किमी के कार्य पीडब्ल्यूडी द्वारा करवाए जा रहे हैं।

500 आबादी के 851 गांवों को सड़कों से जोड़ा

वर्ष 2011 की जनगणनानुसार 500 से अधिक आबादी के कुल 851 गांवों को सड़कों से जोड़ा जा चुका है। शेष रहे गांवों को जोड़ने का काम भी निरंतर चल रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग ने राज्य के निर्माण कार्यों को समयबद्ध पूरा करने के साथ उनकी बेहतर गुणवत्ता से निर्माण भी सुनिश्चित किया है।

सड़क दुर्घटना नियंत्रण के लिए 1423 ब्लैक स्पॉट्स ठीक किए

राज्य सरकार सड़कों, चौराहों व मोड़ों के अधिक दुर्घटना क्षेत्रों का निरीक्षण कर उनकी संरचना को दुर्घटना रहित बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। सड़क सुरक्षा की दृष्टि से पूर्व में चिन्हित 384 ब्लैक स्पॉट्स में से 370 व उसके बाद चिन्हित 404 ब्लैक स्पॉट्स में से 391 व 2019 में 325 स्पॉट्स में से 315, इसी तरह 2020 में चिन्हित किए गए 193 ब्लैक स्पॉट्स में से 170 एवं 2021 में चिन्हित किए गए 242 ब्लैक स्पॉट्स में से 177 ब्लैक स्पॉट्स को विभिन्न एजेंसियों-सार्वजनिक निर्माण विभाग,आरएसआरडीसी, रिडकोर द्वारा ठीक करवा दिया गया है। इस प्रकार कुल 1548 में से 1423 ब्लैक स्पॉट्स को दुरूस्त किया जा चुका है।

विभिन्न जिलों में होंगे यह भी कार्य

अजमेर में 51 करोड़ के 108, भीलवाडा में 49 करोड़ के 96, नागौर में 89 करोड़ के 206, टोंक में 40 करोड़ के 108 , भरतपुर में 86 करोड़ के 226 , धौलपुर में 34 करोड़ के 120, करौली में 35 करोड़ के 92 , सवाईमाधोपुर में 32 करोड़ के 241, बीकानेर में 15 करोड़ के 102, हनुमानगढ में 43 करोड़ के 85 , श्रीगंगानगर में 65 करोड़ के 141 , चूरू में 70 करोड़ के 316, जयपुर में 109 करोड़ के 487, अलवर में 119 करोड़ के 441, सीकर में 74 करोड़ के 205 , झुंझुनू में 80 करोड़ के 213 , दौसा में 39 करोड़ के 100, जोधपुर में 67 करोड़ के 171 , पाली में 62 करोड़ के 102, सिरोही में 41 करोड़ के 132, जैसलमेर में 16 करोड़ के 54 , बाड़मेर में 23 करोड़ के 74 , कोटा में 64 करोड़ के 63, बूंदी में 40 करोड़ के 69 , बारां में 35 करोड़ के 111, झालावाड़ में 28 करोड़ के 38 , उदयपुर में 12 करोड़ के 23 , चितौडगढ में 35 करोड़ के 126, राजसमंद में 28 करोड़ के 114 , बांसवाड़ा में 22 करोड़ के 50 , डूंगरपुर में 5 करोड़ के 10, प्रतापगढ में 19 करोड़ के 28 काम।

डूंगरपुर-बांसवाड़ा जिलों की आबादी को पुल से जोड़ा

बांसवाड़ा- डूंगरपुर सीमा पर बोरेश्वर मंदिर के पास माही नदी पर टू लेन उच्च स्तरीय पुल व दोनों और ऐप्रोच सड़क का निर्माण 58 करोड़ की लागत से अक्टूबर 2020 में कार्य पूर्ण हो चुका है। इससे डूंगरपुर में निठाउवा क्षेत्र के 8 जनजाति बाहुल्य ग्राम पंचायतों के पचास हजार, बांसवाड़ा जिले के घाटोल पंचायत समिति के जनजाति बाहुल्य करीब अस्सी हजार लोगों को सीधा आवागमन मिला। लोगों को पहले 50 किमी घूम कर आना-जाना पड़ता था। दूरी अब 10-15 किमी रह गई है। इससे घाटोल क्षेत्र के वाहन सीधे उदयपुर जा सकते हैं।

13 हजार करोड़ के 42 प्रोजेक्ट पूरे होने की ओर 13 लाख ग्रामीण परिवारों को मिलेगा जल

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई बजट घोषणाओं में शामिल जलदाय विभाग की करीब 13 हजार 328 करोड़ रुपए की परियोजनाएं मार्च 2024 तक पूरी हो जाएंगी। इन परियोजनाओं से प्रदेश के 19 जिलों के करीब 13 लाख ग्रामीण परिवार लाभांवित होंगे। अभी प्रगतिरत बड़ी परियोजनाओं में से कुछ वर्ष के अंत तक पूरी हो जाएंगी। मार्च 2024 तक विभाग का 13 हजार 328 करोड़ रुपए की 42 विभिन्न पेयजल परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य है।

कौनसी योजना कब पूरी हो रही

- 698.72 करोड़ रुपए की नोखा-बीकानेर पेयजल परियोजना इस वर्ष मार्च तक पूरी होगी। यहां पंचायत समिति के 137 गांव तथा कोलायत क्षेत्र के 9 गांवों की जनता लाभांवित होगी।
- 331 करोड़ रुपए की जोधपुर जिले की देवनिया-नाथरू पेयजल परियोजना तथा 489 करोड़ रुपए की बीकानेर जिले की खाजूवाला जलप्रदाय योजना के कार्य मार्च 2024 तक पूरे होंगे।
- 443 करोड़ रुपए की बेर हरलाया भाग प्रथम एवं द्वितीय का कार्य भी इस अवधि में पूरा हो जाएगा। 205 करोड़ रुपए की झालावाड़ जिले की राजगढ़-झालरापाटन जल प्रदाय परियोजना का कार्य अक्टूबर 2023 तक पूरा होगा।
- 173 करोड़ रुपए की चूरू जिले की बूंगी-राजगढ़ पेयजल परियोजना का कार्य अगस्त 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा।
- 254 करोड़ रुपए की बाड़मेर लिफ्ट परियोजना पार्ट-ए, बाड़मेर बायतू-बालोतरा, पार्ट डी भणियाणा, सांकड़ा, सम, फतेहगढ़, मोहनगढ़, जैसलमेर, परियोजना तथा 231 करोड़ रुपए की इंदिरा गांधी नहर परियोजना से एकीकृत तारानगर, झुंझुनूं, सीकर, खेतड़ी वृहद पेयजल परियोजना इस वर्ष के अंत तक पूरी होगी।
- 175 करोड़ रुपए की अजमेर जिले की ब्यावर-जवाजा पेयजल परियोजना, 133.48 करोड़ रुपए

की राजसमंद जिले की बाघेरी का नाका क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना तथा 159 करोड़ रुपए की नागौर जिले की जायल मातासुख पेयजल परियोजना भी इसी वर्ष पूरी हो जाएंगी।
- 198.80 करोड़ रुपए की चूरू जिले की आपणी योजना द्वितीय चरण, रतनगढ़-सुजानगढ़ सेक्शन अप्रैल 2023 में तथा 104 करोड़ 49 लाख रुपए की डूंगरपुर जिले की सोम कमला आम्बा बांध से आसपुर की पेयजल परियोजना के कार्य भी सितम्बर 2023 तक हो जाएंगे।
- 927 करोड़ रुपए की नर्मदा ईआर आधारित क्लस्टर जल प्रदाय परियोजना, जसवंतपुरा-रानीवाड़ा, सांचोर सरनाऊ, चितलवाना, बागौड़ा, भीनमाल,जालौर, सायला मार्च 2024 तक पूरी किए जाने का लक्ष्य है। 151 करोड़ रुपए की छापी, झालावाड़, झालरापाटन, पेयजल परियोजना का कार्य सितम्बर 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
- 130 करोड़ की बांसवाड़ा जिले के सुरवानिया बांध से बागीदौरा, बांसवाड़ा और तलवाड़ा ब्लॉक की पेयजल परियोजना का कार्य जून 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य है। 169 करोड़ 51 लाख रुपए की कोटा जिले की रामगंजमंडी, पचपहाड़ पेयजल परियोजना का कार्य सितम्बर 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा।
- 1274.26 करोड़ की इंदिरा गांधी नहर पर एस्केप रिजर्वायर निर्माण की परियोजना के तहत इंदिरा गांधी नहर विभाग द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के डिपोजिट कार्य के रूप में 4 एस्केप रिजर्वायर का निर्माण कार्य चल रहा है और इसे मार्च 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

स्मार्ट वॉटर सप्लाई मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए अवॉर्ड

जयपुर। नई दिल्ली में तीसरे डिजिटेक कॉन्क्लेव-2022 में राजस्थान को आईओटी आधारित स्मार्ट वॉटर सप्लाई मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए अवार्ड प्रदान किया गया। जलदाय मंत्री डॉ. महेश जोशी ने यह अवार्ड ग्रहण किया था।

पायलट प्रोजेक्ट के तहत चयनित जयपुर जिले के 15 गांवों में नलों के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए आईओटी (इंटरनेट ऑफ थिंग्स) आधारित स्मार्ट वॉटर सप्लाई मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए गए हैं। इस सिस्टम में पेयजल आपूर्ति की लाइन की शुरुआत, पाइप लाइन के ब्रांच नोड एवं टेल नोड पर सेंसर्स लगाए गए हैं। इन सेंसर्स को इंटरनेट से जोड़ा गया है। इंटरनेट के माध्यम से सेंसर्स द्वारा एकत्र डेटा से यह भी जानकारी मिलती है कि टंकी का पानी शुद्ध है एवं उसमें किसी तरह की अशुद्धि नहीं है। साथ ही टेल एंड के उपभोक्ता को जो पानी मिल रहा है उसका प्रेशर कितना है, फ्लो कैसा है, पीएच वैल्यू, टीडीएस, क्लोरीन एवं फ्लोराइड कितनी मात्रा में है इसका डेटा भी सेंसर्स से प्राप्त होता है।

जलदाय विभाग की उपलब्धियां एक नजर में

- 71,038 करोड़ की स्वीकृति जारी, 11,167 एकल जलप्रदाय परियोजनाएं एवं 134 वृह्द परियोजनाएं शामिल हैं। योजनाओं से लगभग 95 लाख परिवारों को घरेलू जल संबंधों द्वारा पेयजल आपूर्ति की जा सकेगी।
- वृहद पेयजल परियोजनाओं के माध्यम से सतही जल स्त्रोत से वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पेयजल परियोजनाओं पर समग्र व्यय 21386.56 करोड़ रुपए कर 28 वृहद पेयजल परियोजनाएं पूर्ण की गईं एवं 19 शहरों, 5148 ग्राम एवं 4115 ढ़ाणियों को पेयजल से लाभान्वित किया गया है।
- शहरी क्षेत्र में दिसम्बर 2018 से मई 2023 तक 4,210 नए कार्य 5,156 करोड़ के स्वीकृत किए गए हैं। शहरी क्षेत्र की पेयजल योजनाओं पर 2554 करोड़ व्यय हुए।
- गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए 1207 आरओ प्लांट लगाकर चालू किए गए हैं।
- फ्लोराइड प्रभावित गांव/ढाणियों में 1991 सौर उर्जा आधारित डी-फ्लोरिडेशन यूनिट स्थापित किए गए।
- 12,183 नये नलकूप, 22,880 नए हैण्डपम्प लगाकर चालू किए गए।
- 10.85 लाख खराब पाए गए हैण्डपम्पों को सुधार कर पुनः चालू किया।
- अगस्त 2016 में चिन्हित शेष 6,849 फ्लोराइड प्रभावित गांव/ढाणियों में से 6,849 गांव/ढाणियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा दिया गया है। दिसम्बर 2018 के बाद 4,158 गांव/ढाणियों को लाभान्वित किया गया।

स्मार्ट मीटर लग रहे, बकाया बिल एक साथ नहीं वसूलेंगे

15 हजार लीटर जल उपभोग पर शुल्क में पूरी छूट

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा के तहत जलदाय विभाग ने प्रथम चरण में प्रदेश के तीन शहरों जयपुर, जोधपुर एवं कोटा में कुल 30 हजार खराब वॉटर मीटर बदलकर स्मार्ट वॉटर मीटर लगाए जाएंगे। इसमें जयपुर शहर के 15 हजार खराब मीटर बदलना भी शामिल है। इसके लिए 25 करोड़ रुपए का अनुमोदन किया गया है। जयपुर शहर के शेष करीब 1 लाख 35 हजार खराब मीटर भी क्रमबद्ध तरीके से बदले जाएंगे। पहले जयपुर शहर के करीब 71 हजार 300 वॉटर मीटर क्रमबद्ध तरीके से बदले जा चुके हैं। इसके अलावा जयपुर शहर के उपभोक्ताओं को दो माह से अधिक के पानी के बकाया बिल एक साथ नहीं भेजकर निश्चित समय अंतराल पर भेजे जा रहे हैं ताकि किसी भी उपभोक्ता पर एक साथ आर्थिक भार नहीं आए। प्रदेश में चालू मीटर वाले घरेलू उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 15 हजार लीटर तक जल उपभोग पर जल शुल्क में शत-प्रतिशत छूट दी गई है।

पाली में नवाचार, खाली पड़ी खदानों का पानी उपयोग में लिया

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशों के बाद जलदाय विभाग ने बंद पड़ी खदानों में खुदाई के बाद गहरे गड्ढों में भरे पानी को जलदायिनी बना दिया। पाली के लिए तो यह संजीवनी बना। गर्मियों में पाली में पहली बार जलापूर्ति के वैकल्पिक स्त्रोत के रूप में जाडन के पास स्थित तीन खदानों में एकत्र पानी करीब 6 किलोमीटर लम्बी पाइप लाइन डालकर उपयोग में लिया गया। इन माइंस से करीब 80 लाख लीटर पानी पाली शहर को तथा 20 लाख लीटर सोजत को मिला। बाकली बांध के नीचे स्थित कुओं से पानी एकत्र कर जैतपुर क्षेत्र में जलापूर्ति की गई।

33 लाख से अधिक घरों में पहुंचाया पेयजल

प्रदेश में अब तक 45 लाख से अधिक घरों में जल कनेक्शन हुए

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने आम अवाम को पेयजल उपलब्ध कराने पर गंभीरता दिखाई। दिसम्बर 2019 से लेकर अब तक 33.25 लाख घरों को जल कनेक्शन देकर पीने का शुद्ध जल पहुंचाया है। वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को घर तक जलापूर्ति की जाएगी। 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के आधार पर पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। अब राजस्थान में 45 लाख से अधिक घरों तक जलापूर्ति हो गई है। सीएम गहलोत खुद कई बार जलापूर्ति को लेकर समीक्षा बैठकें कर चुके हैं।

प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थितियों एवं छितराई बसावट के कारण जल कनेक्शन देना बड़ी चुनौती है बावजूद इसके प्रदेश में 90 प्रतिशत जल संबंधों की स्वीकृतियां हो गई है। 50 प्रतिशत जल संबंधों के लिए कार्यादेश भी जारी हो चुके हैं।

राजस्थान यूं आगे

1. कुल 43 हजार 364 गांवों में से 43,251 गांवों में ग्राम जल स्वच्छता समितियों का गठन किया जा चुका है। करीब 13 हजार समितियों का बैंक खाता खोला जा चुका है। इन समितियों के गठन में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। अभी तक 43 हजार 208 ग्राम कार्य योजनाएं (विलेज एक्शन प्लान) बनाई जा चुकी हैं जो कि देश में सर्वाधिक हैं।

2. वित्तीय वर्ष 2023-24 में अभी तक जारी 5.81 लाख जल सम्बन्धों एवं प्रतिदिन किये जाने वाले जल कनेक्शनों की संख्या के आधार पर राजस्थान चौथे स्थान पर है। 17,854 करोड़ रुपए व्यय कर खर्च के मामले में राजस्थान दूसरे स्थान पर है। चालू वित्तीय वर्ष में अभी तक 3158 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं।

3. जनवरी से मार्च 2023 की तिमाही में जल कनेक्शन देने का काम पूर्ण रफ्तार में है। तीन महीनों में 7 लाख 35 हजार जल कनेक्शन दिए गए। मार्च माह में ही 3.74 लाख ग्रामीण क्षेत्र में कनेक्शन दिए हैं। 31 मार्च 2023 को एक दिन में ही रिकार्ड 27,470 कनेक्शन दिए गए। इस समयावधि में राजस्थान देश में जल कनेक्शन देने में तीसरे स्थान पर रहा है।

बजट 2023-24 में ये बड़ी सौगातें

- प्रदेश के 3,133 अतिरिक्त गांवों को सतही जल स्रोतों से जल उपलब्धता के लिए 11,255 करोड़ की 3 वृहद् पेयजल परियोजनाओं की घोषणा की। इनमें 5,776 करोड़ की चम्बल-अलवर-भरतपुर पेयजल परियोजना, 4,657 करोड़ की चम्बल-सवाईमाधोपुर-नादौती परियोजना और 822 करोड़ रुपए की चम्बल नदी आधारित कालीतीर परियोजना शामिल।
- विभिन्न शहरों में पेयजल के लिए 980 करोड़ की योजनाओं की घोषणा की गई। इनमें सोम कमला आम्बा बांध से उदयपुर शहर के लिए जल प्रदाय योजना पर 676.73 करोड़, भादरा शहरी जल प्रदाय योजना के लिए 95.64 करोड़, जयपुर की गैटोर शहरी जल प्रदाय योजना के लिए 37.16 करोड़ रुपए, जयपुर जगतपुरा शहरी जल प्रदाय योजना के लिए 44.30 करोड़ रुपए तथा जयपुर में बाईजी को कोठी मॉडल टाउन जल प्रदाय योजना के लिए 46.37 करोड़ रुपए, मण्डावर शहरी जल प्रदाय योजना, दौसा के लिए 21.41 करोड़, रूपावतों का बेरा, जोधपुर में उच्च जलाशय एवं वितरण प्रणाली के लिए 5.96 करोड़, पीपाड़ सिटी शहरी जल प्रदाय योजना, जोधपुर के लिए 5.57 करोड़ एवं सांचौर शहरी जल प्रदाय योजना, जालोर के लिए 47.96 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उदयपुर शहर को अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए देवास तृतीय एवं चुतर्थ बांधों के निर्माण के लिए 1,691 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया।

महिला सशक्तीकरण के लिए पिंक डिवीजन में बदले ऑफिस

महिला सशक्तीकरण की दिशा में अनूठी पहल करते हुए पीएचईडी के संभाग स्थित एक-एक कार्यालय को पिंक डिवीजन में परिवर्तित किया जा रहा है। इन विशेष डिवीजन में सभी अभियंता यथा अधिशाषी अभियंता, सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता एवं अन्य पदों पर महिलाओं को लगाया जा रहा है। जयपुर में नगर खण्ड तृतीय दक्षिण, मालवीय नगर को प्रदेश का पहला पिंक डिवीजन बनाया गया है। जहां समस्त स्टाफ महिलाएं हैं।

2025 तक 5,123 करोड़ खर्च कर शहर के हर घर में शुद्ध जल पहुंचेगा

जयपुर। वर्ष 2025 तक प्रत्येक शहरी परिवार को जल कनेक्शन देकर स्वच्छ जल उपलब्ध कराने एवं शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार को प्रदेश के 183 शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्रों के लिए 5,123.06 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। वर्ष 2025-26 तक 7 लाख 71 हजार 141 नए नल कनेक्शन दिए जाएंगे। 21 लाख 37 हजार टेप कनेक्शन सुधारे जाएंगे। योजना में 33 लाख 15 हजार 165 आबादी को लाभांवित करने का प्रस्ताव है।

सरकार का लक्ष्य 2025-26 तक वॉटर सिक्योर सिटीज तैयार करना है। अनकवर्ड एरिया में वॉटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वर्तमान में उपलब्ध जलापूर्ति सिस्टम में और सुधार, चिन्हित क्षेत्रों में चौबीस घंटे जलापूर्ति, शोधित जल को उद्योगों, पेड़-पौधों आदि में री-यूज करना, पीने के पानी के अलावा 20 प्रतिशत पानी की मांग रिसाइकल्ड पानी के माध्यम से पूरी करना, जल स्त्रोतों में वृद्धि, वर्षा जल संरक्षण, नॉन रेवेन्यू पानी में कमी लाना जैसे कार्य हैं।

2.55 लाख घरों में चौबीस घंटे जलापूर्ति

सरकार की 2,55,760 शहरी घरों एवं 35,665 कच्ची बस्तियों में चौबीस घंटे जलापूर्ति का लक्ष्य है। हर शहरी निकाय में कम से कम दो हजार परिवारों को चौबीस घंटे जलापूर्ति का लाभ मिलेगा। योजना के तहत 371.612 एमएलडी सोर्स वॉटर एवं वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता में 214 एमएलडी से अधिक की बढ़ोतरी होगी। 145 एमएलडी पानी रि-यूज किया जाएगा।

बहुमंजिला इमारतों में पेयजल की समस्या होगी हल, जलापूर्ति नीति जारी

जयपुर। राजस्थान में तेज विकास के चलते बड़े शहरों में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में जलापूर्ति के लिए कोई पॉलिसी नहीं थी। जिसके चलते यहां रहने वाले करोड़ों लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा था। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने इनमें जलापूर्ति के लिए पॉलिसी बना दी है। अब यहां रहने वाले लोगों को जल कनेक्शन मिल रहे हैं और उनकी पेयजल समस्या समाप्त होने लगी है। कनेक्शनों की नई पॉलिसी सभी नगरीय क्षेत्रों में समान रूप से लागू है। सीएम अशोक गहलोत ने वर्ष 2023-24 के बजट में शहरी क्षेत्रों में बहुमंजिला भवनों को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की योजनाओं से पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराने के संबंध में घोषणा की थी। पॉलिसी बनाने से पहले मल्टी स्टोरी एवं निजी टाउनशिप डवलपर्स के साथ ही रेजीडेन्ट वेलफेयर सोसायटी के प्रतिनिधियों से सुझाव भी लिए गए ताकि नीति उनके अनुरूप बने। पूर्व में 2016 एवं 2020 में जारी किए गए परिपत्र सिर्फ जयपुर शहर की बहुमंजिला इमारतों को पेयजल कनेक्शन देने को ध्यान में रखकर ही जारी की गई थी।

पॉलिसी में यूं मिलेगा जल कनेक्शन

विकास समिति या सोसायटी आवेदन करेंगे। अनुमोदित मानचित्र भी देना होगा। भवन में मौजूद समस्त इकाइयों की श्रेणी जैसे वाणज्यिक, आवासीय तथा कारपेट एरिया इत्यादि बताने होंगे। जिनके भवन की ऊंचाई 15 मीटर से अधिक हो। बहुमंजिला भवनों में घरेलू पेयजल मांग की गणना 1500 वर्ग फीट कारपेट एरिया तक के फ्लैट में 5 व्यक्ति प्रति फ्लैट तथा 1500 वर्ग फीट से अधिक कारपेट एरिया के फ्लैट में 7 व्यक्ति प्रति फ्लैट के अनुसार की जाएगी। एकमुश्त शुल्क कुल कारपेट एरिया के आधार पर होगा। सप्लाई इत्यादि के लिए खर्च की राशि एकमुश्त देनी होगी। न्यूनतम 25 प्रतिशत राकि कनेक्शन के समय जमा कराई जाएगी। शेष 75 प्रतिशत जल उपभोग बिल के साथ, 60 समान किश्तों में 9 प्रतिशत प्रति वर्ष साधारण ब्याज के साथ देय होगी। सारी राशि एक साथ देने पर 5 प्रतिशत की छूट देय होगी। कनेक्शन पृथक- पृथक एकल बल्क पेयजल सम्बन्ध भूतल पर जारी किया होगा, इसके अतिरिक्त किसी भी ईकाई फ्लैट के मालिक को अलग से पेयजल कनेक्शन नहीं देंगे।

आवासीय में केवल 25 रुपए प्रति वर्ग फीट लगेगा शुल्क

आवासीय बहुमंजिला भवन के कुल कारपेट एरिया पर 25 रुपए प्रति वर्ग फीट, वाणिज्यिक में कुल कारपेट एरिया पर 42 रुपए प्रति वर्ग फीट, मिश्रित बहुमंजिला भवन में आवासीय क्षेत्र के कुल कारपेट एरिया पर 25 रुपए प्रति वर्ग फीट तथा वाणिज्यिक क्षेत्र के कुल कारपेट एरिया पर 42 रुपए प्रति वर्ग फीट। संस्थागत अथवा औद्योगिक बहुमंजिला भवनों में सप्लाई के बुनियादी ढांचे की वास्तविक लागत की पूर्ण राशि देय होगी। बहुमंजिला भवन में पेयजल कनेक्शन के लिए एकमुश्त शुल्क राशि में छूट भी तय की गई है।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा प्रसारित

सौ यूनिट तक बिजली बिल शून्य, 200 यूनिट तक खर्च तो स्थायी शुल्क, विद्युत कर सहित अन्य शुल्क भी माफ

सरकार ने बिजली बिल में जनता को दी बड़ी राहत एक करोड़ से ज्यादा परिवारों के लिए मुफ्त बिजली

घरेलू उपभोक्ताओं को बिल में छूट से 7000 करोड़ राज्य सरकार कर रही वहन

जयपुर। राज्य सरकार ने बिजली बिलों में 100 यूनिट तक निःशुल्क कर प्रदेश की जनता को बड़ी और ऐतिहासिक राहत दी है। सरकार ने 200 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को पहले 100 यूनिट बिजली फ्री के साथ 200 यूनिट तक के स्थायी शुल्क, फ्यूल सरचार्ज एवं तमाम अन्य शुल्क भी माफ कर दिए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संवेदनशीलता दिखाते हुए बिजली के बिलों से राहत का सिलसिला पिछले वर्ष के बजट में घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के 50 यूनिट प्रतिमाह उपभोग पर बिजली बिल शून्य कर शुरू किया था। प्रतिमाह 150 यूनिट तक उपभोग पर 3 रुपए प्रति यूनिट तथा 151 से 300 यूनिट पर 2 रुपए प्रति यूनिट अनुदान दिया जाता था। वर्ष 2023-24 के बजट में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना लेकर आए। जिसमें सरकार का लक्ष्य आर्थिक रूप से कमजोर ऐसे घरेलू उपभोक्ताओं को निशुल्क बिजली उपलब्ध कराना था। क्योंकि इस वर्ग का प्रतिमाह विद्युत उपभोग अधिकांशतः 100 यूनिट तक रहता है।

उपभोग 200 यूनिट प्रतिमाह रहने पर 100 यूनिट के साथ-साथ स्थाई शुल्क, विद्युत कर, ईंधन अधिभार भी खत्म कर दिया गया। इससे एक करोड़ से अधिक परिवारों को निःशुल्क बिजली मिलेगी। वहीं 11.95 लाख परिवारों जिनके बिल 200 यूनिट तक आते हैं, सौ यूनिट तक बिजली फ्री होने से उपभोक्ता को वर्तमान में न्यूनतम 562.50 रुपए प्रतिमाह का अनुदान लाभ मिल रहा है। निःशुल्क बिजली योजना का लाभ लेने के लिए मंहगाई राहत शिविर में पंजीकरण करवाया जा रहा है। जुलाई 2023 तक लगभग 94.63 लाख घरेलू उपभोक्ताओं ने पंजीकरण करवाकर अपने बिजली बिल में राहत ली है। आमजन को बिजली बिल से राहत देने के लिए सरकार निःशुल्क बिजली योजना के लिए प्रतिवर्ष लगभग रु. 7000 करोड़ का वित्तीय भार वहन करेगी।

राजस्थान में कहां कितने घरेलू उपभोक्ताओं को राहत मिली

1. 1 से 100 यूनिट फ्रीः 1 करोड़ 4 लाख 58 हजार 241 परिवार लाभान्वित

जयपुर डिस्कॉम 32,86,318
अजमेर डिस्कॉम 39,09,672
जोधपुर डिस्कॉम 32,62,251

2. 101 से 200 यूनिट पर शुल्क माफः 11 लाख 95 हजार 393 परिवारों को लाभ

जयपुर डिस्कॉम 4,47,952
अजमेर डिस्कॉम 4,24,129
जोधपुर डिस्कॉम 3,23,312

घरेलू उपभोक्ता एवं किसानों को 24 हजार करोड़ नहीं चुकाने पड़ेंगे

1 मई 2023 से यानी बिलिंग माह जून 2023 से यह राहत शुरू हुई। घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों को कृषि कनेक्शन पर निःशुल्क बिजली योजना से लगभग 1 करोड़ 40 लाख घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं को 24 हजार करोड़ रुपए प्रति वर्ष नहीं चुकाने पड़ेंगे। यह वित्तीय भार सरकार खुद वहन कर रही है।

प्रतिमाह दो हजार यूनिट बिजली निःशुल्क, 11 लाख किसानों के बिल शून्य

विगत वर्ष के बजट में प्रदेश के किसानों के विद्युत बिल भार को कम करने के लिए मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरूआत की गई थी। जिसके अन्तर्गत सामान्य श्रेणी ग्रामीण ब्लॉक आवर सप्लाई के किसानों को प्रतिमाह 1000 रुपए तक का अतिरिक्त अनुदान दिया जा रहा था। इस वर्ष 2023-24 में घोषित मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना के अन्तर्गत 2000 यूनिट बिजली प्रतिमाह तक उपभोग करने वाले इन सामान्य श्रेणी ग्रामीण ब्लॉक आवर सप्लाई के एवं फ्लेट श्रेणी के 15 एचपी विद्युत भार वाले कृषि उपभोक्ताओं का बिजली का बिल शून्य राशि का हो गया। इस तरह न केवल विद्युत खर्च अपितु स्थायी शुल्क, विद्युत कर, फ्यूल सरचार्ज आदि का वित्तीय भार भी राज्य सरकार वहन कर रही है। इससे 11 लाख किसानों का बिजली बिल शून्य होगा। 2000 यूनिट प्रतिमाह से अधिक बिजली उपभोग करने वाले सामान्य श्रेणी - ग्रामीण ब्लॉक आवर सप्लाई कृषि उपभोक्ताओं को मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत वर्तमान में दिया जा रहा 1000 रुपए प्रतिमाह का अनुदान पूर्व की भांति प्राप्त होता रहेगा। इससे शेष बचे लगभग 5 लाख कृषि उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। निःशुल्क बिजली योजना का लाभ लेने के लिए मंहगाई राहत शिविर में पंजीकरण करवा कर जुलाई 2023 तक लगभग 11.44 लाख से अधिक (75.4 प्रतिशत) कृषि उपभोक्ताओं ने इसका फायदा उठा भी लिया है। लगभग 17000 करोड़ रुपए का वित्तीय भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

बिजली के स्मार्ट मीटर लगे, बिलों में त्रुटियों की शिकायतें समाप्त हुई

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में सरकार ने आम उपभोक्ताओं के घरों में जहां स्मार्ट मीटर लगवाए वहीं उनके बिलों में होने वाली त्रुटियों की शिकायतों को भी समाप्त करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करवाया। उपभोक्ताओं की सतर्कता जांच संबंधी शिकायतों को दृष्टिगत रखते हुए सतर्कता मोबाइल एप लॉन्च किया गया। वहीं शहरी क्षेत्रों में 7.22 लाख उपभोक्ता परिसरों पर स्मार्ट मीटर स्थापित करने की योजना के तहत 5.35 लाख स्मार्ट मीटर स्थापित किए जा चुके हैं, जिससे स्वचालित पठन होने से मानवीय हस्तक्षेप समाप्त हो गया है और विद्युत बिलों में त्रुटियां होने की शिकायतें समाप्त हो गई है। प्रदेश में बिजली वितरण तंत्र के रख-रखाव और मेंटनेंस के लिए शट-डाउन लेने से आम उपभोक्ताओं को अचानक बिजली आपूर्ति रुकने से काम ठप ना हों, परेशानी ना हो, इसके लिए उपभोक्ताओं को एक दिन पहले ही शट डाउन होने पर एस.एम.एस द्वारा सूचित करने का सिस्टम विकसित कर शुरू किया गया।

कृषि के कटे कनेक्शनों को पुनः जुड़वाने की अवधि बढ़ाई

बिजली के जो कृषि कनेक्शन कटे हुए पड़े थे, उन्हें पुनः जीवित करने यानी शुरू करने की अवधि 15 वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष की गई। इससे किसान वर्ग को बड़ी राहत मिली और कटे कनेक्शनों को जुड़वाने में आसानी हुई।

22 लाख उपभोक्ता होंगे लाभान्वित

जयपुर। कृषि श्रेणी के नियमित अथवा कटे हुए तथा गैर कृषि श्रेणी के अन्तर्गत कटे हुए विद्युत कनेक्शनों हेतु 31 दिसम्बर 2022 तक देय विलम्ब राशि व ब्याज में चरणबद्ध छूट की अवधि को 30 सितम्बर 2023 तक बढ़ाया गया है। इससे 22 लाख से अधिक उपभोक्ता लाभान्वित होंगे।

किसानों को ये भी अनुदान और फायदे

जयपुर। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत प्रतिमाह 1000 रुपए तक व प्रतिवर्ष अधिकतम 12000 रुपए तक का अनुदान कृषि उपभोक्ताओं को वर्तमान में दिए जाने वाले अनुदान के अतिरिक्त देय हो रहा है। बिलिंग मई 2021 से जून 2023 तक लगभग 13.50 लाख किसानों को 2409.69 करोड़ रूपए का अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया गया है। साथ ही, लगभग 8.79 लाख किसानों के शून्य राशि के बिल जारी किए गए।

साथ ही किसान के हितों को ध्यान में रखते हुए विद्युत कनेक्शन आवेदनों की 31 दिसम्बर 2012 से चली आ रही 9 वर्ष से अधिक की पेंडेंसी लगभग 4 लाख 88 हजार विद्युत कनेक्शन आवेदन खत्म करने की दृष्टि से 22 फरवरी 2022 तक के समस्त बकाया विद्युत कनेक्शन दो वर्षों में जारी किए जाएंगे। वर्ष 2022-23 में 99,137 कनेक्शन जारी तथा वर्ष 2023-24 में जून 2023 तक 39,058 कृषि कनेक्शन जारी हो चुके हैं।

बिजली में एमनेस्टी स्कीम उपभोक्ताओं को छूट मामले भी निस्तारित

जयपुर। सरकार ने बिजली संबंधित मामलों, पैनल्टी, पुराने भुगतान चुकाने में ब्याज सहित अन्य जुर्माना राशि में छूट देने के लिए कई एमनेस्टी स्कीमों को भी क्रियान्वित किया है ताकि मामलों को निपटाया जा सके और आमजन को राहत भी दी जा सके। ऊर्जा संबंधी एमेनेस्टी योजना 3 अप्रैल 23 को जारी की गई थी। यह योजना 30 सितम्बर 2023 तक प्रभावी रहेंगी।

स्कीम से ये फायदा ले सकेंगे उपभोक्ता

- ऊर्जा संबंधी एमनेस्टी-सतर्कता जांच प्रतिवेदनों (वीसीआर) के प्रकरणों में 31 दिसम्बर 2022 या उससे पूर्व के लम्बित प्रकरणों में छूट दी जानी प्रस्तावित है।
- 31 दिसम्बर 2022 या उससे पूर्व के लम्बित सतर्कता जांच प्रतिवेदनों के निस्तारण हेतु 1 लाख रुपए तक की सिविल लायबिलिटी राशि होने पर इस राशि का 40 प्रतिशत एवं प्रशमन (कम्पाउंडिंग) राशि का 25 प्रतिशत लेकर अंतिम निस्तारण किया जा रहा है।
- यदि सिविल लायबिलिटी राशि 1 लाख रुपए से अधिक है, तो 1 लाख रुपए तक की राशि का 40 प्रतिशत एवं 1 लाख रुपए से अधिक राशि का 10 प्रतिशत एवं प्रशमन (कम्पाउंडिंग) राशि का 25 प्रतिशत लेकर अंतिम निस्तारण किया जा रहा है।
- यह राशि 6 मासिक किश्तों में बिना ब्याज के जमा कराई जा सकेगी। इस योजना के अन्तर्गत 30 सितम्बर 2023 तक आवेदन किए जा सकेंगे।
- वर्तमान में प्रचलित राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट 1962 असामयिक हो चुका है, अतः इसे रिपील कर नया अधिनियम लाया जाना प्रस्तावित है।

किसानों के कल्याण का फैसला

चार लाख कृषि कनेक्शन दिए एग्रीमेंट स्टाम्प ड्यूटी मुक्त किया

पांच साल नहीं बढ़ाई बिजली दरें, दो ब्लॉक में बिजली आपूर्ति को 18 जिलों में विद्युत तंत्र स्थापित

जयपुर। सीएम अशोक गहलोत ने किसानों की बिजली की समस्या पर संवेदनशीलता दिखाते हुए दिसम्बर 2018 से जून 2023 तक 4.03 लाख कृषि कनेक्शन जारी कर उन्हें इससे निजात दिलाई है। साथ ही कृषि विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए विद्युत वितरण निगम एवं उपभोक्ताओं के मध्य होने वाले करार को स्टाम्प ड्यूटी से मुक्त किया गया है। किसानों को कृषि के लिए दिन के दो ब्लॉक में विद्युत आपूर्ति हेतु 18 जिलों में विद्युत तंत्र स्थापित किए गए। बिजली की उपलब्धता अनुसार दिन के दो ब्लॉक में विद्युत आपूर्ति की जा रही है, जिला जालौर के 90 प्रतिशत क्षेत्रों में दिन के 2 ब्लॉक के लिए विद्युत् तंत्र स्थापित किए गए हैं। शेष 14 जिलों में कृषि के लिए दिन के दो ब्लॉक में विद्युत आपूर्ति के लिए माह जुलाई 2024 तक विद्युत तंत्र स्थापित किया जाना तय किया गया है।

ये भी दिखाई संवेदनशीलता

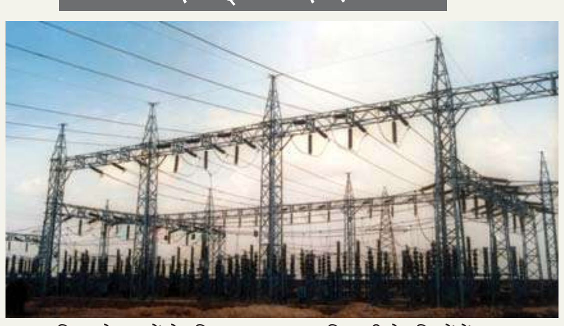

- कृषि कनेक्शनों के लिए अलग से फीडर स्थापित करने के लिए प्रथम चरणमें 1,534 फीडरों का कार्यपूर्ण।
- 5 सालों तक कृषि विद्युत कनेक्शन पर बिजली की दर नहीं बढ़ाने का निर्णय।
- दिसम्बर 2018 से मई 2023 तक किसानों को बिजली के बिलोंमें 71 हजार 53 करोड़ रूपए काअनुदान दिया गया।
- अनुसूचित जाति के 56,642 कृषकों को कृषि कनेक्शन जारी किए गए।
- अनुसूचित जनजाति के 37086 कृषकों को कृषि कनेक्शन जारी किए गए।

उचित मूल्य पर बिजली खरीद में भी मदद मिलेगी

बिजली आईटी कंपनी बनाने की तैयारी

उपभोक्ताओं की समस्याएं निपटेंगी, उत्पादन-मांग का पूर्वानुमान होगा

जयपुर। प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं के निवारण और पांचों बिजली कंपनियों के आईटी संबंधित कामों के लिए राज्य सरकार ने विद्युत आईटी कंपनी बनाने की तैयारी में है। उपभोक्ताओं की सेवाओं को इसी कंपनी के मार्फत ऑनलाइन इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा। वहीं यह कंपनी आईटी तकनीक के माध्यम से बिजली उत्पादन और मांग के सटीक पूर्वानुमान भी निकालकर बिजली कंपनियों को देगी ताकि बिजली संकट का पहले से पता लग सके। इसके लिए एडवांसड डाटा एनालिटिक्स आधारित इंटीग्रेटेड रियल टाइम डाटा एंड कमांड सेंटर स्थापित किया जाएगा। इसी के माध्यम से एनर्जी एक्सचेंज से आवश्यकतानुसार उचित मूल्य पर बिजली भी खरीदी जा सकेगी।

दो लाख परिवारों को एक हजार करोड़ खर्च कर सरकार देगी कनेक्शन

जयपुर। प्रदेश में 31 मार्च 2019 के बाद लगभग 2 लाख परिवार घरेलू विद्युत कनेक्शन से वंचित थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार इनको कनेक्शन जारी करने का कार्य कर रही है। इसमें लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। अतः अब 2 सालों में इन सभी वंचित 2 लाख परिवारों को लगभग एक हजार करोड़ रुपए की लागत से घरेलू कनेक्शन उपलब्ध करवाने का सरकार ने फैसला किया है।

■ 14 हजार मेगावाट के सौर ऊर्जा ■ 894 मेगावाट के पवन ऊर्जा ■ 8 मेगावाट बायोमास संयंत्र लगे

बिजली उत्पादन में रिकॉर्ड बढ़त : 3575 मेगावाट बिजली ज्यादा बनने लगी, बिजली में आत्मनिर्भर राजस्थान

■ गांवों में 17.50 लाख, शहरों में 5.90 लाख घरेलू और 2.14 लाख बीपीएल के घर हुए जगमग

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में दिसम्बर 2018 से अब तक राजस्थान में बिजली उत्पादन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। अब तक 3 हजार 575 मेगावॉट बिजली उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। वहीं बिजली का प्रदेश में कुल उत्पादन क्षमता 23,658 मेगावॉट हो गई है। ऐसे में राजस्थान बिजली उत्पादन में जहां आत्मनिर्भर बना है, वहीं गांव-ढाणियों में भी निर्बाध बिजली की पूरी सप्लाई शुरू हुई है। वहीं प्रदेश सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा के उत्पादन में भी तेजी से आगे बढ़ा है।

जयपुर। राज्य सरकार बिजली उत्पादन में प्रतिबद्ध रही है। दिसम्बर 2018 से अब तक 14 हजार एक मेगावॉट के सोलर रुफटॉप सहित सौर ऊर्जा संयंत्र, 894 मेगावॉट पवन ऊर्जा संयंत्र, 8 मेगावॉट के बायोमास संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। आरपीओ के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु 4,885 मेगावॉट क्षमता की सौर ऊर्जा व 1,426 मेगावॉट क्षमता की पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए 4,285 मेगावॉट क्षमता के निविदा के माध्यम से विकासकर्ताओं का चयन किया गया। जिसमें से 1,110 मेगावॉट की सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो गए। 1,200 मेगावॉट पवन ऊर्जा क्षमता के लिए 78.30 मेगावॉट के पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित हुए।

-75 हजार 30 मेगावॉट क्षमता के अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के कस्टमाइज्ड पैकेज जारी हुए। ग्रामीण क्षेत्र में 17.19 लाख एवं शहरी क्षेत्र में 5.74 लाख घरेलू कनेक्शन जारी किए गए। वहीं 2.14 लाख बी.पी.एल वर्ग के परिवारों को कनेक्शन दिए गए।

बिजली तंत्र हुआ मजबूत

- छबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर रस्टेशन की 660 मेगावॉट की छठी इकाई (दिनांक 02.04.2019) एवं सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल परियोजना की 660 मेगावॉट की इकाई-7 (दिनांक 01.12.2020), 660 मेगावॉट की इकाई-8 (दिनांक 07.10.2021) से वाणिज्यिक विद्युत उत्पादन शुरू हुआ।
- कुसुम कम्पोनेंट-ए के अंतर्गत 93 मेगावॉट के 71 संयंत्र स्थापित।
- कुसुम कम्पोनेंट-सी के अंतर्गत 1375 पंप सेट सौर ऊर्जीकृत हुए।
- दिसम्बर 2018 से 883 मेगावॉट सोलर रूफ टॉप स्थापित किए गए हैं।
- दिसम्बर, 2018 से मई 2023 तक 400 केवी का एक ग्रिड सब-स्टेशन, 220 केवी का 5 ग्रिडसब-स्टेशन, 132 केवी के 32 ग्रिड सब-स्टेशन एवं 33 केवी के 653 सब-स्टेशन स्थापित हुए।
- 400 केवी से 2,220 केवी के 11,132 केवी के 34 जीएसएस एवं 33/11 केवी के 150 सब स्टेशन स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है।
- 765 केवी ग्रिड सबस्टेशन जोधपुर में स्थापित किए जाने हेतु 3,089 करोड़ रूपए की योजना स्वीकृत की गई।

तकनीक, नवाचार व परियोजनाओं से सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी देने में जुटी राजस्थान सरकार

सिंचाई व्यवस्था मजबूत करने के लिए ₹12 हजार करोड़ से अधिक राशि खर्च, हर खेत तक पानी पहुंचाने में जुटी सरकार

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान सरकार प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसानों को अधिकतम सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध करवाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है।

नहरों के विकास के लिए राज्य सरकार सदा ही प्रतिबद्ध है। किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार बांधों व नहर प्रणाली को विकसित करने में जुटी है। पिछले चार साल में राजस्थान सरकार ने विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं पर करीब 12,163 करोड़ रुपए व्यय कर 40,352 हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई है। इतना ही नहीं, सरकार ने एक कदम आगे बढ़कर सिंचाई के क्षेत्र में तकनीक व नवाचार का भी भरपूर इस्तेमाल किया है। इस क्रम में बीसलपुर, माही, गुढ़ा व जवाई, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर बांधों व गंग, भाखडा, नर्मदा नहरों पर स्काडा सिस्टम स्थापित किया। जबकि पार्वती बांध, छापी बांध व सोम कमला अम्बा बांध पर स्काडा सिस्टम लगाने का कार्य प्रगति पर है। गौरतलब है कि स्काडा सिस्टम वेब आधारित होने की वजह से नहर में प्रवाहित पानी व अन्य आंकड़े किसान और जनता द्वारा इंटरनेट (सेटेलाइट) से किसी भी जगह या स्थान से देखे जा सकते हैं। यही नहीं, किसान अपने मोबाइल पर भी नहर में आने वाले पानी की जानकारी ले सकेगा।

इन परियोजनाओं पर हैं राजस्थान सरकार का फोकस

[1] ईआरसीपी

पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) से प्रदेश के 13 जिलों झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर व धौलपुर की वर्ष 2051 तक की पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी। इन 13 जिलों में प्रदेश की 40% जनसंख्या है। फीडर कैनाल से पूर्व में निर्मित क्षेत्र की 26 वृहद व मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को पानी दिया जाना प्रस्तावित है। करीब 2 लाख हैक्टेयर नए क्षेत्र में माइक्रो इरिगेशन सिस्टम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। उद्योगों को भी पानी मिलेगा।

परियोजना को जल्द पूरा करने के लिए 17 जून 2022 को ईआरसीपी कॉर्पोरेशन गठित हुआ। ईआरसीपी के दो महत्वपूर्ण घटकों- नवनेरा बैराज व ईसरदा बांध का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

[2] नर्मदा नहर परियोजना

परियोजना में 1793 किलोमीटर लंबाई में वितरिकाओं व उप-वितरिकाओं का कार्य पूर्ण। 2.46 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

परियोजना में 2231 डिग्गियों का निर्माण कर 1215 डिग्गियों पर पंपिंग यूनिट स्थापित की गई हैं।

[3] परवन परियोजना

परियोजना से कोटा, बारां व झालावाड़ जिलों के 1821 गांवों में पेयजल व 637 गांवों के 2.01 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।

वर्तमान में 490 मिलियन घन मीटर क्षमता का एक बांध बनाया जा रहा है।

[4] धौलपुर लिफ्ट परियोजना

चंबल नदी से पानी लिफ्ट कर धौलपुर, मनिया, राजाखेड़ा व सैंपऊ तहसीलों में सिंचाई हेतु उपलब्ध करवाना प्रस्तावित।

धौलपुर जिले के 256 गांवों के 39 हजार 980 हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र में स्प्रिंकलर पद्धति से सिंचाई होगी।

[5] ल्हासी, गागरिन, राजगढ़, तकली, गरड़दा व हथियादेह परियोजनाएं

इन सभी मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से 42,798 हैक्टेयर भूमि सिंचित होगी। इन परियोजनाओं पर पिछले चार साल में 674.82 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं।

नवनेरा बैराज का कार्य प्रगति पर है। राजस्थान सरकार इस परियोजना पर अभी तक 902.22 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है।

खेत का पानी खेत और गांव का पानी गांव में रोकना जरूरी

राजस्थान में अभी जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा नहीं है, वहां बरसात के पानी पर निर्भर रहना पड़ता है। खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में रोकना जरूरी है। सरकार इस योजना पर काम कर रही है। इससे किसानों को सिंचाई के लिए पानी की कमी नहीं रहेगी।

-अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री, राजस्थान

वर्षों बाद हुई सरहिंद फीडर और राजस्थान फीडर की री-लाइनिंग

पंजाब स्थित सरहिंद फीडर व राजस्थान फीडर के री-लाइनिंग के विगत कई वर्षों से लंबित कार्य वर्ष 2019 में शुरू हुए। राजस्थान सरकार के प्रयासों से पंजाब में सरहिंद फीडर के लगभग 85 किमी लंबे री-रिलाइनिंग कार्य हुए हैं। जबकि राज्य सरकार ने राजस्थान फीडर के 62 किमी लंबे रिलाइनिंग कार्य किए हैं। इस साल की नहरबंदी में राजस्थान फीडर में 19 किमी लंबाई में री-रिलाइनिंग कार्य पूरे हुए। इसके अलावा रेगिस्तानी क्षेत्र में राजस्थान जल क्षेत्र पुनः संरचना परियोजना के अंतर्गत इंदिरा गांधी फीडर व मुख्य नहर की 176.91 किमी की रिलाइनिंग व 1372.59 किलोमीटर में वितरिकाओं के नवीनीकरण/आधुनिकीकरण का कार्य पूरा किया जा चुका है।

बांध पुनरूद्धार व सुधार परियोजना

सिंचाई का पानी बढ़ाने के लिए हो रहा बांधों का आधुनिकीकरण

परियोजना का उद्देश्य बड़े बांधों का जीर्णोद्धार व जल रिसाव रोकना

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान सरकार बांधों के आधुनिकीकरण पर तेजी से कार्य कर रही है। बांध पुनरुद्धार व सुधार परियोजना के माध्यम से राज्य के बड़े बांधों का जीर्णोद्धार किया जाएगा और जल रिसाव रोका जाएगा। इससे जलभराव क्षमता बढ़ेगी और किसानों को सिंचाई के लिए अधिक जल उपलब्ध होगा। आधुनिक उपकरणों के माध्यम से बांधों का आधुनिकीकरण किया जाएगा, जिससे वर्षा कालीन व बाढ़ बचाव संबंधी आंकड़े तत्काल उपलब्ध होंगे।

परियोजना के दूसरे व तीसरे चरण के अंतर्गत कुल 189 बांधों को लिया गया है। वर्ष 2020-21 की बजट घोषणा में 18 व 2021-22 में 18 बांधों का जीर्णोद्धार करने की घोषणा की गई थी। 35 बांधों की पीएसटीएस भेजी जा चुकी है। इसकी अनुमानित लागत 660.92 करोड़ रुपए है। प्रदेश के 12 बांधों के जीर्णोद्धार के लिए 404.14 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी हो चुकी है। जबकि 21 बांधों के जीर्णोद्धार के लिए 246.47 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। अन्य स्तर पर 3 बांधों के जीर्णोद्धार के लिए 39.53 करोड़ रुपए की स्वीकृति की प्रक्रिया चल रही है। बांध पुनरुद्धार व सुधार परियोजना पर वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 209.24 करोड़ रुपए का प्रावधान स्वीकृत है। जून, 2023 तक 6.77 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं।

परियोजना के दूसरे व तीसरे चरण में प्रदेश के 189 बांध शामिल

बांध पुररुद्धार एवं सुधार परियोजना के दूसरे व तीसरे चरण के अंतर्गत कुल 189 बांधों को लिया गया है। वर्ष 2020-21 की बजट घोषणा में 18 व 2021-22 में 18 बांधो के जीर्णोद्धार करने की घोषणा की गई थी।

सिंचाई सुविधाओं का विस्तार कर रही राज्य सरकार

अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना से 42 हजार हैक्टेयर में होगी सिंचाई

बांसवाड़ा जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र व 6 तहसीलों के 338 गांवों तक पहुंचेगा सिंचाई का पानी, किसानों को होगा फायदा

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान सरकार सिंचाई परियोजनाओं पर योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। सरकार का पूरा फोकस इस बात पर है कि समय पर काम पूरा हो, जिससे किसानों को सिंचाई की सुविधा का जल्द से जल्द लाभ मिले। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2022-23 के बजट में अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना की घोषणा की थी। इस परियोजना की कुल लागत 2,500 करोड़ रुपए है। इसमें कमांड क्षेत्र से बाहर और ऊंचाई पर स्थित बांसवाड़ा जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र बांसवाड़ा, बागीदौरा व कुशलगढ़ और 6 तहसीलों- बांसवाड़ा बागीदौरा, गांगडतलाई, आनंदपुरी, कुशलगढ़ व सज्जनगढ़ के कुल 338 गांवों के 42 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

साथ ही नहर की क्षमता में विद्युत उत्पादन का भी प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा 105 किमी लंबी मुख्य नहर के एलाइनमेंट में आ रहे तालाबों में पेयजल आपूर्ति संभव होगी। परियोजना से प्रत्येक 1.25-1.5 हैक्टेयर क्षेत्र में नक्का निर्मित कर फव्वारा पद्धति द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। परियोजना के लिए 2248.94 करोड़ रुपए का बजट इस साल 12 मई को जारी कर दिया गया है। परियोजना की प्रारंभ व समाप्ति तिथि क्रमशः 22 मई 2023 व 21 नवंबर 2026 नियत है। फिलहाल सर्वे का कार्य चल रहा है।

इन परियोजनाओं पर तेजी से हो रहा काम

1 पीपलखूंट हाई लेवल कैनाल परियोजना

माही बांध से ईएल 259 मीटर के स्तर से पीपलखूंट हाई लेवल कैनाल निकालना प्रस्तावित है। परियोजना की प्रशासनिक वित्तीय व तकनीकी स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं और वर्तमान में निविदा कार्य प्रक्रियाधीन है। परियोजना का निर्माण पारंपरिक नहर पद्धति के स्थान पर संपूर्ण लोहे के पाइप में प्रस्तावित की गई है। जिसमें मुख्य नहर भी लोहे के पाइप में निर्मित कर डिग्गियों में जल डालकर पंप व पाइपों से कमांड क्षेत्र के प्रत्येक 1.25-1.5 हैक्टेयर क्षेत्र में नक्का बनाकर फव्वारा पद्धति से सिंचाई जल दिया जाएगा। इससे सिंचाई जल का कुशलतम उपयोग होगा।

2 अनास नदी पर गराडिया एनिकट निर्माण कार्य

परियोजना का कार्यादेश इसी साल 15 मई को जारी हुआ और 26 मई से कार्य प्रारंभ हुआ। एनिकट में संग्रहित जल को सौर ऊर्जा आधारित सूक्ष्म सिंचाई पद्धति से सिंचाई व पेयजल के काम लिया जाएगा।

3 सालगांव बांध

सिरोही के सालगांव में 155.56 मिलियन घन फुट भराव क्षमता का बांध सालगांव व गंभीरी नाला के संगम पर निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। पिछले साल के बजट में इसकी घोषणा हुई थी। इसके लिए इसी साल 16 मई को 111.11 करोड़ रुपए का कार्यादेश जारी कर दिया गया है।

₹1070 करोड़ की लागत से हो रहा 65 सिंचाई उप परियोजनाओं का जीर्णोद्धार

राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना के तहत पहले चरण में राज्य के 21 जिलों की 65 सिंचाई उप परियोजनाओं के जीर्णोद्धार हेतु 1069.40 करोड़ रुपए की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी है। इससे 2.62 लाख हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र लाभान्वित होगा। इन सिंचाई उपपरियोजनाओं में से 38 सिंचाई उपरियोजनाओं में कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। यानी लगभग 1.49 लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल अभी तक कवर किया जा चुका है। शेष 27 सिंचाई उप परियोजनाओं के कार्य प्रगति पर हैं। परियोजना के अंतर्गत पानी की बचत और बाजार उन्मुख फसल उत्पादन के लिए स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई प्रणाली को बढ़ावा दिया जा रहा है।

मरू क्षेत्र हेतु जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना का 55% काम हुआ पूरा

प्रदेश के रेगिस्तानी इलाकों में सिंचाई की सुचारू व्यवस्था बनाने पर हो रहा काम

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान सरकार प्रदेश के रेगिस्तानी क्षेत्र में सिंचाई की सुविधाओं को सुचारू बनाने के लिए नए सिरे से काम कर रही है। इसके लिए मरू क्षेत्र हेतु जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण के नहरी तंत्र के जीर्णोद्धार के लिए न्यू डवलपमेन्ट बैंक द्वारा इस परियोजना को वित्त पोषित किया गया है। इसका लाभ श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर, झुंझुनूं, सीकर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों को मिलेगा। बता दें कि यह परियोजना 2018 में प्रारंभ हुई। जिसमें अब तक 281 कार्य पूर्ण हो चुके हैं और वर्तमान में 120 कार्य प्रगति पर हैं। इंदिरा गांधी फीडर, इंदिरा गांधी मुख्य नहर व इसके नहरी तंत्र की कुल 2678.22 किमी लंबाई में री-लाइनिंग का कार्य प्रस्तावित है, जिसके विरुद्ध अब तक 1549.50 किमी री-लाइनिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है।

परियोजना की कुल अनुमानित लागत 3291.63 करोड़ रुपए है। इसमें से जून, 2023 तक 1806.77 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। परियोजना 55% पूर्ण हो चुकी है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में इस परियोजना के लिए 784.89 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया। इसमें से जून, 2023 तक 156.88 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। परियोजना पूर्ण होने की तिथि 12 फरवरी 2025 है।

समय पर पूरा हो रहा है री-लाइनिंग का काम

- इंदिरा गांधी फीडर (पंजाब भाग) में कुल 97 किमी लंबाई में री-लाइनिंग कार्य करवाए जाने हैं। इनमें से अब तक 81.70 किमी लंबाई में री-लाइनिंग कार्य करवाए जा चुके हैं। इन कार्यों पर जून, 2023 तक 1052.25 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं।
- राजस्थान सरकार की ओर से इंदिरा गांधी फीडर (पंजाब भाग) में कुल 97 किमी लंबाई में री-लाइनिंग कार्य के लिए अपनी हिस्सा राशि के विरूद्ध 659.15 करोड़ रुपए पंजाब को हस्तांतरित किए जा चुके हैं।
- सरहिंद फीडर में कुल 100 किमी लंबाई में री-लाइनिंग कार्य करवाए जाने हैं। इनमें से अब तक 84 किमी लंबाई में री-लाइनिंग कार्य करवाए जा चुके हैं। इन कार्यों पर जून 2023 तक 506.15 करोड़ रुपए व्यय हुए हैं। राजस्थान द्वारा इन कार्यों पर अपनी हिस्सा राशि के विरूद्ध 125.83 करोड़ रुपए पंजाब को हस्तांतरित किए जा चुके हैं। पंजाब द्वारा ये कार्य जून, 2024 तक पूर्ण किए जाने प्रस्तावित हैं।

ड्रेनेज सिस्टम, नहरें, ब्रांच केनाल व वितरिकाएं दुरुस्त

चंबल कमांड एरिया में सिंचित क्षेत्र की दक्षता सुधार के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध

राज्य के नहरी क्षेत्र के रखररखाव का काम तेज गति से हो रहा है। चंबल कमांड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कोटा, बूंदी व बारां जिलों के सिंचित क्षेत्र की दक्षता सुधार हेतु ड्रेनेज सिस्टम के जीर्णोद्धार, विभिन्न नहरों, वितरिकाओं व ब्रांच केनालों में पक्की लाइनिंग के कार्य के तहत 367 करोड़ रुपए से लगभग 600 किमी लंबाई में नहरों की लाइनिंग का कार्य किया जा रहा है। 36.78 करोड़ रुपए की लागत से 10,510 हैक्टेयर कमांड क्षेत्र में पक्का खाला निर्माण कार्य प्रगति पर है। ड्रेनेज सिस्टम जीर्णोद्धार के लिए 64.98 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी हुई है। उक्त कार्यों पर माह मई, 2023 तक 53.36 करोड़ रुपए व्यय किए गए व 48.25 किमी लंबाई में नहरों की लाइनिंग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। साथ ही ड्रेनेज कार्यों पर 12.40 करोड़ रुपए व्यय हुए हैं व 391.80 किमी लंबाई में ड्रेनेज सिस्टम का पुनरूद्धार किया जा चुका है।

▪ स्पेशल इनिशिएटिव, जल संसाधन विभाग

साढ़े चार साल में सड़कों के विकास पर 32,384 करोड़ रुपए खर्च, 65 हजार किमी लंबी सड़कों का हुआ विकास

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई में राजस्थान सरकार प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा रही है। उच्च गुणवत्तापूर्ण सड़कों से सफर दुर्घटना रहित, सुरक्षित व सुगम हो रहा है। इससे प्रदेश में निवेशक आकर्षित हो रहे हैं, जिससे विकास को गति मिल रही है। शहर व कस्बों में ही नहीं, गांव और ढाणी तक पहुंच रहे देश-विदेश के पर्यटक राजस्थान की मजबूत सड़कों की सराहना कर रहे हैं।

मजबूत सड़कों से विकास पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा राजस्थान, सुरक्षित व सुगम हुआ आवागमन

सड़कें विकास की मुख्य कड़ी हैं। इसी सोच को ध्यान में रखकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर प्रदेश के सड़क तंत्र को लगातार सुदृढ़ किया जा रहा है। शहरों से लेकर गांव-ढाणी तक सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि प्रदेश का एक भी गांव-ढाणी सड़कों से जुड़ने से वंचित नहीं रहे। राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल में अब तक प्रदेश के 1,164 ऐसे गांवों को सड़कों से जोड़ दिया है, जहां आज तक सड़क नहीं पहुंच सकी थी। इस सिलसिले को और आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 31 जुलाई को 2,422 करोड़ रुपए की लागत से 1,514 राजस्व गांवों को नवीन डामर सड़कों से जोड़ने के कार्यों का शिलान्यास किया। इनमें से 778 राजस्व गांव 2011 की जनगणना के अनुसार सामान्य क्षेत्रों में 350 व अधिक आबादी और जनजातीय व मरुस्थलीय क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी के हैं। इन गांवों में 1,192 करोड़ रुपए की लागत से सड़कें बनेंगी। बाकी 736 गांव जनगणना वर्ष 2011 के पश्चात घोषित सामान्य क्षेत्रों में 500 व अधिक आबादी और जनजातीय व मरुस्थलीय क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी के हैं। इनमें 1,230 करोड़ रुपए की लागत से सड़कें बनेंगी।

31 जिलों की 106 विधानसभा क्षेत्रों के 1,514 गांवों में नवीन सड़कों के निर्माण से गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य व परिवहन सुविधा में सुगमता आएगी। किसानों की आय में वृद्धि होगी। ये सड़कें गांव और ग्रामीणों के लिए जीवनदायिनी साबित होंगी। इन 1,514 गांवों में निर्माण पूरा होने के बाद प्रदेश के 91% गांव सड़क से जुड़ जाएंगे। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा शेष गांवों को भी शीघ्र ही सड़कों से जोड़ा जाएगा। बता दें कि 2023-24 के बजट में 16,123 करोड़ रुपए की लागत से 23 हजार किमी सड़कों का निर्माण और सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि किसी भी प्रदेश और गांवों के विकास में सड़कों की अहम भूमिका होती है। सार्वजनिक निर्माण और अन्य विभागों ने मिलकर इस दिशा में बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारा है। आज राजस्थान मजबूत सड़क तंत्र में अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। इसमें निर्माणकर्ता ठेकेदारों की भी अहम भूमिका रही है।

मजबूत सड़क तंत्र में राजस्थान अग्रणी राज्य

किसी भी प्रदेश और गांवों के विकास में सड़कों की अहम भूमिका होती है। सार्वजनिक निर्माण और अन्य विभागों ने मिलकर इस दिशा में बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारा है। आज राजस्थान मजबूत सड़क तंत्र में अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। इसमें निर्माणकर्ता ठेकेदारों की भी अहम भूमिका रही है।

–अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री, राजस्थान

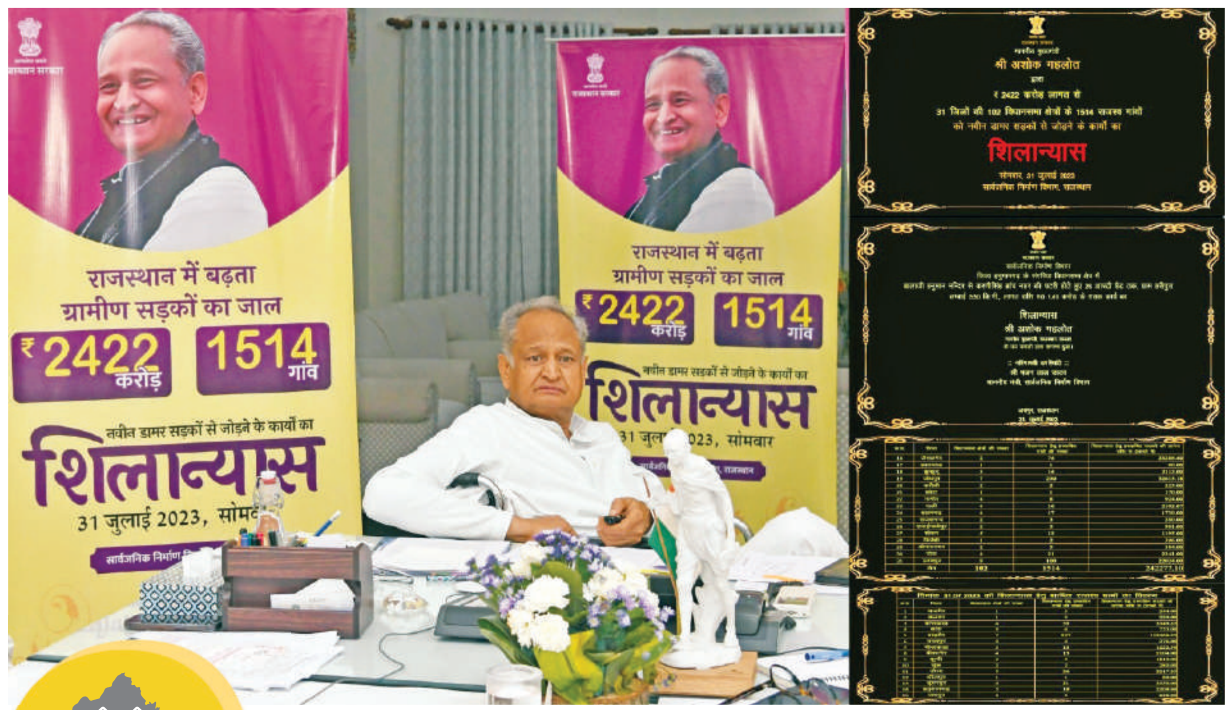

- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2018 में सरकार की कमान संभालने के बाद 1 लाख किमी से अधिक सड़कों का विकास कराने का लक्ष्य रखा था।
- 31 जुलाई को 1,514 राजस्व गांवों को नवीन डामर सड़कों से जोड़ने के कार्यों का शिलान्यास करते हुए मुख्यमंत्री ने इस लक्ष्य को दोहराया। उन्होंने कहा कि अभी तक 65 हजार किमी में सड़कों का विकास हो चुका है। नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका में भी सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से सड़कें बनाई जा रही हैं। आगे भी नवीन सड़क निर्माण, सुदृढ़ीकरण व चौड़ाईकरण के कार्य कराए जाएंगे।
- तय समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण सड़क निर्माण होने से आमजन को राहत मिली है। वर्तमान सरकार के 4 वर्ष 7 माह के कार्यकाल में सड़क विकास पर 32384.26 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। इस राशि से प्रदेश में 64,946 किमी लंबी सड़कों का निर्माण हुआ है।

प्रदेश सरकार ने ऐसे बिछाया सड़कों का जाल

01 नई सड़कों का निर्माण
लंबाई : 12,230 किमी
लागत : ₹6,083.68 करोड़

02 राज्य मार्गों व मुख्य जिला सड़कों का विकास
लंबाई : 9,427 किमी
लागत : ₹10,387.26 करोड़

03 ग्रामीण सड़कों का विकास
लंबाई : 41,930 किमी
लागत : ₹10,882.80 करोड़

04 राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास
लंबाई : 1,359 किमी
लागत : ₹5,030.52 करोड़

05 कुल सड़क निर्माण व विकास कार्य
लंबाई : 64,946 किमी
लागत : ₹32,384.26 करोड़

सड़क विकास पर बढ़ते राजस्थान के कदम

राजस्थान में मजबूत हुआ राज्य राजमार्गों का नेटवर्क

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान सरकार प्रदेश में राज्य राजमार्गों का नेटवर्क मजबूत करने में जुटी है। आवागमन को सुगम व सुरक्षित बनाने के लिए राज्य मार्गों व मुख्य जिला सड़कों सुदृढ़ व नवीनीकृत करना सरकार की प्राथमिकता रहा है। वर्तमान सरकार ने सड़क आधारभूत निधि में पिछले साढ़े चार साल में 1,743 किमी सड़कों का विकास किया है। वहीं, 1607.26 किमी लंबाई के 81 कार्यों हेतु 2045.62 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। हाल ही में इस योजना में 1709.63 किमी राज्य राजमार्गों व जिला सड़कों के 2233.62 करोड़ रुपए की लागत से 74 कार्य स्वीकृत किए गए हैं।

नाबार्ड योजना के अंतर्गत 872 किमी सड़कों का विकास हुआ है। पीपीपी-वीजीएफ, एन्यूटी, ईपीसी के तहत 1,372 किमी लंबी सड़कें बनी हैं। आरएसआरडीसी के माध्यम से 424 किमी लंबाई में कार्य पूर्ण किया गया है। राज्य योजना में 867 किमी लंबाई में चौड़ाईकरण, सुदृढ़ीकरण व नवीनीकरण का कार्य पूर्ण किया गया है। राज्य सड़क निधि में 4,018 किमी लंबी सड़कों का विकास हुआ है। बजट घोषणा 2022-23 के अनुसार 1001 किमी के 53 राज्य राजमार्गों को व 2023-24 के अनुसार 714 किमी लम्बाई के 40 राज्य राजमार्गों को चौड़ा करने के कार्य प्रगतिरत हैं। इन राज्य राजमार्गों को दो लेन किया जा रहा है।

इन राज्य राजमार्गों का काम हुआ पूरा

1. बाड़मेर-सिन्दरी-जालोर
2. आहोर-बाली-मुंदरा
3. पीलीबंगा-लखुवाली
4. सरदारशहर-लूणकरणसर
5. चुरू-भालेरी
6. संजू-तरनेऊ
7. रूपनगढ़-नारायणा
8. अजीतगढ़-चला
10. सीकर-गनेड़ी-जसवन्तगढ़
11. बीदासर-नोखा
12. सिंघाना-बुहाना
13. नागौर-तरनेऊ-डीडवाना-मुकंदगढ़
14. बनाड़-भोपालगढ़-कुचेरा
15. जोधपुर-मारवाड़ जंक्शन-जोजावर
16. जोधपुर-सोजत
17. भीनमाल-पंथेरी-जीवाना

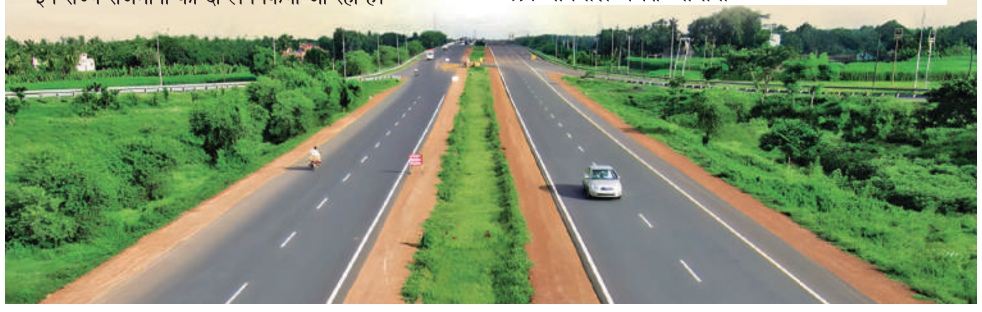

साढ़े चार साल में प्रदेश के 1,164 राजस्व गांवों को सड़कों से जोड़ा

राजस्थान में गांव-ढाणी तक बिछा पक्की और मजबूत सड़कों का जाल

राजस्थान में 89% गांव सड़क से जुड़ चुके हैं। जल्द ही यह आंकड़ा 91% हो जाएगा।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान सरकार प्रदेश में गांव-ढाणी तक सड़क पहुंचाने के लिए मिशन मोड पर जुटी है। वर्तमान सरकार अब तक 1,164 गांवों व 31 ढाणियों को सड़कों से जोड़ चुकी है। इससे राजस्थान के सड़कों की पहुंच वाले गांवों का प्रतिशत 89 हो गया है। 1,514 राजस्व गांवों की नवीन डामर सड़कों के विकास कार्यों का शिलान्यास हो चुका है। इनका निर्माण पूरा होने के बाद ये आंकड़ा 91% हो जाएगा। राज्य सरकार इस दिशा में कितनी तेजी से काम कर रही है, इसका अंदाजा बजट घोषणाओं और उन पर अमल की गति से लगाया जा सकता है।

बजट घोषणा 2019-20 के अनुसार प्रथम चरण में 2011 की जनगणनानुसार 500 व अधिक आबादी के 330 गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए 393 करोड़ रुपए लागत के कार्य सड़क विकास निधि के तहत प्रारंभ किए गए। इनमें से 1064 किमी लंबाई में सड़कों का निर्माण हो चुका है व 324 गांवों को सड़कों से जोड़ दिया गया है। वहीं, अप्रेल 2022 में 367 गांवों को सड़कों से जोड़ने के कार्य स्वीकृत किए गए। इनमें से 303 गांवों को सड़कों से जोड़ दिया गया है।

ऐसे सुगम हुआ गांवों तक पहुंचने का रास्ता

1 मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण

वर्ष 2020-21 तक स्वीकृत कार्यों के अंतर्गत 3,057, 2021-22 के अंतर्गत 2,026, 2022-23 के अंतर्गत 883 किमी मिसिंग लिंक सड़कों का कार्य पूर्ण किया गया। 7 हजार से अधिक मिसिंग लिंक सड़कों का कार्य प्रगति पर है।

2 सुदृढ़ीकरण व नवीनीकरण

ग्रामीण क्षेत्रों में 15,576 किमी लंबी सड़कों के उन्नयन, सुदृढ़ीकरण व नवीनीकरण करने का कार्य पूर्ण किया गया है। नाबार्ड ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 12,879 किमी लंबाई में सड़कों को सुदृढ़ व नवीनीकृत करने का कार्य पूर्ण किया गया है।

नई तकनीक पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित, सड़कों की गुणवत्ता भी सुधरी

राजस्थान में नई तकनीक से बन रही सड़कें, बेकार प्लास्टिक व पुरानी सामग्री के उपयोग से कम हो रही सड़कों की लागत

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान सरकार नागरिक जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सड़कों के विकास के महत्व को समझती है, लेकिन खास बात है कि सड़कों के निर्माण के लिए राजस्थान सरकार पारंपरिक तरीकों के साथ नवीन तकनीकों का भी भरपूर इस्तेमाल कर रही है। इससे कम लागत में उच्च गुणवत्ता वाली सड़कें मिल रही हैं। ये वाहनों के लिए सुरक्षित तो हैं ही, इनसे पर्यावरण भी संरक्षित हो रहा है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग सड़क निर्माण की नई तकनीकों के अलावा इनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भी हमेशा सतर्क व सजग रहता है। विभाग की ओर से तृतीय पार्टी गुण नियंत्रण हेतु 18 आईक्यूम नियुक्त किए गए। इनके माध्यम से 436 कार्यों का निरीक्षण किया गया। इससे प्रदेश में विभाग की ओर से तय मानकों के आधार सड़कों का विकास सुनिश्चित हो रहा है।

प्रदेश में सड़क बनाने में हो रहे ये नए प्रयोग

- **अपशिष्ट प्लास्टिक:** अब तक करीब 15 हजार किमी लंबी सड़कें डामर के साथ अपशिष्ट प्लास्टिक के उपयोग से बनीं। इससे सड़कें टिकाऊ व मजबूत हुईं।
- **सेल फील्ड कंक्रीट:** राज्य में अब तक 330 किमी लंबी सेल फील्ड कंक्रीट सड़क का निर्माण हुआ।
- **हरित सड़क:** ग्रिट, इमल्शन बिना गर्म किए प्लांट में मिलाकर सड़क का निर्माण किया जा रहा है।
- **फुल डैप्थ रिक्लेमेशन:** पुरानी सड़क की सामग्री का उपयोग कर नई सामग्री (ग्रिट) के साथ सड़क का निर्माण। इसमें नवीन सामग्री की कम आवश्यकता, लागत घटी।
- **पीडब्ल्यूडी सेवा एप:** डीएलपी अवधि में सड़कों व भवनों के रखरखाव के लिए इस एप को विकसित किया जा रहा है। इससे इस अवधि के कार्यों के रखरखाव की प्रभावी मॉनिटरिंग होगी। इस पर सड़कों व भवनों की शिकायत भी ऑनलाइन प्राप्त हो सकेगी व उनका शीघ्र निवारण किया जा सकेगा।

और बदल गई गांव की तस्वीर

सड़कों का बेहतर विकास नागरिकों के लिए मजबूत आर्थिक स्थिति का द्वार भी खोलता है। जयपुर जिले के डाबड़ी गांव के सुरज्ञान ने इस सच को अनुभव किया। वे बताते हैं कि उनके पिताजी को दूध बेचने के लिए शहर जाना पड़ता है। लेकिन सड़क ना होने से उन्हें आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। बारिश के दिनों में यह समस्या और विकट हो जाती थी। कई बार शहर जाना संभव नहीं होता था और बिक्री प्रभावित होती थी। मुख्यमंत्री की पहल पर उनके गांव में सड़क का निर्माण हो सका है। गांव में सड़क निर्माण होने से ग्राम वासियों की आवागमन की तकलीफ दूर हुई है।

28 आरयूबी, 18 आरओबी बन रहे...

तेज हुआ आरओबी व आरयूबी के निर्माण का कार्य

प्रदेश सरकार ने लोगों की राह सुगम करने के लिए रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी) व रेलवे अंडर ब्रिज (आरयूबी) के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 39 आरयूबी का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है, जबकि 28 आरयूबी का निर्माण कार्य प्रगति पर है। 14 आरओबी का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है व 18 का निर्माण कार्य प्रगति पर है। प्रदेश में 676 करोड़ रुपए की लागत से 14 आरओबी स्वीकृत किए गए हैं। राज्य सरकार ने 45,304.42 करोड़ रुपए लागत के 19,279 कार्य राजस्थान राज्य सड़क विकास व निर्माण निगम लिमिटेड सहित स्वीकृत किए हैं। इन स्वीकृतियों से 73908.73 किमी लंबाई में सड़कों के विकास कार्य करवाए जा सकेंगे। इनमें 97 आरओबी, आरयूबी व पुल का निर्माण कार्य सम्मिलित हैं।

▪ **स्पेशल इनिशिएटिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग**

हर व्यक्ति तक पीने योग्य शुद्ध पानी पहुंचाने का प्रयास

राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों, वर्षा की मात्रा व निरंतरता में कमी और अत्यधिक भूजल दोहन से कई ब्लॉक्स के डार्क जोन में आने के बावजूद प्रदेश के हर व्यक्ति को पीने योग्य शुद्ध पानी उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार हरसंभव कदम उठा रही है।

–अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री, राजस्थान

6 किमी पाइप लाइन डालकर की जलापूर्ति

बंद पड़ी खदानों में भरा बारिश का पानी बना पाली के लिए संजीवनी

राजस्थान सरकार ने पेयजल आपूर्ति के क्षेत्र में कई नवाचार भी किए हैं। सरकार के प्रयासों से बंद पड़ी पत्थर की खदानों में भरा बारिश का पानी पाली के लिए संजीवनी बन गया। गर्मियों में पाली में पहली बार जलापूर्ति के वैकल्पिक स्रोत के रूप में जाडन के पास स्थित तीन खदानों में एकत्रित पानी करीब 6 किमी लंबी पाइप लाइन डालकर उपयोग में लिया गया। इन माइंस से करीब 80 लाख लीटर पानी पाली शहर को तथा 20 लाख लीटर सोजत को मिला। बाकली बांध के निचले क्षेत्र में स्थित कुओं से पानी एकत्र कर जैतपुर क्षेत्र में जलापूर्ति की गई।

मीटर बदलने के लिए 25 करोड़ रुपए स्वीकृत

पानी के खराब मीटरों की जगह लगेंगे स्मार्ट मीटर

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा के तहत जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा प्रथम चरण में प्रदेश के तीन शहरों में पानी के 30 हजार खराब मीटरों की जगह स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इसमें जयपुर शहर के 15 हजार खराब मीटर बदलना भी शामिल हैं। इसके अलावा 15 हजार खराब मीटर जोधपुर व कोटा में बदले जाएंगे। इसके लिए 25 करोड़ रुपए का अनुमोदन किया गया है। जलदाय मंत्री डॉ. महेश जोशी ने बताया कि विभिन्न योजनाओं में उपभोक्ताओं के खराब मीटर बदले जाएंगे। अशोक गहलोत की बजट घोषणा के अंतर्गत जयपुर शहर के शेष करीब 1 लाख 35 हजार खराब मीटर भी क्रमबद्ध तरीके से बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले जयपुर शहर के करीब 71 हजार 300 पानी के मीटर क्रमबद्ध तरीके से बदले जा चुके हैं। डॉ. महेश जोशी ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के तहत प्रदेश में चालू मीटर वाले घरेलू उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 15 हजार लीटर तक जल उपभोग पर जल शुल्क में शत-प्रतिशत छूट दी गई है।

राजस्थान के सभी नगरीय क्षेत्रों में लागू होगी नीति

प्रदेश के बहुमंजिला भवनों में पेयजल कनेक्शन पॉलिसी की अधिसूचना जारी

राज्य के समस्त नगरीय क्षेत्रों में स्थित बहुमंजिला भवनों में पेयजल कनेक्शन के लिए बनाई गई नीति की अधिसूचना जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2023-24 के बजट में शहरी क्षेत्रों में बहुमंजिला भवनों को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की योजनाओं से पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए घोषणा की थी। बहुमंजिला भवनों में पीएचईडी द्वारा पेयजल कनेक्शन दिए जाने के संबंध में कोई स्पष्ट नीति नहीं होने के कारण इन भवनों के रहवासी लंबे समय से पेयजल कनेक्शन के लिए इंतजार कर रहे थे। बहुमंजिला भवनों को जल कनेक्शन देने की यह नीति पूरे राजस्थान के सभी नगरीय क्षेत्रों में समान रूप से लागू होगी। इससे बहुमंजिला भवनों में रह रहे लोगों तक पेयजल पहुंचाना संभव होगा। बड़ी संख्या में लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे।

पेयजल पहुंचाने की कवायद

ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक पानी पहुंचाने के कार्य पर अभी तक 17,854 करोड़ रुपए खर्च

हर घर तक पीने का पानी पहुंचाने के मिशन में जुटी राजस्थान सरकार

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान सरकार हर घर तक पीने का पानी पहुंचाने में जुटी है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में इस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पिछले 4 साल में 71,038 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। इसमें 11,167 एकल जलप्रदाय परियोजनाएं व 134 वृहद परियोजनाएं शामिल हैं। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 2019 से अब तक 33 लाख 25 हजार नए कनेक्शन दिए हैं। राजस्थान के 45 लाख से अधिक (41%) ग्रामीण घरों को जल कनेक्शन से जोड़ा जा चुका है। राजस्थान जैसे विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्य के लिए यह बड़ी उपलब्धि है। इसे हासिल करने में अभी तक 17,854 करोड़ रुपए व्यय हुए हैं। खर्च के मामले में राजस्थान पूरे देश में दूसरे नंबर पर है। चालू वित्तीय वर्ष में अभी तक 3,158 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। इस साल जनवरी से 31 मार्च तक 7 लाख 34 हजार 715 जल कनेक्शन दिए गए।

वर्तमान सरकार ने 21,386.56 करोड़ रुपए की लागत से 28 वृहद पेयजल परियोजनाओं को पूरा किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जल शुल्क माफ करने का ऐतिहासिक फैसला कर लोगों को बड़ी राहत दी। शहरी क्षेत्रों में चालू मीटर वाले घरेलू जल उपभोक्ताओं को 15 हजार लीटर मासिक उपभोग तक जल शुल्क माफ किया। जबकि गैर मरूस्थलीय इलाके के ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू जल उपभोक्ताओं को 40 एलपीसीडी व मरूस्थलीय क्षेत्र में 70 एलपीसीडी पानी के उपभोग तक जल शुल्क माफ किया। सरकार शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में 26 लाख 31 हजार उपभोक्ताओं का हर साल 177 करोड़ से अधिक जल शुल्क माफ कर उन्हें सीधी राहत दे रही है।

राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य सरकार ने अब तक 33 लाख 25 हजार नए कनेक्शन दिए हैं। प्रदेश के 45 लाख से अधिक (41%) ग्रामीण घरों को जल कनेक्शन से जोड़ा जा चुका है। राजस्थान जैसे विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्य के लिए यह बड़ी उपलब्धि है।

पेयजल के लिए यह प्रयास कर रही सरकार

- राज्य के सभी 228 शहरों व कस्बों को विभिन्न शहरी पेयजल योजनाओं से लाभांवित किया जा रहा है। सभी पाइप्ड पेयजल योजना से जुड़े हुए हैं।
- 120 शहरों को सतही जल स्रोतों से और 62 शहरों को भूजल स्रोतों से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। शेष 46 शहरों की पेयजल योजनाएं सतही व भूजल के मिश्रित जल स्रोतों पर आधारित हैं।
- प्रदेश के 43,362 गांवों में से 43,231 व 78,254 ढाणियों में से 69,353 में विभिन्न पेयजल योजनाओं से लाभान्वित हैं।
- प्रदेश के करीब 24,955 गांव व 52,210 ढाणियां भूजल से जबकि 18,276 गांव व 17,143 ढाणियां सतही जल स्रोतों से लाभान्वित हैं।
- प्रदेश के कई स्थानों पर भूजल में फ्लोराइड व खारेपन की समस्या को देखते हुए शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न तकनीक उपयोग में लाई जा रही हैं। फ्लोराइड की समस्या के समाधान के लिए एक्टिवेटड एल्यूमिना और खारेपन को मिटाने के लिए रिवर्स ओस्मोसिस (आरओ) का प्रयोग किया जा रहा है। इससे लोगों को शुद्ध पेयजल मिल रहा है।

2026 तक पूरा होगा काम, 33 लाख से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा पेयजल

प्रदेश के 183 स्थानीय निकायों में मिलेंगे 7.71 लाख नए नल कनेक्शन

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान सरकार प्रदेश के हर नागरिक को शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध करवाने के लिए मिशन मोड पर काम कर रही है। इसी कड़ी में 2025 तक प्रत्येक शहरी परिवार को नल से स्वच्छ जल उपलब्ध कराने व शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से प्रदेश के 183 शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्रों के लिए 5123.06 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। योजना के अंतर्गत प्रदेश के शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्रों में वर्ष 2025-26 तक 7 लाख 71 हजार 141 नए नल कनेक्शन दिए जाएंगे। इसके अलावा पहले से मौजूद 21 लाख 37 हजार टेप कनेक्शन सुधारे जाएंगे।

कोटा शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्र के अलावा अन्य सभी शहरी स्थानीय निकायों में पेयजल आपूर्ति के कार्य जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की शहरी आबादी 1 करोड़ 31 लाख 75 हजार 685 है। वर्ष 2025 तक की संभावित शहरी जनसंख्या 1 करोड़ 73 लाख 55 हजार 48 होगी। ऐसे में, वर्ष 2025-26 तक 64 लाख 764 शहरी आबादी टेप वाटर से अनकनेक्टेड होगी। इस आबादी तक पेयजल पहुंचाने के लिए सरकार प्राथमिकता के आधार पर काम कर रही है। नई योजना से 33 लाख 15 हजार 165 आबादी को लाभान्वित करना प्रस्तावित है।

हर निकाय में कम से कम 2 हजार परिवारों को 24 घंटे जलापूर्ति

1. योजना के अंतर्गत 2 लाख 55 हजार 760 शहरी घरों व 35 हजार 665 कच्ची बस्तियों में चौबीस घंटे जलापूर्ति का लक्ष्य है। प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय में कम से कम 2 हजार परिवारों को 24 घंटे जलापूर्ति का लाभ मिलेगा।
2. योजना के अंतर्गत 371.612 एमएलडी सोर्स वॉटर में बढ़ोतरी की जाएगी। इसके अलावा वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता में 214 एमएलडी से अधिक की बढ़ोतरी की जाएगी। 145 एमएलडी पानी रि-साइकल अथवा रि-यूज किया जाएगा।
3. वर्ष 2025-26 तक वॉटर सिक्योर सिटीज तैयार करते हुए हर शहरी परिवार तक पर्याप्त व शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य है। अनकवर्ड एरिया में वॉटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जलापूर्ति सिस्टम में सुधार लाना, चिह्नित क्षेत्रों में 24 घंटे जलापूर्ति, जल स्रोतों में वृद्धि, वर्षा जल संरक्षण, नॉन रेवेन्यू पानी में कमी लाना जैसे कार्य होंगे।

पानी की छीजत कम करने में मिलेगी मदद

डेनमार्क से एमओयू, कुशल पेयजल प्रबंधन में कायम हुए नए आयाम

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान सरकार प्रदेश में शुद्ध व स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने और पेयजल के कुशल प्रबंधन के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से खासतौर पर शहरी क्षेत्रों में जल स्रोतों के विकास, पेयजल वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ करने और पेयजल छीजत कम करने की दिशा में जारी कार्यों से पेयजल प्रबंधन के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित हुए हैं। इसी क्रम में राजस्थान सरकार ने इसी साल मई में शहरी जल प्रबंधन के लिए आहूस, डेनमार्क के साथ एक ऐतिहासिक अनुबंध किया है। डेनमार्क व राजस्थान के बीच विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग की पहल मार्च, 2021 में की गई थी।

इस अनुबंध (एमओयू) के बाद राजस्थान और डेनमार्क शहरी पेयजल क्षेत्र में सेवाओं व गुणवत्ता में सुधार, वितरण तंत्र की दक्षता में वृद्धि, गैर-राजस्व जल (छीजत) में कमी, जलस्रोतों का समन्वित प्रबंधन व भूजल एक्विफर मैपिंग, अपशिष्ट जल प्रबंधन की योजना व पुनर्चक्रण, नदियों के कायाकल्प के लिए हरित समाधान आदि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मिलकर कार्य करेंगे। एमओयू के बाद न सिर्फ राजधानी जयपुर, बल्कि जोधपुर और कोटा जैसे बड़े जिलों में भी कुशल जल प्रबंधन किया जा सकेगा। एमओयू के अवसर पर डेनमार्क के राजदूत फ्रेडी स्वान ने उम्मीद जताई कि आगे भी दोनों पक्षों में सकारात्मक भागीदारी जारी रहेगी।

राजस्थान को भविष्य में तकनीकों से लाभ मिलेगा

डेनमार्क में पानी की छीजत शून्य है और वहां पानी का पूरा इस्तेमाल होता है। ऐसे में उनकी लाभकारी तकनीकों को अपनाने से पानी की कमी से जूझते राजस्थान को भविष्य में निश्चित तौर पर बड़ा फायदा मिलेगा।

स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग सिस्टम में प्रदेश शीर्ष पर

हर घर जल पहुंचाने में हो रहा तकनीक का इस्तेमाल, सटीक तरीके से हो रही निगरानी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान सरकार न सिर्फ प्रदेश वासियों के लिए उचित मात्रा में पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है, बल्कि प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए पेयजल के प्रबंधन को लेकर भी पूरी तरह सजग है। इस दिशा में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे अभिनव प्रयासों का ही नतीजा है कि इकोनॉमिक टाइम्स डिजिटेक कॉन्क्लेव-2022 में राजस्थान को आईओटी आधारित स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए अवार्ड प्रदान किया गया। राजस्थान की तरफ से यह अवार्ड जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ. महेश जोशी ने प्राप्त किया। गौरतलब है कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत चयनित जयपुर जिले के 15 गांवों में नलों के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए गए हैं। इस सिस्टम में पेयजल आपूर्ति की लाइन की शुरूआत, पाइप लाइन के ब्रांच नोड व टेल नोड पर सेंसर्स लगाए गए हैं। इन्हें इंटरनेट से जोड़ा गया है। इंटरनेट के माध्यम से सेंसर द्वारा एकत्रित डेटा का आदान-प्रदान व मॉनिटरिंग की जाती है। सेंसर के माध्यम से यह भी जानकारी मिलती है कि टंकी का पानी शुद्ध है और इसमें किसी तरह की अशुद्धि तो नहीं है। पानी के प्रेशर, फ्लो, पीएच वैल्यू, टीडीएस, क्लोरीन व फ्लोराइड कितनी मात्रा में है, इसका डेटा भी सेंसर से प्राप्त होता है।

पिंक डिविजन की पहल: जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने महिला सशक्तीकरण की दिशा में अनूठी पहल करते हुए संभाग स्थित एक-एक कार्यालय को पिंक डिविजन में परिवर्तित कर रहा है। इन विशेष डिवीजन में सभी अभियंता व अन्य पदों पर महिलाओं को लगाया जा रहा है। जयपुर में नगर खंड-तृतीय (दक्षिण) मालवीय नगर को प्रदेश का पहला पिंक डिवीजन बनाया गया, जहां समस्त स्टाफ महिलाएं हैं।

क्या है स्मार्ट वॉटर सप्लाई मॉनिटरिंग सिस्टम

- उपभोक्ताओं को सही मात्रा में व तय गुणवत्ता मानकों के साथ पेयजल आपूर्ति की मॉनिटरिंग के लिए आईओटी आधारित स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया गया है। इससे गांवों में होने वाली पेयजल आपूर्ति की सही मात्रा और पर्याप्त गुणवत्ता मानकों की मॉनिटरिंग की जाती है।
- प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के तहत चयनित किए गए गांवों में आईओटी आधारित सेंसर लगाए गए। इन सेंसर्स को इंटरनेट से जोड़ा गया है, जिनसे एकत्र डेटा का आदान-प्रदान व मॉनिटरिंग की जाती है।
- इन सेंसर्स के माध्यम से यह जांचा जाता है कि टंकी का पानी शुद्ध है या नहीं और उसमें किसी तरह की अशुद्धि नहीं है। साथ ही आखिरी छोर के उपभोक्ता को जो पानी मिल रहा है उसका प्रेशर, फ्लो, पीएच वैल्यू, टीडीएस, क्लोरीन और फ्लोराइड की मात्रा का डेटा भी इन सेंसर्स से प्राप्त होता है। मॉनिटरिंग सिस्टम द्वारा भेजे जाने वाले आंकड़े सीधे डेशबोर्ड पर देखे जा सकते हैं।

▪ स्पेशल इनिशिएटिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

उपभोक्ताओं को बड़ी राहत • 200 यूनिट तक स्थाई शुल्क, फ्यूल सरचार्ज समेत अन्य शुल्क भी माफ

राजस्थान में हर महीने मिल रही 100 यूनिट निशुल्क बिजली, एक करोड़ उपभोक्ताओं का बिल होगा शून्य

प्रदेश सरकार ने हर घर तक बिना किसी बाधा के बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के अलावा आमजन पर बिजली के बिल का बोझ कम करने के लिए ऐतिहासिक व प्रभावी निर्णय लिए हैं।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान सरकार प्रदेश वासियों के लिए 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश सरकार ने आमजन पर बिजली बिल का बोझ कम करने की दिशा में एक के बाद एक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। इनकी शुरुआत 2022 में मुख्यमंत्री घरेलू विद्युत अनुदान योजना से हुई। इस योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिल में 100 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली के उपभोग पर 50 यूनिट बिजली मुफ्त दिए जाने का प्रावधान किया गया। इससे अधिक बिजली का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं के लिए भी स्लैब के अनुसार लाभ दिया गया।

वर्ष 2023-24 के बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इससे एक कदम आगे जाते हुए मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना की घोषणा की। इससे 100 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को निशुल्क बिजली मिलने लगी। इससे प्रदेश के 1.19 करोड़ में से 1.04 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को फायदा हुआ। बाकी 15 लाख उपभोक्ताओं को भी स्लैब के अनुसार 300 से 750 रुपए प्रतिमाह तक की छूट दी गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहत को यहीं तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने इसका दायरा बढ़ाते हुए प्रदेश में 100 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली उपभोग करने वालों का बिजली बिल तो पहले की ही तरह शून्य ही रखा। इसके अतिरिक्त 200 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली उपभोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं के पहले 100 यूनिट निशुल्क बिजली के साथ 200 यूनिट तक के स्थायी शुल्क, फ्यूल सरचार्ज व अन्य सभी शुल्क भी माफ कर दिए। साथ ही समस्त घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट प्रतिमाह से अधिक उपभोग होने पर भी पहले 100 यूनिट बिजली निशुल्क दी जा रही है। इससे एक करोड़ से ज्यादा उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य हो जाएगा। महंगाई राहत कैंपों में अब तक 94,63,838 उपभोक्ता पंजीकरण करवा चुके हैं।

महंगाई राहत कैंपों में अब तक 94,63,838 घरेलू उपभोक्ता मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना के अंतर्गत अपना पंजीकरण करवा चुके हैं।

बिजली बिल शून्य हुआ तो खुशी से झूम उठे मनोज

- राजस्थान के करोड़ों बिजली उपभोक्ता अपना बिजली बिल शून्य आने के बाद हर महीने दिवाली जैसी खुशियां मना पा रहे हैं।
- इन्हीं लाभान्वितों में डूंगरपुर जिले के दोवड़ा गांव निवासी मनोज पाटीदार भी शामिल हैं, जो बिजली बिल में मिल रही छूट देखकर हर बार खुशी से झूम जाते हैं। पाटीदार बताते हैं कि मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना के बाद से ही उनका बिजली बिल शून्य आ रहा है।
- मनोज पाटीदार कहते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा शुरू की गई इस योजना के कारण उनके सिर से आर्थिक बोझ कम हुआ है। इसके लिए वह मुख्यमंत्री के आभारी हैं। मुख्यमंत्री के द्वारा प्रदेश वासियों के लिए ऐसी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनसे न सिर्फ गरीब व मध्यम परिवार के लोगों को आर्थिक मदद मिल रही है, बल्कि उनके जीवन यापन की राह सुगम हुई है।

लोगों को राहत देना है सरकार का लक्ष्य

सरकार का लक्ष्य लोगों को राहत देना है। प्रति माह 100 यूनिट तक बिजली उपभोग निशुल्क है। प्रति माह 200 यूनिट उपभोग पर पहले 100 यूनिट बिजली निशुल्क के साथ 200 यूनिट तक स्थायी शुल्क, फ्यूल सरचार्ज व अन्य शुल्क लगेंगे। सरकार जन सहयोग से बिजली की छीजत में कमी लाने के लिए भी प्रयासरत है।

-अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री, राजस्थान

पवन ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान देश में पहले नंबर पर

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान सरकार द्वारा जारी निवेशोन्मुखी अक्षय ऊर्जा नीतियों के कारण राजस्थान पूरे देश में नाम कमा रहा है। वर्ष 2022-23 में देश में सर्वाधिक पवन ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित कर पवन ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान दूसरे राज्यों से आगे निकल चुका है। वर्ष 2022-23 में प्रदेश में 867 मेगावाट क्षमता की नई पवन ऊर्जा परियोजनाऐं स्थापित की गई, जो कि अन्य राज्यों की अपेक्षा सर्वाधिक है। वर्ष 2022 में प्रदेश में 4337 मेगावाट पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित की गयी थी, जो कि मार्च 2023 तक बढ़कर 5204 मेगावाट हो गई। बता दें कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी राजस्थान देश में अव्वल है।

प्रदेश के 11 लाख किसानों का बिजली बिल हुआ शून्य

मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना से राज्य में अन्नदाताओं को मिल रहा आर्थिक संबल

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई में राज्य सरकार किसानों की खुशहाली और समृद्धि को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखती आई है। किसानों को राहत प्रदान करते हुए राज्य सरकार द्वारा कृषि बिजली की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है और 90 पैसे प्रति यूनिट पर ही बिजली दी जा रही है। प्रदेश के किसानों के विद्युत बिल भार को और कम करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2021 में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की। इस योजना में सामान्य श्रेणी-ग्रामीण ब्लॉक आवर सप्लाई के किसानों को प्रतिमाह 1,000 रुपए तक का अतिरिक्त अनुदान दिया जा रहा है। अब राज्य सरकार ने इस वर्ष उपरोक्त श्रेणी के कृषि उपभोक्ताओं के लिए मुख्यमंत्री निशुल्क कृषि बिजली योजना शुरू की है, जिसमें किसानों को 2,000 यूनिट बिजली प्रतिमाह तक उपभोग पर बिजली निशुल्क है।

राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली 2,000 यूनिट निशुल्क बिजली का लाभ महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद माह मई 2023 से मिलना शुरू हो गया है। इससे करीब 11 लाख किसानों का बिजली बिल शून्य हो गया है। 2,000 यूनिट प्रतिमाह से अधिक बिजली उपभोग करने वाले सामान्य श्रेणी - ग्रामीण ब्लॉक आवर सप्लाई कृषि उपभोक्ताओं को मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत वर्तमान में दिया जा रहा 1,000 रुपए प्रतिमाह का अनुदान प्राप्त हो सकेगा।

विलम्ब राशि और ब्याज में छूट

कृषि श्रेणी के नियमित या कटे हुए और गैर कृषि श्रेणी के अंतर्गत कटे हुए विद्युत कनेक्शनों के लिए देय विलंब राशि व ब्याज में चरणबद्ध छूट की अवधि को 30 सितंबर, 2023 तक बढ़ा दिया है। इससे 22 लाख से अधिक कृषि एवं अन्य उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। कृषि विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने हेतु विद्युत वितरण निगम व उपभोक्ताओं के मध्य होने वाले करार को स्टांप ड्यूटी से मुक्त कर दिया है।

मुख्यमंत्री की पहल से मुकेश को मिल रहा संबल, बिजली का बिल हुआ शून्य

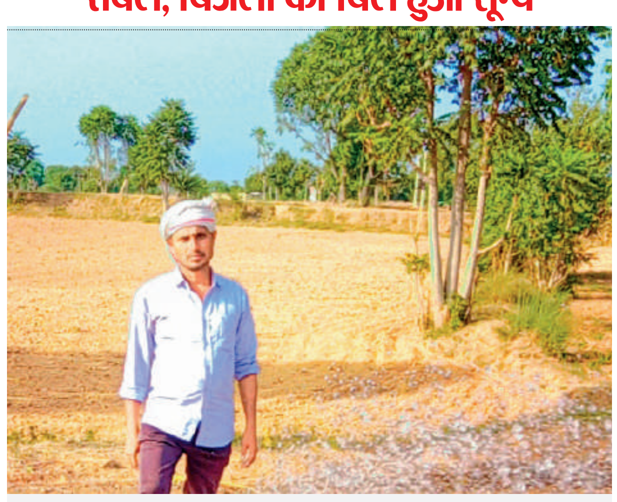

"दौसा जिले के झील गांव के किसान मुकेश मीणा की मां का देहांत उनके बचपन में हो गया था। जब वे 18 वर्ष के हुए तब पिता का भी निधन हो गया। पिता के बाद वे अपने पैतृक व्यवसाय खेती के सहारे जीवन यापन और आगे की पढ़ाई करने लगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त करते हुए मुकेश बताते हैं कि पहले उनका कृषि बिजली बिल लगभग 10 हजार रुपए प्रतिवर्ष आता था, लेकिन योजना के शुरू होने के बाद उनका कृषि बिजली बिल लगभग शून्य आता है। मुख्यमंत्री की इस पहल से उन्हें आर्थिक संबल प्राप्त हुआ है, साथ ही कृषि बिजली बिल से होने वाली बचत का उपयोग आगे की पढ़ाई और खेती को और बेहतर करने में कर रहे हैं।

बिजली कनेक्शन की पेंडेंसी खत्म की

- किसान के हितों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने विद्युत कनेक्शन के लिए 2012 से चली आ रही 4 लाख 88 हजार की पेंडेंसी को खत्म करने के लिए 2024 तक का लक्ष्य तय किया है।
- इस दिशा में आगे बढ़ते हुए राजस्थान सरकार ने दिसंबर, 2018 से जून, 2023 तक 4.03 लाख कृषि कनेक्शन जारी किए।

कृषकों को विद्युत आपूर्ति के लिए 18 जिलों में विद्युत तंत्र स्थापित

- किसानों को कृषि के लिए दिन के दो ब्लॉक में विद्युत आपूर्ति हेतु 18 जिलों में विद्युत तंत्र स्थापित किए गए हैं।
- इनके अलावा 14 जिलों में कृषि के लिए दिन के दो ब्लॉक में विद्युत आपूर्ति हेतु माह जुलाई, 2024 तक विद्युत तंत्र स्थापित किया जाने का लक्ष्य है।
- कृषि कनेक्शनों के लिए अलग से फीडर स्थापित करने के लिए प्रथम चरण में 1,534 फीडरों का कार्य पूर्ण हो चुका है।

अगले 2 साल में 2 लाख ढाणियों तक पहुंचेगी बिजली, एक हजार करोड़ की लागत आएगी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान सरकार आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति तक के जीवन को रोशन करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में ऊर्जा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी ने इसी साल विधानसभा में घोषणा की है कि बिजली से वंचित 2 लाख ढाणियों को आगामी दो वर्ष में विद्युतीकरण से जोड़ा जाएगा। इस योजना में एक हजार करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके अलावा प्रदेश के उन दो लाख परिवारों को भी विद्युत कनेक्शन दिए जाएंगे जो 31 मार्च, 2019 के पश्चात प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर (सौभाग्य) योजना का लाभ उठाने से वंचित रह गए थे। गौरतलब है कि राजस्थान सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने की दिशा में प्राथमिकता के आधार पर काम कर रही है।

राजस्थान सरकार आगामी 2 वर्षों में इन सभी वंचित 2 लाख परिवारों को घरेलू कनेक्शन उपलब्ध कराएगी। एक हजार करोड़ रुपए के खर्च में ये कनेक्शन भी शामिल हैं।

ऊर्जा के क्षेत्र में तकनीक का उपयोग

ऑनलाइन इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम से उपभोक्ताओं को आसानी से मिलेंगी सेवाएं

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान सरकार अन्य क्षेत्रों की तरह ऊर्जा के क्षेत्र में भी तकनीक और नवाचारों का भरपूर इस्तेमाल कर रही है। इसी क्रम में विद्युत उपभोक्ताओं को सुगमता से सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है। इसके अलावा सरकार ने पांचों विद्युत कंपनियों के आईटी संबंधी कार्यों से जुड़ी समस्याओं के निदान के लिए एक विद्युत आईटी कंपनी स्थापित करने की भी घोषणा की है। साथ ही बिजली उत्पादन व मांग के सटीक पूर्वानुमान के लिए एडवांस डेटा एनालिटिक्स आधारित इंटीग्रेटेड रियल टाइम डेटा एंड कमांड सेंटर भी स्थापित किया जाएगा। इसके माध्यम से एनर्जी एक्सचेंज से आवश्यकतानुसार उचित मूल्य पर बिजली खरीदी जा सकेगी।

सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना में मदद कर रहा पोर्टल

सौर कृषि आजीविका योजना से बंजर जमीन पर स्थापित हो रहे संयंत्र, किसानों की आय में हो रही बढ़ोतरी

राजस्थान देश के उन राज्यों में शुमार है, जहां कई किसानों के पास जमीन तो है, लेकिन बंजर होने की वजह से उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा। इन जमीनों से किसानों के लिए आय के स्रोत विकसित करने और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने सौर कृषि आजीविका योजना पोर्टल शुरू किया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भार वाले लोड केंद्रों पर विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों को बढ़ावा देना है। इसके माध्यम से राज्य के किसानों व भूमि मालिकों को अपनी बंजर या अनुपयोगी भूमि को लीज पर देने का अवसर मिल रहा है। ऑनलाइन पोर्टल से किसान अपनी जमीन लीज पर देने के लिए व विकासकर्ता किसानों तक पहुंच सकते हैं।

सालाना लीज राशि 80 हजार से 1.60 लाख रुपए के बीच

- लीज राशि की गणना पंजीकरण के समय जमीन की प्रति हेक्टेयर डीएलसी दर से होती है। 8 लाख तक डीएलसी दर पर 80 हजार, 8 लाख से अधिक व 12 लाख से कम पर 1 लाख, 12 लाख से अधिक व 20 लाख से कम पर 1.40 लाख और 20 लाख से अधिक प्रति हेक्टेयर डीएलसी दर पर सालाना 1.60 लाख रुपए लीज राशि तय है।
- राजस्थान सरकार द्वारा स्वीकृत वार्षिक लीज शुल्क में हर 2 साल में 5% की बढ़ोतरी की जाती है।
- बड़ी संख्या में किसान अपनी बंजर या अनुपयोगी जमीन को लीज पर देकर अपनी आजीविका बढ़ा रहे हैं।

तापीय व पनबिजलीघरों से बिजली उत्पादन की संपूर्ण स्थापित क्षमता हुई 8597.35 मेगावाट

विद्युत उत्पादन में आत्मनिर्भर बना राजस्थान, क्षमता में हुई बढ़ोतरी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान सरकार के प्रयासों से प्रदेश विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन गया है। वर्तमान में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के विभिन्न तापीय व पनबिजलीघरों से बिजली उत्पादन की संपूर्ण स्थापित क्षमता 8597.35 मेगावाट है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 660 मेगावाट क्षमता की छबड़ा सुपरक्रिटिकल इकाई 6 से 2019 में व 660-660 मेगावाट क्षमता की सूरतगढ़ सुपरक्रिटिकल इकाई 7 से 2020 व 8 से 2021 में वाणिज्यिक विद्युत उत्पादन प्रारंभ किया जा चुका है। राज्य सरकार ने बीकानेर के गुढ़ा में 125 मेगावाट की लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति 2022 में जारी कर दी है। बीकानेर में 2000 मेगावाट के सोलर पार्क की स्थापना की जाएगी। छबड़ा में 660-660 मेगावाट व कालीसिंध में 800 मेगावाट की अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल इकाइयों की स्थापना हेतु 2022 में प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी हैं।

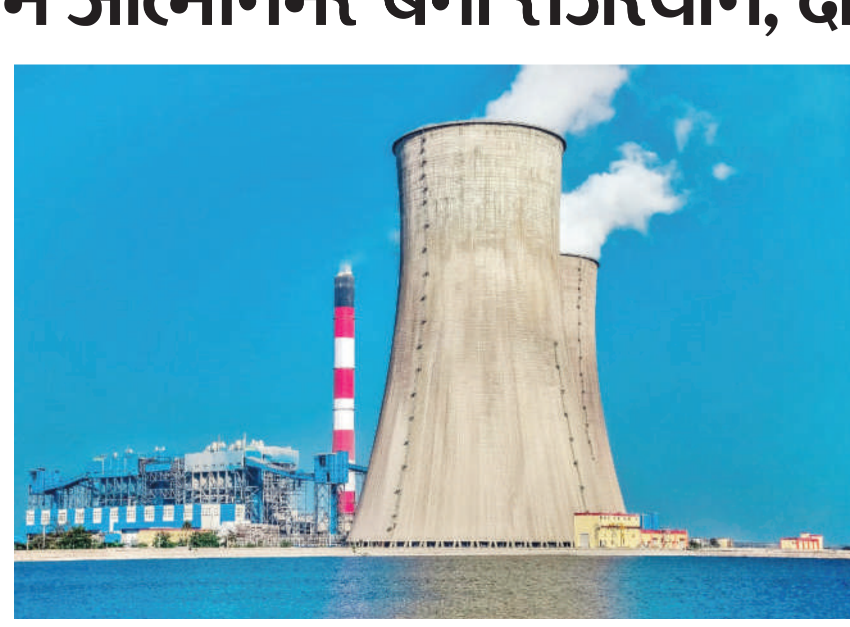

किस इकाई में कितना हो रहा उत्पादन

विद्युत गृह	क्षमता (मेगावाट)
कोटा सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन (इकाई 1 से 7)	1240
सूरतगढ़ सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन (इकाई 1 से 6)	1500
सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल धर्मल पॉवर स्टेशन (इकाई 7 व 8)	1320
छबड़ा थर्मल पॉवर स्टेशन (इकाई 1 से 4)	1000
छबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पॉवर स्टेशन (इकाई 5 व 6)	1320
कालीसिंध थर्मल पॉवर स्टेशन (इकाई 1 व 2)	1200
गिरल लिग्नाइट थर्मल पॉवर स्टेशन (इकाई 1 व 2)	250
रामगढ़ गैस थर्मल पॉवर स्टेशन (इकाई 1 से 4)	273.50
धौलपुर कंबाइंड साइकिल पॉवर स्टेशन (इकाई 1 से 3)	330
माही पन विद्युतगृह 1 व 2	140
लघु पन विद्युत परियोजनाएं (इकाई 10)	23.85
कुल	8597.35

▪ स्पेशल इनिशिएटिव, ऊर्जा विभाग